चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 20 मार्च– 26 मार्च 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम

भाजपा के लिए भी अविश्वसनीय है

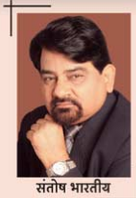

संतोष भारतीय

चुनाव के अप्रत्याशित परिणाम हमारे सामने हैं. ये परिणाम बताते हैं कि जब इच्छाओं का सत्य के साथ मिश्रण होता है, तो वो कितना ख़तरनाक होता है. सिर्फ सत्य सच्चाई के पास ले जाता है. जब इच्छाएं मिल जाती हैं, तो सच्चाई से वो सत्य बहुत दूर पहुंच जाता है. उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने देश को नरेंद्र मोदी नाम का प्रधानमंत्री दिया. न उत्तर प्रदेश से 73 सीटें भाजपा जीतती, न केंद्र में भाजपा की सरकार बनती. उसी तरह जितने भी चुनाव हुए, उनमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसी जीत नहीं मिली, जैसी 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली. इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी ताक़त लगाकर बिहार में चुनाव लड़ा था, लेकिन बिहार का चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल तो नहीं ही आया, बल्कि पिछले चुनाव से कम सीटें उन्हें इस चुनाव में मिलीं. बिहार का चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं को दांव पर लगा दिया था और कहा था कि अगर नीतीश कुमार चुनाव जीतते हैं, तो बिहार में विनाश होगा और अगर मैं जीतता हूं, तो बिहार में विकास होगा. इसके बावजूद, लोगों ने नरेन्द्र मोदी के मुक़ाबले नीतीश कुमार को चुना और उनके द्वारा बनाए हुए गठबंधन की लैंड स्लाइड विक्ट्री हुई.

जिस उत्तर प्रदेश ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, उसी उत्तर प्रदेश ने नरेंद्र मोदी को विधानसभा चुनाव में इतिहास की सबसे बड़ी विजयश्री से अलंकृत किया. इतने बड़े विजयश्री का स्वप्न भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने भी नहीं देखा था. वैसे तो 73 सीटों के बारे में भी कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं सोचा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में कभी इतनी सीटें मिलेंगी, इसकी तो किसी ने कल्पना ही नहीं की थीं. इसके पीछे के कारणों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश के लोगों का अहसानमंद होना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किन वजहों से इतनी बड़ी विजय प्राप्त कर सके, इसके कारणों की पड़ताल से पहले हमें अखिलेश यादव और मायावती की उन कमियों के बारे में सोचना चाहिए, जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया. सबसे पहले अखिलेश यादव की बात करते हैं. अखिलेश यादव ने पिछले तीन साल में उत्तर प्रदेश में एक नई समाजवादी पार्टी बनाने की योजना पर काम किया. उन्होंने एक हज़ार से अधिक ऐसे लोगों को तैयार किया, जो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते थे. अखिलेश यादव ने इन एक हज़ार लोगों को आर्थिक रूप से बहुत मज़बूत कर दिया. उन्हें ठेके मिले, उनकी सिफारिशों के ऊपर काम होने लगा, वे अपने-अपने क्षेत्र के मिनी या छोटा मुख्यमंत्री के नाम से नवाज़े जाने लगे. अखिलेश यादव ने माना था कि इस विधानसभा चुनावों में वे इन्हीं एक हज़ार लोगों में से 400 लोगों को टिकट देंगे और समाजवादी पार्टी के सारे पुराने विधायकों को घर भेज देंगे. लेकिन चुनाव आयोग में मुलायम सिंह यादव के मुक़ाबले अखिलेश यादव को अपना पक्ष मज़बूती से रखना था. इसके लिए उन्हें विधायकों का समर्थन चाहिए था. इस मजबूरी ने उन्हें सारे विधायकों को दोबारा टिकट देने के लिए विवश कर दिया और यहीं से, जिन लोगों को अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया था वे चिंतित हो गये. वे मानते थे कि वे हर हाल में विधानसभा पहुंचेंगे. इनमें से जितने लोग चुनाव में लड़ते, उनमें से कितने जीतते ये तो पता नहीं, लेकिन हर एक के मन में ये सपना पल गया था कि वो विधानसभा जा रहा है. इसलिए अखिलेश यादव ने मौजूदा विधायकों को टिकट देने का फैसला किया. उनके प्रति समर्पित लोगों ने जो पिछले तीन साल से चुनाव लड़ने के लिए अपना मन बना रहे थे, उनमें से अधिकांश ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन भर दिया.

दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश के देहाती क्षेत्र के लोगों को अखिलेश यादव का अपने पिता मुलायम सिंह को धोखा देना पसन्द नहीं आया. गांव-गांव में ये चर्चाएं थीं कि जो अपने पिता का नहीं हुआ, वो हमारा क्या होगा. परिणामस्वरूप, मुलायम सिंह की राजनीति को 30 साल तक देखने वाले उनके समर्थक हाथ पर हाथ रखकर चुप बैठ गए. अखिलेश यादव द्वारा शिवपाल यादव के प्रति किया गया व्यवहार भी ग्रामीण क्षेत्र के यादव समाज के लोगों को पसंद नहीं आया. बल्कि ये कह सकते हैं कि यादव समाज ही नहीं, अब तक मुलायम सिंह के समर्थक रहे यादव और दूसरे पिछड़े समाज जिनमें अति पिछड़े समाज भी शामिल हैं, उनको भी यह कांड न तो पसंद आया और न उन्होंने इसका समर्थन किया. इसलिए जब अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह के फैसले के बाद जिन लोगों ने साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर पर्चा भरा, उनके समर्थन में मुलायम सिंह के ज्यादातर समर्थक निष्क्रिय हो गए या तटस्थ हो गए. वे चुनावों में लगे ही नहीं. यहां तक कि आज़मगढ़ में भी एक भी मुलायम समर्थक अखिलेश यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने नहीं उतरा. अखिलेश यादव ने रामगोपाल यादव को अपना सर्वेसर्वा बना लिया था. इधर पूरे मुस्लिम समाज में ये बात फैल गई थी कि रामगोपाल यादव का अमित शाह के साथ नाता है. इस बात को अपनी सभाओं में पहले शिवपाल यादव ने और उसके बाद खुद मुलायम सिंह यादव ने रिकंफर्म किया कि रामगोपाल यादव ने न केवल उन्हें धोखा दिया है, बल्कि उनका रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ है. मुलायम सिंह यादव का आखिर में यह कहना कि अखिलेश मुसलमान विरोधी हैं, अखिलेश के भविष्य के ऊपर फुलस्टॉप लगा गया. अखिलेश यादव के साथ मीडिया का एक बड़ा तबक़ा था, जिसे

(शेष पृष्ठ 2 पर)

नरेंद्र मोदी ने पिछले तीन सालों में बहुत सारे वादे किए. उन वादों पर कफुए की चाल से अमल भी हुआ. उन्होंने नोटबंदी कर दी, मध्य वर्ग को बहुत नुक़सान हुआ, तकलीफ हुई. इससे मध्य वर्ग और नेताओं ने भी मान लिया कि गरीब को भी इससे परेशानी हुई होगी. इसमें कोई दो राय नहीं कि गरीब को भी परेशानी हुई. लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये माहौल बनाना शुरू किया कि वे अमीरों के खिलाफ हैं, कालेधन वालों के खिलाफ हैं, कालाबाज़ारी करने वालों के खिलाफ हैं, इसीलिए सारी पार्टियां उनका विरोध कर रही हैं.

न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये अंदाजा था कि उन्हें इतनी सीटें आएंगी, न विपक्षी नेताओं को ये अंदाजा था कि उनका इतना बुरा हाल होगा. यहां तक कि पत्रकारों को इस अभूतपूर्व मोदी लहर का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं हुआ और जिन्होंने सीटों का आकलन किया वे सिर्फ रुझान समझ पाए. वे जनता के उस गुस्से को नहीं समझ पाए, जो गुस्सा समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की अकर्मण्यता के कारण या उनके सत्ता में रहने के दौरान मिले घावों से लगा था.

मोदी के नाम जीत का इतिहास P-4

कुशासन के ख़िलाफ़ यह जनता की जीत है P-6

न कांग्रेस हारी न भाजपा जीती P-7

भाजपा के लिए भी अविश्वसनीय है

पृष्ठ 1 का शेष

उनकी मीडिया मैनेजमेंट टीम ने अपने क़ब्ज़े में कर रखा था. स्टीव जॉर्डन, जो हावर्ड के प्रोफेसर हैं, वे अखिलेश के लिए रणनीति बना रहे थे. उनके लोगों ने ही मीडिया स्ट्रैटिजी बनाई और काम बोलता है जैसे नारे गढ़े. अखिलेश यादव एक चीज़ भूल गए. शायद प्रोफेसर जॉर्डन भी इस बात को भूल गए कि आप जितना अपने काम का प्रचार करेंगे, उतना ही लोग अपने दाएं-बाएं उस काम को तलाशने लगेंगे. अखिलेश यादव ने ज्यादातर काम शहरी मतदाताओं के लिए किए, चाहे वो मेट्रो हो या आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे हो. आज एक्सप्रेस-वे की क्या हालत है, ये हम बताना नहीं चाहते. बहुत सारी जगहों पर दरार पड़ गई है. एक्सप्रेस-वे पूरा नहीं हुआ है. लखनऊ की मेट्रो भी पूरी नहीं हुई है. अखिलेश यादव अपने पूरे चुनाव-प्रचार में इन्हीं दोनों का ज्यादा गुणगान करते रहे. लेकिन अखिलेश यादव ने ग्रामीण मतदाता के लिए क्या किया? मुलायम सिंह अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ज्यादातर फैसले उन लोगों के लिए लेते थे, जो गांवों में रहते हैं और जो मुलायम सिंह के परंपरागत समर्थक वर्ग में तब्दील हो गए थे. अखिलेश यादव ने इस समर्थक वर्ग का कोई ख्याल नहीं किया. कहने के लिए तो उन्होंने दावा कर दिया कि सिंचाई की सुविधा गांवों में मिल गई है, 24 घंटे बिजली गांवों में मिल गई है, सड़कें गांव में बन गई हैं, सबकुछ गांवों में हो गया है. लेकिन जब गांव वालों ने अपने आस-पास देखा, तो उन्हें ये चीज़ें कहीं दिखाई नहीं दीं.

अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह की 30 साल की राजनीति को ध्वस्त कर दिया और उन्होंने आगे बढ़कर कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया. दरअसल, अखिलेश यादव का जन्म विचारधारा के साथ नहीं हुआ. अखिलेश यादव ने कोई आन्दोलन नहीं देखा, कोई धरना नहीं दिया.

समाजवाद की परिभाषा नहीं समझी. लोहिया, जयप्रकाश का नाम लेना अलग चीज़ है, लेकिन लोहिया, जयप्रकाश क्या थे, ये उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की. अपने संघर्ष के दम पर नेता बने देश की मशहूर शख्सियत मुलायम सिंह यादव के पुत्र होने के नाते अखिलेश यादव प्रसिद्धि प्राप्त करते गए. इसलिए जब उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, तब मुलायम सिंह का परंपरागत समर्थक और गैर कांग्रेसवाद की विचारधारा से अभिप्रेरित वर्ग अखिलेश यादव से दूर चला गया. कैसे-कैसे नारे बने- यूपी को साथ पसंद है. ये एक मशहूर हिंदी गीत, बेबी को बेस पसंद है, पर आधारित है. इस गीत को नारा बनाने को लेकर जिन लोगों ने अखिलेश यादव को राय दी, उनका न तो समाजवाद से कोई रिश्ता है, न संघर्ष से और न ही आंदोलनों से. वो तो मुलायम सिंह या अखिलेश यादव के नाम पर चुनाव जीतकर विधानसभा में जाना चाहते थे. इन्होंने जिन एजेंसियों का सहारा लिया, उन्होंने भी सिवाय अखिलेश यादव से पैसा पीटने के और कुछ नहीं किया. अखिलेश यादव ने उन सारे लोगों को अपने से दूर रखा, जिनमें आंदोलन पहचानने की क्षमता थी, या जिनमें मतदाताओं का मन टटोलने की क्षमता थी. उन्होंने अपने साथ ऐसे लोगों को रखा और उनकी राय पर चले, जिनका आंदोलनों से कोई रिश्ता नहीं रहा. मुलायम सिंह यादव ने पब्लिकली कहा कि रामगोपाल यादव एक दिन भी आंदोलन में नहीं रहे हैं. उन्हें पता ही नहीं कि मैंने पार्टी कैसे बनाई, जबकि वे अखिलेश के फैन, फिलॉस्फर और गाइड बने हुए हैं. अखिलेश यादव ने किसानों से जुड़े वे एक भी काम नहीं किए, जिनके लिए उनके पिता मुलायम सिंह यादव उन्हें हमेशा सलाह देते रहे. दूसरी तरफ, अखिलेश यादव ने उन दो अधिकारियों को अपने सबसे नजदीक रखा और उनके हाथ में पूरा उत्तर प्रदेश सौंप दिया, जो मायावती के सबसे खास अधिकारी थे. इससे ब्यूरोक्रेसी में ये संदेश गया कि ईमानदार और साख वाले अधिकारियों की अखिलेश यादव को कोई जरूरत नहीं है. अखिलेश यादव को उनकी जरूरत है, जो पैसा कमाकर उनको दे सकते हैं. अखिलेश यादव ने पार्टी से भी उन सारे लोगों को दूर रखा, मंत्रिमंडल में भले ही लिया हो, लेकिन कभी उनकी बात नहीं मानी, जिनके बारे में उन्हें शक था कि वे उनके पिता मुलायम सिंह यादव से जाकर मिलते रहते हैं. इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने पांच साल में अपने सगे चाचा शिवपाल यादव की एक भी बात नहीं मानी और न ही उनसे कोई सलाह ली. अखिलेश यादव ने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए, जो उनके लिए आने वाले मुख्यमंत्री के शासनकाल में परेशानीदायक हो सकते हैं. जिनमें एक फैसला आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे है. अगर इसकी जांच हुई, तो वे अधिकारी जिन्होंने अखिलेश यादव (शेष पृष्ठ 3 पर)

अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह की 30 साल की राजनीति को ध्वस्त कर दिया और उन्होंने आगे बढ़कर कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया. दरअसल, अखिलेश यादव का जन्म विचारधारा के साथ नहीं हुआ. अखिलेश यादव ने कोई आन्दोलन नहीं देखा, कोई धरना नहीं दिया. समाजवाद की परिभाषा नहीं समझी. लोहिया, जयप्रकाश का नाम लेना अलग चीज़ है, लेकिन लोहिया, जयप्रकाश क्या थे, ये उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 09 अंक 03
20 मार्च- 26 मार्च 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

इजरायल दौरे की तैयारी

इस साल के अंत तक प्रधानमंत्री इजरायल जाएंगे. साल 1992 के बाद इजरायल की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे. मोदी सरकार के अधीन भारत-इजरायल संबंध में मजबूती आई है. ऐसे में यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती लाएगी. इस यात्रा की तारीख अभी तय होनी है, लेकिन संभावना है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा जून-जुलाई के बीच होगा. इस ऐतिहासिक यात्रा का ग्राउंड तैयार करने के लिए विदेश सचिव एस जयशंकर शीघ्र ही इजरायल जा रहे हैं. इससे पहले अजीत डोभाल हाल ही में दो दिन की इजरायल यात्रा कर चुके हैं. इस तरह की और यात्राएं इधर होंगी. इन वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा, कई वरिष्ठ बाबू भी खास कर रक्षा मामलों के जानकार, इजरायल की यात्रा कर सकते हैं. अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फिलीस्तीन नहीं जाएंगे. ■

नीतीश बनाम बाबू

बीएसएससी घोटाले में गिरफ्तार सुधीर कुमार के मामले में आईएएस अधिकारियों द्वारा लिए गए स्टैंड के खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ा रूख अपनाया है. हालांकि सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार इस केस को सीबीआई के सुपुर्द किए जाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि गुस्से में आए बाबुओं को शांत किया जा सके. आमतौर पर नीतीश कुमार हर एक मामले पर एक स्टैंड रखते हैं, लेकिन सुधीर कुमार की गिरफ्तारी के मामले में वे काफी दिन तक चुप रहे. नीतीश कुमार ने इस मसले पर विधानसभा में बोला भी है. उन्होंने एसआईटी द्वारा एक निपक्ष जांच का आश्वासन भी दिया है. उन्होंने आईएएस बिरादरी द्वारा किए गए प्रदर्शन पर एक निर्णय लिए जाने की भी बात कही, हालांकि इसकी घोषणा अभी की जानी है. ■

पलनीस्वामी के बाबू

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीस्वामी द्वारा किए गए बाबुओं के फेरबदल के तहत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निरंजन मार्दी को गृह सचिव बनाया गया है. वे अपूर्वा वर्मा की जगह आए हैं. वर्मा को पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है. सूत्रों का कहना है कि मार्दी पर मुख्यमंत्री तभी से भरोसा करते हैं, जब वे उच्च पथ विभाग के मंत्री थे और मार्दी उस विभाग के सचिव हुआ करते थे. पलनीस्वामी द्वारा किया गया यह पहला प्रमुख बदलाव है. मार्दी की नियुक्ति से पहले दिसंबर 2016 में पी राम मोहन राव की जगह गिरिजा वैद्यनाथन को राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया था. पर्यवेक्षक मानते हैं कि आने वाले दिनों में और भी बदलाव होंगे, क्योंकि पलनीस्वामी अब धीरे-धीरे सेटल हो रहे हैं और अपने विश्वस्त बाबुओं की टीम बनाने की कोशिश कर रहे है. ■

भाजपा के लिए भी अविश्वसनीय है

पृष्ठ 2 का शेष

को पिछले पांच साल पैसे कमा कर दिए, वे कितने दिन चुप रहेंगे या क्या-क्या नहीं बोलेंगे, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता. अखिलेश यादव के सबसे नजदीकी अधिकारी के बारे में मेरे पास खबर आई है कि इस अफसर की संपत्ति की कीमत पांच हजार करोड़ रुपए है. अखिलेश यादव ने लॉ एण्ड ऑर्डर के ऊपर कंट्रोल नहीं किया. अखिलेश यादव के आसपास के लोग जमीनों पर कब्ज़ा करते रहे. अखिलेश यादव ने पोस्टिंग में अपने समाज के लोगों का ज्यादा ध्यान रखा. आखिरी तीन महीने उन्होंने जिस तरीके से अपने पिता और अपने चाचा से लड़ाई लड़ी, वो उनकी हार के मुख्य कारणों में से एक रहा.

अखिलेश यादव की एक सबसे बड़ी गलती अति पिछड़े समाज को भारतीय जनता पार्टी में भेज देने की है. उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह से सीख नहीं ली. मुलायम सिंह जब तक राजनीति में सक्रिय थे, या जब तक उन्हें जबरदस्ती रिटायर नहीं कर दिया गया, तब तक वे चुनावी सभाओं में अपने साथ अतिपिछड़े वर्ग के या दूसरे पिछड़े वर्ग के नेताओं को मंच पर रखते थे. उन्हें कम सीटें देते थे, लेकिन वे बताते थे कि ये सारा समाज उनके साथ है. अखिलेश यादव ने अपने साथ एक भी अतिपिछड़े समाज के दूसरे नेता को नहीं रखा. इसका परिणाम हुआ कि यादव समाज का भी एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया. लेकिन इससे भी बुरा हाल इससे पहले हुआ, जब पूरा अतिपिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसक गया और अखिलेश यादव को पता भी नहीं चला. हमलोग टेलीविजन प्रोग्राम में, अपने ब्लॉग में, अपने अखबार में लगातार कहते रहे कि अतिपिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव को न तो लिखे जाने की कोई चिंता थी और न ही किसी ने उनको सलाह दी होगी. परिणामस्वरूप अखिलेश यादव कुल 47 सीटों तक सिमट गए. अखिलेश यादव की वजह से ही लोकसभा में मुलायम सिंह यादव की पार्टी को सिर्फ पांच सीटें मिलीं, वो भी उनके घर की, उनके परिवार की और विधानसभा चुनाव में उन्हें सिर्फ 47 सीटें मिलीं. अखिलेश यादव ने ये माहौल बनाया कि मैं नौजवान हूं और राहुल गांधी नौजवान हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश का नौजवान उनके साथ खड़ा है. ठेकेदार परंपरा से आए हुए लोग, स्कॉर्पियो, एसयूवी, फार्चूनर में बैठने वाले लड़के, अखिलेश यादव को नौजवान दिखाई देने लगे. उन्हें वो नौजवान नहीं दिखाई दिया, जो उनके अपने समाज में या अतिपिछड़े समाज में है. सवर्णों की बात तो हम छोड़ ही दें, दलितों की बात भी छोड़ दें. इसके अलावा गलतियों की एक लंबी परंपरा है, जिन्हें अगर अखिलेश यादव खुद समझने की कोशिश करें, तो ज्यादा बेहतर होगा. क्योंकि अगर हम उनके बारे में लिखेंगे, तो शायद उन्हें ये लगेगा कि हम उनमें जबरदस्ती कमियां निकाल रहे हैं. लेकिन 47 सीट लाने के बाद अगर अखिलेश यादव नहीं सोचते हैं, तो भविष्य के लिए भी अखिलेश यादव निरर्थक राजनीति में निरर्थक साबित होंगे.

मायावती जी ने इस भ्रम को नहीं तोड़ा कि वे पैसे लेकर टिकट देती हैं. उनके घर में जो भी गया और जिसने भी टिकट ली, उसने यही कहा कि मैंने दो करोड़ दिए, मैंने दस करोड़ दिए, मैंने पांच करोड़ दिए. जिनकी टिकट बदली गई, उन्होंने आरोप लगाया कि मायावती जी ने पैसे लेकर टिकट बदल दिए. ये चर्चा उत्तर प्रदेश के दलित समाज को झकझोरती रही कि मायावती जी अपने लिए पैसे का इंतजाम कर रही हैं. राजनीतिक रूप से लोगों को मजबूत नहीं कर रही हैं. मायावती ने ये मान लिया था कि दलित समाज के अलावा अतिमहादलित समाज के लोग या अतिपिछड़े लोग उन्हीं को अपना नेता मानकर चलेंगे. वे ये भूल गईं कि हर समाज का आदमी अपने नेता को सबसे बड़े नेता के साथ देखना चाहता है. उसके संवाद का तरीका ही उनके जरिए होता है. मायावती का किसी के साथ संवाद नहीं है. लेकिन एक भ्रम था स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए कि मौर्य समाज का मायावती के साथ संवाद है. ऐसे ही दूसरे समाजों की कहानी है. मायावती ने उनको लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई. पूरे पांच साल मुस्लिम समाज को अपने साथ नहीं रखा. मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, वहां नहीं गईं. आखिर में उन्हें दलित और मुस्लिम गठजोड़ याद आया और उन्होंने मुसलमानों के कुछ सवाल उठाए, लेकिन मुस्लिम समाज ने भी कभी अपने किसी नेता को मायावती के साथ मंच पर नहीं देखा. लिहाजा, मुस्लिम समाज मायावती के साथ खुलेआम नहीं दिखाई दिया. अब परिणाम के दिन मायावती ने ये आरोप लगाया कि ईवीएम मशीन की प्रोग्रामिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है. उन्होंने सवाल उठाया कि दलितों और मुसलमानों ने उन्हें जो वोट दिया वो वोट कहां गया? मायावती अगर कह रही हैं और अगर ये हुआ, तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र का ये सबसे घिनौना षडयंत्र है. इसलिए केंद्र सरकार को इस बयान को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करानी चाहिए. लेकिन सवाल दूसरा है. सवाल ये है कि अगर मायावती ये समझती हैं कि ईवीएम मशीन की प्रोग्रामिंग मे कोई घपला हुआ है, कोई बदलाव हुआ है, तो उन्हें बजाय बयान देने के, पूरे उत्तर प्रदेश के उन लोगों को साथ ले कर सड़क पर आ कर आंदोलन करना चाहिए, जो उनके इस आरोप पर विश्वास करते हैं. ऐसे लोगों के साथ पूरे यूपी को जाम कर देना चाहिए. लेकिन अगर मायावती उत्तर प्रदेश में आंदोलन नहीं करती हैं, सिर्फ बयान देती हैं, तो शायद उन्हें आगे चल कर कुछ और परेशानियों का सामना करना पड़े. दूसरे शब्दों में, मायावती अगर अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं करती हैं और जैसी तस्वीर उन्होंने अपनी बना रखी है, अगर वो खुद वैसी नहीं हैं, तो फिर उन्हें अपनी तस्वीर बदल लेनी चाहिए. अगर वे वैसी ही हैं, तो उन्हें आगे आने वाले समय में राजनीतिक रूप से ज्यादा परेशानी हो सकती है. मैं इस सवाल को नहीं मानता कि सीबीआई की तलवार ने मायावती के कदमों को रोका है.

राहुल गांधी के बारे में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने एक धारणा बना रखी है. राहुल गांधी के इधर के भाषण बहुत अच्छे है. लेकिन उस धारणा के कारण उनकी अच्छी बात को भी लोग नहीं सुन रहे हैं. दूसरे शब्दों में, राहुल गांधी को किसी ने नहीं बताया कि उनके शरीर की भाषा, उनके बोलने का ढंग, शब्दों के ऊपर जोर, शब्दों का उच्चारण और समस्याओं का वर्णन ऐसा होता है, जिससे जनता जुड़ नहीं पाती. जनता से न जुड़ना ही राहुल गांधी की पार्टी की नाकामयाबी का एक बड़ा कारण है. दूसरा बड़ा कारण है, राहुल गांधी द्वारा प्रदेश के संगठन को मजबूत न करना. वे यह समझ ही नहीं पाए कि किस समय संगठन में बदलाव करना चाहिए और अगर बदलाव करना है, तो किन उद्देश्यों के लिए करना चाहिए, या जो लोग काम कर रहे हैं, उनमें से कौन लोग अच्छे हैं, जिन्हें नहीं बदलना चाहिए. एक नेता की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो लोगों को उनकी योग्यतानुसार काम सौंपे. कांग्रेस में योग्यतानुसार काम सौंपने की परिपाटी ही नहीं है. यहां उन्हीं को काम सौंपने की परिपाटी है, जो गणेश परिक्रमा करते हों. इसलिए कांग्रेस के बारे में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ता भी अब टीवी चैनलों पर आ कर साफ-साफ कहना शुरू कर चुके हैं. राहुल गांधी पिछले 4 साल से कांग्रेस को अखिलेश यादव के मुक़ाबले खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे. स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के संदेश दिए, शिविर किए, बैठकें की और फिर अचानक अखिलेश यादव से समझौता कर लिया. पूरी पार्टी आराम की मुद्रा में आ कर बैठ गई. कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकला.

इन सारे सवालों या कमियों को देखने के बाद, हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ आते हैं. नरेंद्र मोदी ने पिछले तीन सालों में बहुत सारे वादे किए. उन वादों पर कछुए की चाल से अमल भी हुआ. उन्होंने नोटबंदी कर दी, मध्य वर्ग को बहुत नुक़सान हुआ, तकलीफ हुई. इससे मध्य वर्ग और नेताओं ने भी मान लिया कि गरीब को भी इससे परेशानी हुई होगी. इसमें कोई दो राय नहीं कि गरीब को भी परेशानी हुई. लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये माहौल बनाना शुरू किया कि वे अमीरों के खिलाफ हैं, कालेधन वालों के खिलाफ हैं, कालाबाज़ारी करने वालों के खिलाफ हैं, इसीलिए सारी पार्टियां उनका विरोध कर रही हैं. उन्होंने लोगों को सफलतापूर्वक समझाया कि नोटबंदी कर इन्हीं वर्गों को नुक़सान पहुंचा रहे हैं, इसीलिए सारे लोग उनका विरोध कर रहे हैं. दूसरा, नरेंद्र मोदी ने अपने हर कदम को देश प्रेम से जोड़ दिया. हमारे यहां देश प्रेम का मतलब होता है, पाकिस्तान से लड़ाई. उन्होंने उसी मानसिकता का फायदा लिया और लोगों से कहा कि जो देश के साथ है, वो हमारे साथ है, यानी जो नरेंद्र मोदी के साथ है, वहीं देशभक्त है. ये हमारे महान विपक्षी नेता समझ ही नहीं पाए कि इस देश का गरीब कब उनके खिलाफ़ हो गया. इस देश के गरीब को लगा कि प्रधानमंत्री उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री उनके हक़ में कुछ करना चाहते है, वे गरीबों को घर दिलाना चाहते हैं, रोजगार दिलाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले ये राजनेता उन्हें ये काम करने से रोक रहे हैं. इस भावना ने वंचितों को, दलितों को, सभी समाज के गरीब तबके को नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा कर दिया. खास कर नौजवान, नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया. जिस नौजवान को अपने साथ रखने का भ्रम अखिलेश यादव ने पाल रखा था और इस भ्रम को एक गुब्बारे में उड़ा कर लोगों को दिखाया था, दरअसल वो पूरा का पूरा तबका नरेंद्र मोदी को वोट देने में अपना हित देखने लगा.

अफसोस की बात ये है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों या समाजवादी पार्टी के नेता हों या बहुजन समाज पार्टी के नेता हों, वे हम पत्रकारों को अपना पब्लिक रिलेशन करने वाला पत्रकार बनाना चाहते हैं. असलियत दिखाने वाला पत्रकार नहीं बनाना चाहते. इसीलिए वे पत्रकार जो असलियत देखते हैं और इन दलों को दिखाते हैं, वे लोग इनके लिए त्याज्य हो जाते हैं.

नरेंद्र मोदी ने फसल बीमा योजना, गांवों में मुफ्त रसोई गैस यानी उज्ज्वला योजना और जनधन खाते जैसे फैसलों से ये आभास दिया कि वे गरीबों के लिए कदम-दर-कदम कुछ करना चाहते हैं. इन कदमों से कोई बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन एक योजना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख को गांव में और महिलाओं के बीच बढ़ा दिया. ये योजना थी, गांव में महिलाओं के बीच गैस चूल्हे और सिलिंडर का वितरण. इस फैसले ने भारतीय जनता पार्टी का या नरेंद्र मोदी का आधार उत्तर प्रदेश के गांव में घर-घर तक पहुंचा दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन-रात सभाएं की. लोगों के बीच में रहे. वहीं, लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को ढूंढते रह गए. अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान दौरे नहीं कर पाए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की लड़ाई को करो या मरो के रूप में लिया. उन्हें मालूम था कि अगर वे उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हो जाते हैं या कम सीटें ला पाते हैं या हंग असेंबली होती है, तो उनके लिए गुजरात मुश्किल हो जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे. उन्हें उत्तर प्रदेश या देश के दूसरे नेताओं पर कोई भरोसा नहीं था. इसलिए उन्होंने प्रचार की कमान सी प्रतिशत अपने हाथ में रखी और उत्तर प्रदेश के हर कोने में जाकर अपनी बात कही. अपनी बातों से अखिलेश यादव को कम राहुल गांधी को ज्यादा बड़ा नेता बनाया और उनका संहार कर दिया.

न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये अंदाजा था कि उन्हें इतनी सीटें आएंगी, न विपक्षी नेताओं को ये अंदाजा था कि उनका इतना बुरा हाल होगा. यहां तक कि पत्रकारों को इस अभूतपूर्व मोदी लहर का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं हुआ और जिन्होंने सीटों का आकलन किया वे सिर्फ रुझान समझ पाए. वे जनता के उस गुस्से को नहीं समझ पाए, जो गुस्सा समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की अकर्मण्यता के कारण या उनके सत्ता में रहने के दौरान मिले घावों से लगा था. इसलिए लोगों ने जाति, धर्म, संप्रदाय, पार्टी सबकी सीमा तोड़ी और नरेंद्र मोदी को इस आशा में वोट दिया कि वे ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे या उस मुख्यमंत्री के ऊपर नजर रखेंगे, जो उत्तर प्रदेश के लोगों का विकास कर सके.

ये विकास का शेर बड़ा खतरनाक है. ये या तो अपने ऊपर सवारी करने देगा, या फिर सवार को ही खा जाएगा. इसलिए इस विकास नाम का गाना इतना ज्यादा हिंदुस्तान में सुना जा चुका है कि अब अगर दो सालों में विकास का रोडमैप नहीं बनता है या लोगों को समझ में नहीं आता है, या लोगों की जिंदगी में किसी प्रकार का सपना वास्तविकता में परिवर्तित होकर अपना असर नहीं दिखाता है, तो फिर शायद 2019 का चुनाव परेशानी वाला हो सकता है.

अफसोस की बात ये है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों या समाजवादी पार्टी के नेता हों या बहुजन समाज पार्टी के नेता हों, वे हम पत्रकारों को अपना पब्लिक रिलेशन करने वाला पत्रकार बनाना चाहते हैं. असलियत दिखाने वाला पत्रकार नहीं बनाना चाहते. इसीलिए वे पत्रकार जो असलियत देखते हैं और इन दलों को दिखाते हैं, वे लोग इनके लिए त्याज्य हो जाते हैं. परिणाम स्वरूप पत्रकारों की साख, वैसे तो पत्रकारों ने खुद ही बहुत खत्म कर ली है, ये राजनेता भी उनकी साख खत्म करने पर तुले हुए हैं. उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद इस बात का डर है कि जैसे विश्व के दूसरे देशों में पत्रकार मुख्य निशाना होने लगे हैं, शायद भारत में भी पत्रकार मुख्य निशाना होने लगें. मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में इसलिए लिखा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का परिणाम सर्वथा आश्चर्यजनक और जनता के गुस्से का द्योतक रहा है. ■

editor@chauthiduniya.com

भाजपा ने किया यूपी से सपा, कांग्रेस और बसपा का सफाया

मोदी के नाम जीत का इतिहास

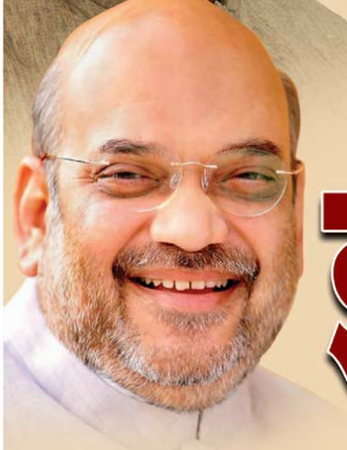

चौथी दुनिया ब्यूरो

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं. चुनाव परिणाम को लेकर अब किस्म-किस्म की समीक्षाएं पेश होंगी और तरह-तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन जमीनी यथार्थ यही है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश और उसके ही शरीर से बने उत्तराखंड के लोगों ने भ्रष्टाचार और कुशासन की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है. 2017 का चुनाव परिणाम राजनीतिक दलों के लिए सीख लेने वाले संदेश की तरह सामने आया है. यह समेकित संदेश है. इसमें धर्म और जाति का भेद नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को यह समझाने में पूरी तरह कामयाब हो चुके हैं कि वे भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ खड़े हैं. जनता के दिमाग में इस समझ के स्थापित होने के कारण ही तमाम प्रचारों-दुष्प्रचारों के बावजूद नोटबंदी कहीं कोई मुद्दा नहीं बना और कुशासन की पृष्ठभूमि पर बैठे सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे दलों की इस बार कोई दाल नहीं गली. भाजपा के पक्ष में वोटों का आच्छादन बताता है कि उसे समाज के प्रत्येक वर्ग का वोट मिला. मुसलमानों का भी वोट मिला, इसमें मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा का अधिक पक्ष लिया.

भाजपा की ऐसी ऐतिहासिक जीत से सपा, बसपा, कांग्रेस बौखला गई हैं. सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने यहां तक कह दिया कि भाजपा ने जनता के साथ धोखाधड़ी की, लोगों को बांटा और बरगलाया. इस पर सपा के ही वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कहा कि यह हार समाजवादियों की नहीं, घमंडियों की हार है. वहीं बसपा नेता मायावती ने आरोप लगा दिया कि भाजपा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ छेड़छाड़ की और अपने मन-मुताबिक परिणाम निकलवा लिया. हालांकि इस आरोप को पुष्ट करने के लिए मायावती ने कोई प्रमाण नहीं दिया. उन्होंने इस बात पर भी आश्चर्य जाहिर किया कि भाजपा द्वारा एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिए जाने के बावजूद मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भाजपा को भारी वोट कैसे मिले! मायावती ने कहा कि वॉटिंग मशीन में 'सेटिंग' की वजह से बसपा हार गई. मायावती बोलीं कि वर्ष 2014 में भी ऐसी ही गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी और हाल में महाराष्ट्र में हुए महानगर पालिका के चुनावों में भी ईवीएम में 'मैनिपुलेशन' की शिकायत सामने आई है. अखिलेश यादव ने भी 'ईवीएम-मैनिपुलेशन' की तरफ इशारा किया और यह भी कहा कि जनता का फैसला उन्हें स्वीकार है. उन्होंने उम्मीद जताई कि नई सरकार बेहतर काम करेगी. अखिलेश ने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में जो निर्णय आएंगे, उसका हम सबको इंतजार रहेगा. किसानों का कर्ज माफ हुआ, तो उन्हें बहुत खुशी होगी.

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जनादेश ने सपा-कांग्रेस गठबंधन तकनीक और बसपा की नई धार्मिक-अभियांत्रिकी को उनकी खोलों में समेट कर रख दिया. मैदान से लेकर पहाड़ तक भाजपा का दबदबा कायम हो गया. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह रही कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी भाजपा को जीत मिली. सपा-कांग्रेस गठबंधन नंबर दो और बसपा नंबर तीन पर स्थान बना पाई. पहले और दूसरे के बीच संख्या की खाई बहुत ज्यादा गहरी है. उत्तराखंड में तो बसपा शून्य में ही रह गई. देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर ही लगा था. यूपी की 403 विधानसभा सीटें पूरे देश की राजनीति का ताप बदल देती हैं. यहां सात विभिन्न चरणों में चुनाव हुए. पहले चरण में 11 फरवरी को 15 जिलों की 73 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए. दूसरे चरण में 15 फरवरी को 11 जिलों की 67 सीटों के लिए चुनाव हुए. तीसरे चरण में 69 सीटों पर 19 फरवरी को चुनाव कराया गया. चौथे चरण में 53 सीटों पर 23 फरवरी को वोटिंग हुई. पांचवें चरण में 52 सीटों के लिए 27 फरवरी को और छठे चरण में 49 सीटों पर 4 मार्च को चुनाव हुए. सातवें चरण में 40 सीटों पर 8 मार्च को हुए मतदान के बाद चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हुई.

2017 के विधानसभा चुनाव की खासियत यह रही कि इसने राम मंदिर आंदोलन काल में भाजपा को मिले जनादेश को भी पीछे धकेल दिया. उस समय भाजपा को 221 सीटें, यानि, करीब 32 प्रतिशत वोट मिले थे. पिछले (2007) चुनावी नतीजों का विश्लेषण करें, तो पाएंगे कि 28 फीसदी से अधिक वोट पाने वाली पार्टी बसपा की सरकार बनी थी. 2007 में बसपा ने 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त की थी. वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी को 224 सीटों के साथ 29.13 प्रतिशत वोट मिले थे और वह सत्ता पर काबिज हुई थी. 2012 के चुनाव में बसपा को 25.91 प्रतिशत वोट मिले थे. 2007 में सपा को 25.5 फीसदी मत मिले थे. भाजपा को उन दोनों चुनावों में महज 17 प्रतिशत के आसपास वोट मिले थे. लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का भाग्य पलटा और उसे 42.3 प्रतिशत वोट के साथ 73 सीटें हासिल हुईं. ठीक वही हाल 2017 के विधानसभा चुनाव में हुआ, जिसमें भाजपा को तीन चौथाई से भी ज्यादा सीटें हासिल हुईं. भाजपा को 403 सीटों में अकेले 312 सीटें मिलीं. भाजपा की सहयोगी अपना दल को नौ सीटें मिलीं, जबकि दूसरी सहयोगी भारतीय समाज पार्टी को भी चार सीटें मिली हैं. यानि, 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को कुल 325 सीटें हासिल हुई हैं. समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन को महज 54 सीटें हासिल हुईं. इनमें 47 सीटें सपा को और सात सीटें कांग्रेस को मिली हैं. बसपा का हाल सबसे खराब रहा. उसे महज 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा. फिर से याद दिलाते चलें कि 2012 के चुनाव में सपा को 224 सीटें मिली थीं और कांग्रेस 28 सीटों पर विजयी हुई थी. भाजपा की जीत को मार्जिन के नजरिए से देखें, तो पाएंगे कि सपा, बसपा और कांग्रेस की 'जमानत' जब्त हो गई. उत्तराखंड में भी भाजपा को 69 में से 56 सीटें मिलीं और तीन चौथाई बहुमत हासिल हुआ. कांग्रेस को महज 11 सीटें मिलीं. मुख्यमंत्री हरीश रावत दो सीटों से चुनाव लड़े थे, दोनों जगह से हार गए. उत्तराखंड में विधानसभा की कुल सीटें 70 हैं.

यूपी में चुनाव परिणाम आने के बाद सपा नेता भी कहने लगे हैं कि मुलायम परिवार का झगड़ा न हुआ होता, तो न आखिरी कील ठोक दी. साधना गुप्ता ने यह भी कहा कि शिवपाल यादव का कोई दोष नहीं है, सब रामगोपाल का किया धरा है. साधना गुप्ता ने कहा कि उनका बहुत अपमान हुआ, वे अब और सहन नहीं करेंगी. उन्होंने शिवपाल का पक्ष लिया और कहा, उन्हें गलत ढंग से पार्टी से किनारे किया गया. चुनाव परिणाम के बाद प्रो. रामगोपाल यादव परिदृश्य से गायब हैं.

यह सही है कि नरेंद्र मोदी की लहर के बारे में सपा समेत किसी भी पार्टी को अनुमान नहीं लग पाया. खुद भाजपा को भी यह भान नहीं था कि अंदर-अंदर इतनी बड़ी सुनामी की शक्ल ले रही है. लेकिन इतनी दयनीय स्थिति पर पार्टी को ला खड़ा करने के लिए अखिलेश ही नहीं, मुलायम भी उतने ही दोषी हैं. प्रो. रामगोपाल भी उतने ही दोषी हैं. परिवार के अंदरूनी विवाद को सार्वजनिक मंचों पर लाकर मुलायम ने उसे अधिक सड़ाया. घर का झगड़ा सड़क तक ला दिया. यह झगड़ा भी लगातार चलता रहा और गहराता रहा. मुलायम और उनके बेटे के बीच या चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच राजनीतिक वर्चस्व का झगड़ा था, तो इसे सड़क पर लाने की क्या जरूरत थी? उसे घर में निपटाने के बजाय उसे पार्टी के सार्वजनिक मंचों पर निपटाया जाने लगा. इसे पूरी दुनिया ने देखा. इसे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा. आम लोगों की तरफ से ये सवाल उठे कि प्रदेश की जनता ने वर्ष 2012 में सपा को जनादेश क्या परिवार का झगड़ा देखने के लिए दिया था? जनता ने भीतर-भीतर यह तय कर लिया था कि इस कलह का पुरस्कार सपा को कैसे देना है. पिता को जबरन पार्टी से बेदखल कर खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करने वाले अखिलेश यादव के सिपहसालार भी उन्हें डुबोने के लिए आमादा थे. कांग्रेस से गठबंधन करने की सलाह देने वाले उनके परामर्शदाता राजनीतिक दूरदृष्टि के हिसाब से पूरे विकलांग ही साबित हुए. मुख्यमंत्री और स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इतने सत्ता दंभ में थे कि कांग्रेस से गठबंधन को लेकर किसी वरिष्ठ नेता से कोई सुझाव लेने की जरूरत नहीं समझी. सारे वरिष्ठों को वे धकिया चुके थे, तो सलाह किससे लेते! हालांकि उपेक्षित किए जाने के बावजूद मुलायम ने कांग्रेस से गठबंधन को सपा के लिए आत्मघाती बताया था. लेकिन मुलायम की सुन कौन रहा था! चाटुकारों की भीड़ के अलावा अखिलेश के पास कोई दूसरा कार्यकर्ता फटक भी नहीं पा रहा था. लेकिन ऐसे आचरणों से कार्यकर्ताओं में नकारात्मक संदेश तो जा ही रहा था. राहुल तो अपनी खाट खड़ी करने पर आमादा थे ही, उन्होंने अखिलेश के माथे पर भी टूटी खाट पटक दी. लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था अखिलेश सरकार के लिए बड़ा मुद्दा बना. लेकिन असलियत यह है कि खराब कानून व्यवस्था से अधिक खराब माना गया था, अखिलेश द्वारा यादव सिंह जैसे भ्रष्ट अधिकारियों और गायत्री प्रजापति जैसे भ्रष्टतम मंत्रियों को संरक्षण दिया जाना. इस अनैतिक संरक्षण के कारण अखिलेश जनता के सामने बुरी तरह एक्सपोज़ हुए, लेकिन उन पर जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था. पर जनता के बीच अखिलेश का यह रवैया भीषणरूप से नापसंद किया जा रहा था. मुजफ्फरनगर के दंगे से लेकर मां-बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार की लोमहर्षक घटनाओं ने अखिलेश का बड़ा नुकसान किया. नोटबंदी पर सपा, कांग्रेस और बसपा की गिरोहबंदी ने रही सही कसर पूरी कर दी. जनता को उकसाने की उनकी कोशिशें नाकाम रहीं और चुनाव में लोगों ने उन तिकड़मों का हिसाब-किताब बराबर कर दिया. भाजपा सांसद व पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कौशल किशोर कहते हैं कि अखिलेश के नारे 'काम बोलता है' ने सपा का 'काम लगा दिया', क्योंकि जनता को यह सफेद झूठ पसंद नहीं आया. बसपा नेता मायावती के बारे में कौशल कहते हैं कि मायावती ने बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों को ताक पर रख दिया, तो व्यापक दलित समुदाय ने मायावती और उनकी पार्टी को ही ताक पर रख दिया.

शेष पृष्ठ संख्या 5 पर

यूपी के 20 सीएम, पर कोई दो बार लगातार 'रिपीट' नहीं हुआ

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक सफलताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, लेकिन उत्तर प्रदेश की परम्परा एक बार एक मुख्यमंत्री को कुर्सी देने की रही है. यानि, कोई मुख्यमंत्री आज तक अपनी कुर्सी पर दो बार लगातार 'रिपीट' नहीं हो पाया है. गोविंद वल्लभ पंत से लेकर अखिलेश यादव तक कोई भी व्यक्ति निरंतरता में दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाया. उत्तर प्रदेश में अब तक 20 मुख्यमंत्री हो चुके हैं. इनके अलावा तीन कार्यकारी मुख्यमंत्री भी हुए हैं, जिनका कार्यकाल छोटा रहा है. 2017 में निवर्तमान मुख्यमंत्री हुए अखिलेश यादव 15 मार्च 2012 को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए थे. उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा को 1952-57 तक गोविंद वल्लभ पंत के रूप में मुख्यमंत्री मिला. दूसरी विधानसभा 1957-62 तक चली, जिसमें सम्पूर्णानंद मुख्यमंत्री बने. इसके बाद चंद्रभानु गुप्त, सुचेता कृपलानी, चंद्रभानु गुप्त, चरण सिंह, चंद्रभानु गुप्त, चरण सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, राम नरेश यादव, बनारसी दास, विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्रीपति मिश्र, नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती, राष्ट्रपति शासन, मायावती, कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्त, राजनाथ सिंह, मायावती, मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने. इनमें से कई नेता दो बार तो मुख्यमंत्री बने, लेकिन कोई भी नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक से दूसरे सत्र में 'रिपीट' नहीं हुआ.

पहाड़ पर भी कांग्रेस 'भक्क-काटा'...

पृष्ठ 4 का शेष

मोदी लहर का असर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी दिखा, जहां से कांग्रेस का 'भक्क -काटा' हो गया. हरीश रावत सरकार में काबीना मंत्री रहे नेता तो चुनाव हारे ही, खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत भी हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा सीट से चुनाव हार गए. उत्तराखंड की 69 सीटों (खबर लिखे जाने तक एक का परिणाम बाकी था) में से भाजपा को 57 और कांग्रेस को 11 सीटें ही मिलीं. हालांकि इस आकर्षक जीत के बावजूद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट चुनाव हार गए. गढ़वाल के सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी ने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की जीत को मोदी की कार्यशैली की जीत बताया.

चुनाव में भाजपा के 'परफॉर्मेंस' को लेकर तमाम आशंकाएं जताई जा रही थीं. कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नेताओं को टिकट दिए जाने से लेकर तमाम 'बाहरियों' को टिकट दिए जाने से भाजपा के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी. कई दिग्गज भाजपा नेता बागी प्रत्याशी के बतौर चुनाव मैदान में भी आ डटे थे. ऐसा लग रहा था कि असंतुष्टों और बागियों की वजह से भाजपा को अपेक्षित सफलता न मिल पाए. लेकिन ऐसी आशंकाएं निर्मूल साबित हुईं. टिकट नहीं दिए जाने से नाराज भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी लक्ष्मी अग्रवाल सहसपुर से निर्दलीय खड़ी हो गई थीं. कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में आए यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य दोनों को टिकट दिए जाने से वे नाराज थीं. भाजपा ने इस बार एक दर्जन से अधिक उन नेताओं को टिकट दिए, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे. कांग्रेस से भाजपा में आए सतपाल महाराज चौबटाखाल से लड़ रहे थे. उनके लिए भाजपा ने तीरथ सिंह रावत का टिकट काट दिया. रावत चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन उनके करीबी कवींद्र इस्टवाल सतपाल महाराज के मुकाबले खड़े थे. भाजपा ने नरेंद्र नगर सीट पर कांग्रेस से आए सुबोध उनियाल को टिकट दिया. इससे नाराज ओम गोपाल रावत बागी प्रत्याशी के बतौर खड़े हो गए थे. कांग्रेसी से भाजपाई बने हरक सिंह रावत की वजह से ही भाजपा के शैलेंद्र रावत को इस्तीफा देना पड़ा. हरक सिंह रावत को भाजपा ने कोटद्वार से टिकट दिया, जहां से शैलेंद्र चुनाव लड़ना चाहते थे. शैलेंद्र बाद में कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस ने उन्हें गढ़वाल की यमकेश्वर सीट से टिकट दे दिया था.

उत्तराखंड के सात सीएम, पर कोई दो बार लगातार 'रिपीट' नहीं हुआ

उत्तराखंड प्रदेश के निर्माण से लेकर अब तक सात मुख्यमंत्री हो चुके हैं. पर्वतीय प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के बतौर नित्यानंद स्वामी का नाम दर्ज हो चुका है. स्वामी 9 नवम्बर 2000 से लेकर 29 अक्टूबर 2001 तक मुख्यमंत्री रहे. स्वामी के बाद 30 अक्टूबर 2001 से 01 मार्च 2002 तक भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे. कोश्यारी के बाद प्रदेश में कांग्रेस का दौर आया और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने. एनडी 02 मार्च 2002 से 07 मार्च 2007 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे. एनडी के बाद फिर भाजपा के भुवन चन्द्र खंडूरी मुख्यमंत्री बने. खंडूरी 08 मार्च 2007 से 23 जून 2009 तक मुख्यमंत्री रहे. खंडूरी के बाद 24 जून 2009 से लेकर 10 सितम्बर 2011 तक रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे. भुवन चन्द्र खंडूरी दोबारा मुख्यमंत्री बने और 11 सितम्बर 2011 से 13 मार्च 2012 तक सीएम की कुर्सी पर काबिज रहे. इसके बाद फिर कांग्रेस का दौर आया, जब विजय बहुगुणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. बहुगुणा 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे. उसके बाद ही कांग्रेस के हरीश रावत मुख्यमंत्री बने. रावत 01 फरवरी 2014 से अब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे. उत्तराखंड में भी कोई मंत्री लगातार दूसरी बार 'रिपीट' नहीं हुआ.■

70 सीटों वाले उत्तराखंड की आधे से अधिक सीटों पर बागी खेल बिगाड़ने में लगे थे. यह अकेले भाजपा के साथ नहीं था. कांग्रेस भी बागियों से परेशान थी. बगावत ने कांग्रेस का तो खेल बिगाड़ा, लेकिन भाजपा का कुछ नहीं बिगड़ा. कांग्रेस के आर्येंद्र शर्मा का सहसपुर सीट से चुनाव लड़ना तय था, लेकिन ऐन मौके पर उनका पत्ता कट गया. फिर वे निर्दलीय ही खड़े हो गए थे. वहीं से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय मैदान में थे, जो इन्हीं वजहों से चुनाव हार गए. निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उपाध्याय को उनकी परम्परागत टिहरी सीट से नहीं लड़वाया. इससे उपाध्याय नाराज भी थे. हालांकि हरीश रावत भी चुनाव में धराशाई ही रहे. कांग्रेस के समक्ष कई दिक्कतें थीं. हरिद्वार की ज्वालापुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार एसपी सिंह के खिलाफ बागी ब्रजरानी खड़ी थीं, तो कुमाऊं की भीमताल सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी दान सिंह भंडारी के खिलाफ राम सिंह कैड़ा बागी उम्मीदवार के रूप में खड़े थे. कुमाऊं की ही द्वाराहाट सीट पर कांग्रेस के मदन बिष्ट के खिलाफ कुबेर कठायत खड़े थे. दिलचस्प यह रहा कि भाजपा ने कांग्रेस छोड़कर आए 13 नेताओं को टिकट दिया, तो कांग्रेस ने भाजपा से कांग्रेस में आए 7 नेताओं को टिकट दिया था.

सियासी कतरब्यौंत और परस्पर तिकड़मबाजी में उत्तराखंड के मूल मुद्दे हाशिए पर ही रहे. राजधानी गैरसैंण ले जाने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पलायन व रोजगार जैसे मसले किनारे रह गए. राज्य के पर्वतीय जिलों में डॉक्टरों का घोर अभाव है. राज्य में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन किसी ने भी स्वास्थ्य क्षेत्र की गंभीर समस्याओं के हल के लिए कुछ नहीं किया. पहाड़ के गांवों से पलायन की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि तीन हजार गांव ऐसे हैं, जहां आज एक भी मतदाता नहीं बचा है. उत्तराखंड के 16 हजार 793 गांवों के 2 लाख 57 हजार 8 सौ 75 घरों में पलायन के कारण ताले लटक चुके हैं. इसके कारण राज्य के चीन से लगे सीमान्त क्षेत्र को गम्भीर सामरिक खतरा भी पैदा हो गया है. लोगों का पलायन रोकने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई. पर्वतीय प्रदेश की समस्याएं जस की तस सामने खड़ी हैं. राज्य में रहने वाले बंगाली, पूरबिया, पंजाबी, मैदानी दलितों की उपेक्षा की बात तो खूब होती है, लेकिन पहाड़, पहाड़ी दलितों, पहाड़ की कुमाऊंनी वगढ़वाली भाषा और लोक-संस्कृति के विलुप्त होते जाने की कोई नेता चर्चा नहीं करता. महिलाओं की पीड़ा की बात किसी राजनीतिक दल ने नहीं की. पहाड़ के लोगों का कहना है कि पहली बार किसी विधानसभा चुनाव में लगा ही नहीं कि यह उत्तराखंड का चुनाव है. लगा कि जैसे यह चुनाव उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है. केवल राज्य का नाम बदला है और कुछ नहीं. उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड एक राज्य के रूप में 9 नवम्बर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था. उत्तर प्रदेश के 13 जिलों हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल व उधमसिंह नगर को मिलाकर उत्तराखंड बना था. यहां केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं. उत्तराखंड की पहली अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री भाजपा के नित्यानंद स्वामी बने थे, जो उसके पहले उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति थे. अक्टूबर 2001 में भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री बनाए गए. उत्तराखंड के चौथे विधानसभा चुनाव के तहत 15 फरवरी 2017 को 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ.■

feedback@chauthiduniya.com

पूंजीपतियों और अपराधियों का दलों पर दबदबा

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव कई किस्म के रिकॉर्ड कायम करने वाला चुनाव भी साबित हुआ. विधानसभा चुनाव में उतरा हर तीसरा उम्मीदवार बलात्कार, हत्या और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों का अभियुक्त था. उत्तर प्रदेश में इस बार कुल प्रत्याशियों में से 30 प्रतिशत करोड़पति प्रत्याशी थे. उत्तराखंड भी पीछे नहीं रहा. उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए कुल 4,853 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा. उनमें से 4,823 उम्मीदवारों के हलफनामों के आधार पर 859 उम्मीदवारों, यानी करीब 18 प्रतिशत प्रत्याशियों ने खुद ही यह बताया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. 15 प्रतिशत उम्मीदवारों यानि, 704 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. विडंबना यह है कि 30 उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग के समक्ष अपना शपथपत्र भी ठीक से नहीं भरा और आयोग ने भी उसे अस्पष्ट माना. इसके बावजूद उन उम्मीदवारों ने बाकायदा चुनाव लड़ा और आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की. इनमें बसपा के नकुल दुबे समेत कई प्रत्याशी शामिल हैं. बहरहाल, यह भी साफ हुआ कि इस बार के चुनाव में करीब 1,457 उम्मीदवार ऐसे थे, जो करोड़पति और अरबपति हैं. आप इसी से समझें कि प्रत्याशियों की औसत सम्पत्ति ही 1.91 करोड़ रुपये की आंकी गई है.

अपराधियों को चुनाव लड़वाने में समाजवादी पार्टी व कांग्रेस गठबंधन पहले नंबर पर रहा. सपा-कांग्रेस मिला कर उनके 69 प्रतिशत प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले हैं. सपा के 37 प्रतिशत और कांग्रेस के 32 प्रतिशत उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही, जिसके 40 प्रतिशत प्रत्याशी आपराधिक पृष्ठभूमि के थे. बसपा के 400 उम्मीदवारों में से 150 उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के थे. भाजपा के 36 प्रतिशत प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसके अलावा बसपा के 31, सपा के 29, भाजपा के 26 और कांग्रेस के 22 प्रतिशत उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर (संज्ञेय) अपराध के मामले दर्ज हैं.

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का कोई भी ऐसा चरण नहीं रहा, जिसमें अपराधी या धनपति उम्मीदवारों की खासी तादाद नहीं थी. 11 फरवरी को हुए पहले चरण के चुनाव में 302 करोड़पति उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा. पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले 168 प्रत्याशी आपराधिक पृष्ठभूमि के थे. पहले चरण में कुल 836 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें बसपा के 73 में से 66, भाजपा के 73 में से 61, सपा के 51 में से 40, कांग्रेस के 24 में से 18, राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के 57 में से 41 और 293 निर्दलीय उम्मीदवारों में से 43 उम्मीदवार करोड़पति थे. पहले चरण में चुनाव में उतरे उम्मीदवारों की औसत सम्पत्ति 2.81 करोड़ रुपये है. पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले आपराधिक छवि के 168 प्रत्याशियों में से 143 उम्मीदवारों पर हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध समेत कई गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं. यह भी उल्लेखनीय है कि इस चरण में चुनाव लड़ने वाले 186 उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग के समक्ष पैन का ब्यौरा भी पेश नहीं किया था.

दूसरे चरण के चुनाव में कई रोचक और हैरत में डालने वाले तथ्य सामने आए. दूसरे चरण का चुनाव लड़ने वाले बसपा के 67 प्रत्याशियों में से 25 (37 प्रतिशत) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. सपा के 51 प्रत्याशियों में से 21 (41 प्रतिशत) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. भाजपा के 67 प्रत्याशियों में से 16 (24 प्रतिशत) और कांग्रेस के 18 प्रत्याशियों में से छह (33 प्रतिशत) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. दूसरे चरण में चुनाव मैदान में उतरे 206 निर्दलीय प्रत्याशियों में से 13 (6 प्रतिशत) प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं. दूसरे चरण के 107 आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों में से 66 प्रत्याशियों पर हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे संगीन मामले दर्ज हैं. इन 66 प्रत्याशियों में बसपा के 17 प्रत्याशी (25 प्रतिशत), भाजपा के 10 प्रत्याशी (15 प्रतिशत), सपा के 17 प्रत्याशी (33 प्रतिशत), कांग्रेस के 4 प्रत्याशी (22 प्रतिशत), रालोद के 52 प्रत्याशियों में से 6 प्रत्याशी (12 प्रतिशत) और 12 निर्दलीय प्रत्याशी (6 प्रतिशत) शामिल हैं. दिलचस्प यह है कि दूसरे चरण में चुनावी मैदान में उतरे 277 यानि 39 फीसदी उम्मीदवार पांचवीं से 12वीं कक्षा पास थे. 310 उम्मीदवार स्नातक थे. 11 उम्मीदवार तो बिल्कुल ही निरक्षर थे. चुनाव के तीसरे चरण में 250 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में थे. तीसरे दौर में 110 उम्मीदवार ऐसे थे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं. 250 करोड़पति प्रत्याशियों में बसपा के 56 प्रत्याशी, भाजपा के 61, सपा के 51, कांग्रेस के 7, रालोद के 13 और 24 निर्दलीय प्रत्याशी शामिल थे. तीसरे चरण के 208 प्रत्याशियों ने अपने पैन का ब्यौरा ही नहीं दिया. आपराधिक पृष्ठभूमि के 110 प्रत्याशियों में से 82 के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं. इन 110 प्रत्याशियों में 21 भाजपा के, 21 बसपा के, पांच रालोद के, 13 सपा के, पांच कांग्रेस के और 13 निर्दलीय हैं. चौथे चरण के मतदान में 189 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में थे हैं. 116 उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले थे. 189 करोड़पतियों में बसपा के 45, भाजपा के 36, सपा के 26, कांग्रेस के 17, रालोद के 6 और 25 निर्दलीय शामिल हैं. आपराधिक पृष्ठभूमि के 116 उम्मीदवारों में से भाजपा के 19, बसपा के 12, रालोद के 9, सपा के 13, कांग्रेस के 8 और 24 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं. पांचवें चरण में चुनावी मैदान में उतरे 612 उम्मीदवारों में से 117 यानि 19 प्रतिशत प्रत्याशी आपराधिक छवि वाले थे. 168 यानी 27 प्रतिशत उम्मीदवार करोड़पति थे. आपराधिक छवि वाले 117 प्रत्याशियों में बसपा के 23, भाजपा के 21, रालोद के 8, सपा के 17, कांग्रेस के 3 और 19 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं. इसी तरह छठे चरण में चुनाव में उतरे 635 उम्मीदवारों में से 20 फीसदी यानि 126 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज थे. आखिरी सातवें चरण में भी राजनीतिक दलों के आपराधिक, दागी और करोड़पति उम्मीदवारों कमी नहीं थी. आखिरी चरण में 115 प्रत्याशी दागी और आपराधिक छवि वाले थे. वहीं 535 में से 132 उम्मीदवार करोड़पति की हैसियत वाले थे.

उत्तराखंड का भी यही रहा हाल: पर्वतीय प्रदेश में हुए चुनाव में भी 200 से ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे. विधानसभा चुनाव में डटे 637 उम्मीदवारों में से 91 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें 54 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. पांच उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज है. पांच उम्मीदवारों पर हत्या प्रयास और पांच उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं. उत्तराखंड में भाजपा के 70 उम्मीदवारों में से 19 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. कांग्रेस के सात उम्मीदवारों पर आपराधिक केस हैं. बसपा के चार उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं. 200 करोड़पति उम्मीदवारों में कांग्रेस के 52, भाजपा के 48 और बसपा के 19 उम्मीदवार शामिल हैं.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

विधानसभा चुनाव परिणाम

कुशासन के ख़िलाफ़ यह जनता की जीत है

आख़िर सत्ता विरोधी लहर ने अपना काम कर ही दिया, लेकिन इन सब के बीच महीनों से चल रहा एक सशक्त अनुमान भी ध्वस्त हो गया. ये अनुमान था आम आदमी पार्टी को लेकर. कहा जा रहा था कि यह पार्टी पंजाब चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी. इसे बहुमत मिल सकता है या कम से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है. चुनाव परिणाम ने इन आकलनों को गलत साबित कर दिया. एक साल पहले तक यहां सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही आम आदमी पार्टी को विपक्ष में बैठ कर ही संतोष करना पड़ेगा. कांग्रेस पार्टी ने अकाली दल-बीजेपी गठबंधन से सत्ता छीन ली. पंजाब की 117 सीटों वाली विधानसभा के लिए 4 फरवरी को एक ही चरण में वोटिंग हुई थी. करीब 77 फीसदी मतदान हुआ था. राज्य के 1.98 करोड़ मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया था. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों सरकार बनाने का दावा कर रहे थे.

पंजाब चुनाव इसलिए भी दिलचस्प था क्योंकि यहां अब तक द्विपक्षीय लड़ाई होती थी, जो इस बार त्रिकोणीय हो गई. आम आदमी पार्टी ने अकाली और कांग्रेस के लिए एक चुनौती पेश की थी. हालांकि इस चुनौती को कांग्रेस ने खत्म कर दिया. निश्चित तौर पर अकाली दल के खिलाफ एंटी इन्कमबेंसी फैक्टर ने काम किया. भाजपा के पास यहां कुछ खास करने को था नहीं. इस चुनाव में आप और कांग्रेस के बीच मुख्य टक्कर होने की संभावना अधिक थी. ये माना जा रहा था कि अकाली बुरी तरह से हारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अकाली दल ने इतनी सीटें तो अपने नाम कर ही ली, जिससे कि वो राज्य की राजनीति में प्रासंगिक बनी रहे. सवाल है कि ऐसा क्या हुआ, जिससे पंजाब में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस को सत्ता मिल गई. जब पंजाब चुनाव की रणभेरी बजी, तभी सभी दलों ने कई वादे किए थे. ड्रग्स को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो इसे जड़ से उखाड़ फेकेंगे. एम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 10 जिलों की कुल 1.23 करोड़ युवा आबादी नशे की गिरफ्त में है. पंजाब में नशे से संबंधित करीब 15 हजार एफआईआर दर्ज हो चुके हैं. दिलचस्प रूप से नशे के इस कारोबार के लिए सत्ताधारी दल शिरोमणि अकाली दल के कुछ नेताओं पर ही आरोप थे. ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और काफी हमलावर तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी नशे के मुद्दे को अपना चुनावी शस्त्र बनाया. तो क्या पंजाब के युवाओं ने ड्रग्स के मुद्दे पर आप का साथ नहीं दिया? क्यों अकाली दल के कद्दावर नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, जिन पर ड्रग्स कारोबार का आरोप लगा, वो भारी मतों से मजीठा विधानसभा से चुनाव जीत गए. जाहिर है, पंजाब की जनता और खास कर युवा वर्ग ने इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा मानने से इंकार कर दिया.

किसे कितनी सीटें मिलीं (117 सीट)

किसे कितने वोट मिले

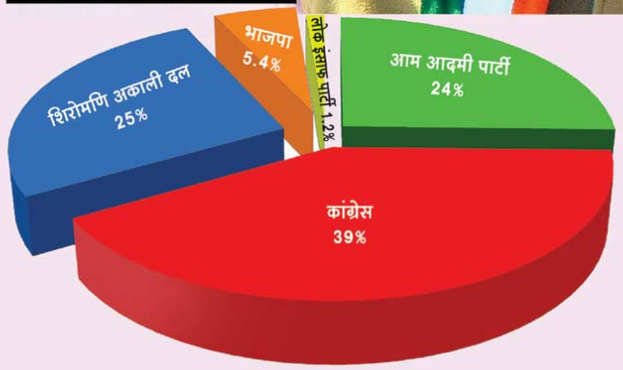

ये जानना भी दिलचस्प होगा कि आखिर वो क्या वजहें रही जिसने आम आदमी पार्टी की उम्मीदें तोड़ दी. इसमें सबसे पहले तो यह समझ में आता है कि पार्टी की ओर से स्थानीय नेताओं के ऊपर दिल्ली से भेजे गए नेताओं का प्रभाव अधिक था, यानी स्थानीय नेताओं के पास निर्णय लेने के अधिकार तक नहीं थे. दिल्ली से पंजाब की राजनीति तय करने की कोशिश की गई. इसका नतीजा यह हुआ कि पार्टी में स्थानीय स्तर पर मतभेद गहराते चले गए. पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रमुख चेहरा रहे सुच्चा सिंह छोटेपुर को बेइज्जत कर पार्टी से बाहर निकाला गया. इससे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में अंदर ही अंदर गुस्सा पनपा. सुच्चा सिंह को जमीनी नेता माना जाता था. उन्होंने भी विद्रोह कर के अलग पार्टी बन ली और चुनाव लड़े. वो खुद चुनाव हार गए लेकिन सांगठनिक क्षमता की वजह से वे आप का भी नुकसान कर गए. एक और विवादास्पद घटना तब घटी, जब पार्टी ने अपने घोषणापत्र में चुनाव चिन्ह झाड़ू को स्वर्ण मंदिर के साथ प्रकाशित कर दिया. ऐसा माना जाता है कि इसका भी नकारात्मक असर मतदाताओं पर पड़ा. ऐसा कहा गया था कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं. टिकट वितरण को लेकर भी काफी सवाल उठे. टिकट नहीं मिलने से नाराज लोगों ने आरोप लगाया कि पैसे वाले उम्मीदवारों को जमीनी कार्यकर्ताओं पर तरजीह दी गई.

ऐसा माना जा रहा था कि एंटी इन्कबेंसी वोट आम आदमी पार्टी को मिलेगा, लेकिन यह निश्चित तौर पर कांग्रेस के खाते में चला गया. नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस में आना भी कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुआ. सिद्धू एक लोकप्रिय नेता और कुशल वक्ता हैं. उनकी पंजाब के मतदाताओं पर भी मजबूत पकड़ है. पहले आम आदमी पार्टी में आने के लिए उनके और केजरीवाल के बीच बातचीत हुई लेकिन जिस तरीके से बातचीत हुई उससे सिद्धू नाराज हो गए और फिर सीधे कांग्रेस में चले गए. कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने ये संदेश भी पंजाब की जनता को देने की कोशिश की कि केजरीवाल या उनकी पार्टी बाहरी है. वे लोग पंजाब और पंजाबियत को नहीं समझते हैं. इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता टोपी की जगह पगड़ी पहनते नजर आए. इसके बावजूद यह लगता है कि पंजाब के लोगों ने उन्हें अपना मानने से इंकार कर दिया. इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक रैली में यहां बोला कि लोग आम आदमी पार्टी को यही मान कर वोट दें कि वो अरविंद केजरीवाल को वोट दे रहे हैं. इसके बाद खुद केजरीवाल ने भी स्पष्टीकरण दिया और यह साफ किया कि वे दिल्ली छोड़ कर कहीं नहीं जा रहे हैं. हालांकि सिसोदिया ने आगे ये कहा था कि जो भी मुख्यमंत्री बने, अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी होगी कि जो वादे किए जा रहे हैं उन्हें पूरा किया जाए. बहरहाल, पंजाब की जनता ने इस बार आम आदमी पार्टी को विपक्ष में रहने की जिम्मेदारी दी है. देखना है कि वे एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हैं या नहीं. ■

feedback@chauthiduniya.com

> पंजाब के लोगों ने बहुत बड़ा जनादेश दिया है. हमारी प्राथमिकता पंजाब से नशाखोरी समाप्त करने की होगी. मैंने चार सप्ताह में ड्रग्स कारोबार को उखाड़ फेंकने की प्रतिबद्धता जताई है. **-कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस**
>
> यह कांग्रेस का पुनर्जीवन है. यह तो बस शुरुआत है. कांग्रेस यहीं से आगे बढ़ेगी. **-नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस**
>
> जनता का फ़ैसला सर माथे पर. सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की. संघर्ष जारी रहेगा. **-अरविन्द केजरीवाल, संयोजक, आम आदमी पार्टी**
>
> हम हार की समीक्षा करेंगे. पर एक बात है जब भी कांग्रेस की सरकार आई है तब राज्य में करप्शन बढ़ा है. **-प्रकाश सिंह बादल, शिरोमणि अकाली दल**

प्रमुख चेहरे जीत/हार

जीत

कैप्टन अमरिंदर सिंह - पटियाला (कांग्रेस)
नवजोत सिंह सिद्धू- अमृतसर पश्चिम (कांग्रेस)
सुखबीर सिंह बादल- जलालाबाद (शिरोमणि अकाली दल)
प्रकाश सिंह बादल- लाम्बी (शिरोमणि अकाली दल)
बिक्रम सिंह मजीठिया - मजीठा (शिरोमणि अकाली दल)
मनप्रीत सिंह बादल- भटिंडा शहरी (कांग्रेस)

हार

भगवंत मान - जलालाबाद (आप)
जरनैल सिंह - लांबी (आप)
सुच्चा सिंह छोटेपुर - गुरदासपुर (अपना पंजाब पार्टी)

गोवा विधानसभा चुनाव परिणाम

न कांग्रेस हारी न भाजपा जीती

शफ़ीक़ आलम

पिछले विधानसभा चुनावों की भांति इस चुनाव में भी गोवा में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुक़ाबला रहा. इस बार भी छोटी-छोटी पार्टियां सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. अंतिम आंकड़ों पर नज़र डालें, तो 17 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जबकि भाजपा को 13 सीटें मिली हैं. महाराष्ट्रवादी गोमान्तक पार्टी (एमजीपी) को तीन, गोवा फॉरवर्ड पार्टी को तीन तथा निर्दलीय और अन्य को 4 सीटें मिली हैं.

चुनाव से ठीक पहले ही भाजपा को विद्रोह का सामना करना पड़ा था. राज्य के पूर्व आरएसएस प्रमुख सुभाष वेलिंगकर ने बगावत का झंडा उठा रखा था. वहीं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर द्वारा एमजीपी के दो मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने से भाजपा-एमजीपी का गठबंधन समाप्त हो गया था. शिव सेना के साथ भी भाजपा का चुनावी गठबंधन नहीं हो पाया था. यदि चुनावी आंकड़ों पर नज़र डालें, तो यह साफ़ हो जाता है कि भाजपा ने यदि एमजीपी के साथ अपना गठबंधन कायम रखा होता, तो वो सरकार बनाने की स्थिति में होती. 2012 में भाजपा को 21 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और एमजीपी को तीन सीटें मिली थीं. इस चुनाव में एमजीपी ने अपने तीन सीटों का आंकड़ा बरकरार रखा है. जहां तक वोट प्रतिशत का सवाल है, तो 32 फीसदी वोटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन ये वोट प्रतिशत नतीजों में नहीं बदल पाए और भाजपा बहुमत से दूर रह गई. कांग्रेस गोवा में 17 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है. वर्ष 2012 में कांग्रेस को यहां केवल 9 सीटें मिली थीं. इस लिहाज़ से यह एक अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन भाजपा में विद्रोह और सत्ता विरोधी लहर के हिसाब से देखें, तो कांग्रेस का प्रदर्शन और बेहतर होना चाहिए था. यदि कांग्रेस ने गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ अपना गठबंधन कर लिया होता, तो भाजपा की स्थिति और भी ख़राब होती. आम आदमी पार्टी, जिस पर सबकी नज़र थी, राज्य में कोई कारनामा नहीं कर पाई. उसे यहां एक भी सीट नहीं मिली. ऐसा कहा जा रहा था कि गोवा के चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी की मज़बूत उपस्थिति कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी. लेकिन चुनावी आंकड़ों को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि एक दो सीटों को छोड़ दिया जाए, तो आम आदमी पार्टी की मौजूदगी से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ. आम आदमी पार्टी को केवल 6.3 प्रतिशत वोट मिले. वहीं कांग्रेस को 28.4 प्रतिशत वोट मिले. हालांकि कांग्रेस को राज्य में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिली करारी शिकस्त के बीच पंजाब, गोवा और मणिपुर सांत्वना की तरह हैं.■

प्रमुख सीट और जीत/हार

सीट	जीत	हार	मार्जिन
मांड्रेम	दयानंद रघुनाथ सोप्ते (कांग्रेस)	लक्ष्मीकांत पार्सेकर (भाजपा)	7,119
नोवेलीम	लुईंजिन्हो फलेइरो (कांग्रेस)	अर्वेटानो फूर्टाडो (निर्दलीय)	2,478
मापूसा	डे पिन्टो ई सूजा (भाजपा)	विनोद फाड़के (एमजीपी)	6,828
मारकैम	रामकृष्ण धावालिकर(एमजीपी)	प्रदीप पंडलिक सेट (भाजपा)	13,860

किसे कितनी सीटें मिलीं

कांग्रेस	17
भाजपा	13
एनसीपी	01
एमजीपी	03
जीएफपी	03
अन्य	03

वोट और मत प्रतिशत

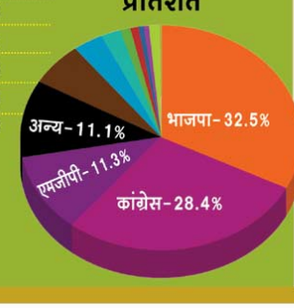

मणिपुर चुनाव परिणाम

इबोबी की सल्तनत में भाजपा की सेंध

60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में 2012 में कांग्रेस को 42 सीटें मिली थीं और इसने सरकार बनाई थी. लेकिन एक-एक कर ऐसी सियासी घटनाएं घटीं, जिनसे कांग्रेस जमीनी स्तर पर कमजोर होती गई. कुछ तो सरकार के फैसलों और कुछ अपनों की नाराजगी ने कांग्रेस को बहुमत से दूर कर दिया. सात नए जिलों का गठन और बिरेन सिंह एवं वाई इराबोत का भाजपा में शामिल होना ऐसे ही दो कारण हैं.

निरंजन मिश्रा

सियासी व सामाजिक उथल-पुथल के लिए जाना जाने वाला मणिपुर अब चुनावी परिणामों के जरिए चौंकाने वाले प्रदेश के रूप में भी जाना जाएगा. चुनावों से पहले और चुनावों के दौरान भी जो मुद्दे मणिपुर की हवा में छाए रहे, उनसे स्पष्ट ही नहीं हो पाया कि मणिपुर का मतदाता इवीएम के किस बटन पर उंगली दबाएगा. हालांकि भारी विकल्प बनने को चुनावी मैदान में उतरी शर्मिला, वोटों के मामले में खुद तिहाई का आंकड़ा भी नहीं छु पाई. चुनाव हारने के बाद शर्मिला को जनमत को स्वीकार करते हुए यह कहना पड़ा कि अब भविष्य में कभी भी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी.

नाकेबंदी ने कर दी वोटबंदी

60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में 2012 में कांग्रेस को 42 सीटें मिली थीं और इसने सरकार बनाई थी. लेकिन एक-एक कर ऐसी सियासी घटनाएं घटीं, जिनसे कांग्रेस जमीनी स्तर पर कमजोर होती गई. कुछ तो सरकार के फैसलों और कुछ अपनों की नाराजगी ने कांग्रेस को बहुमत से दूर कर दिया. सात नए जिलों का गठन और बिरेन सिंह एवं वाई इराबोत का भाजपा में शामिल होना ऐसे ही दो कारण हैं. नए जिलों के गठन वाले फैसले ने उस नगा समुदाय को पूरी तरह से कांग्रेस से दूर कर दिया, जिसकी राज्य में आबादी लगभग 30 प्रतिशत है. यह नगाओं की नाराजगी का ही नतीजा था कि उखरूल जिले में हॉस्पीटल का उद्घाटन करने गए सीएम इबोबी पर दिन दहाड़े गोली चली, जिसमें वे बाल-बाल बचे. 1 नवंबर से शुरू हुई नाकेबंदी आज भी जारी है और जनता सरकारी फैसले व नगा समर्थित अलगवावादी संगठनों के टकराव के बीच पीस रही है. यही कारण भी रहा कि जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और मोइरांग, चूराचांदपुर व हैरोक जैसी सीटों से भाजपा ने जीत दर्ज की, जो कांग्रेस का गढ़ रही हैं. कांग्रेस के लिए यह भी कम चिंतनीय नहीं है कि उसकी पारंपरिक सीट कही जाने वाली जीरीबाम से एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है. हालांकि इबोबी सिंह का सियासी परिवारवाद इस बार भी सफल हुआ है. वे खुद तो चुनाव जीते ही, उनके बेटे और भतीजे ने भी जीत दर्ज की है. उनकी पत्नी द्वारा खाली किए गए सीट खांगाबॉक से बेटे ओ सुरज कुमार ने 9,452 वोटों के अंतर से भाजपा के जदुमनी सिंह को हराया. वहीं, भतीजे ओ हेनरी सिंह ने वांगखेइ से भाजपा के इराबोत सिंह को 4,336 वोटों से मात दी. गौर करने वाली बात ये है कि इराबोत सिंह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया था.

बागी कांग्रेसी बना भाजपा का खेवैया

पूर्वोत्तर के ही असम में भाजपा की एंट्री में जो योगदान पूर्व कांग्रेसी हेमंत विश्वेशर्मा का था, वहीं रोल मणिपुर में नोंगथोमबम बिरेन सिंह का रहा. फुटबॉलर से पत्रकार और पत्रकार से राजनेता बने बिरेन सिंह ने न सिर्फ अपनी हैगांग सीट से भारी जीत दर्ज की बल्कि पूरे राज्य में भाजपा की विजय पताखा फहराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. लगातार तीन बार विधायक रहे इस पूर्व कांग्रेसी नेता ने अक्टूबर, 2016 में मुख्यमंत्री इबोबी सिंह के खिलाफ ही पार्टी में विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था. इसके बाद उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और फिर 17 अक्टूबर, 2016 को भाजपा का दामन थाम लिया. भाजपा ने भी उन्हें सर आंखो पर बिठाया और तुरंत ही पार्टी का प्रवक्ता व प्रदेश इकाई की चुनाव प्रबंधन समिति का सह-संयोजक बना दिया. चुनावी राजनीति के लिहाज से भाजपा के लिए पूरी तरह से नए इस राज्य में पार्टी के लिए जमीन बनाने के महत्वपूर्ण काम बिरेन सिंह ने ही किया.■

नहीं चला शर्मिला का जादू

किसी ने भी नहीं सोचा था कि डेड़ दशक से ज्यादा समय तक अपनी जिजीविषा और जुनून के आगे व्यवस्था को झुका देने वाली ये आयरन लेडी सियासत के मैदान में इस तरह से औंधे मुंह गिरेंगी. हैरानी की बात तो ये है कि जितने लोगों ने नोटा पर बटन दबाया उसका लगभग 1 प्रतिशत वोट ही शर्मिला को नसीब हो पाया. 18 अक्टूबर को जब इरोम शर्मिला ने राजनीति में आने और चुनाव लड़ने की घोषणा की, तो यह मणिपुर के साथ-साथ पूरे देश के लिए खुशखबरी थी. क्योंकि शर्मिला ने लगातार 16 साल तक अनशन कर के अफ्सपा का विरोध किया था. व्यवस्था में आकर व्यवस्था को बदलने का सपना न सिर्फ लोकतांत्रिक पद्धति को स्वीकृति थी, बल्कि शर्मिला का यह फैसला मणिपुर के लिए एक विकल्प भी था. हालांकि चुनाव परिणाम ने शर्मिला के सपने पर पानी फेर दिया. स्थानीय सियासी समीकरणों को समझने वालों का मानना है कि शर्मिला का अति आत्मविश्वास ही उनकी इस हार का कारण बना. पहली बात तो ये कि बिना फंड और बिना कैडर के उस राज्य में चुनाव लड़ना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, जहां एक दल पिछले 15 सालों से सत्ता में काबीज है. दूसरी बात ये है कि शर्मिला ने चुनाव लड़ने के लिए मुख्यमंत्री इबोबी सिंह की सीट का ही चुनाव किया. गौरतलब है कि इबोबी सिंह के विधानसभा क्षेत्र थौबाल की मणिपुर के बाकी क्षेत्रों के मुकाबले वही स्थिति है, जो सैफई की उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों की तुलना में. यही कारण भी है कि एक तरफ जहां ओकरम इबोबी सिंह को 18,649 वोट मिले, वहीं शर्मिला 90 वोटों पर सिमट गईं. न सिर्फ शर्मिला बल्कि उनकी पार्टी के अन्य उम्मीदवार भी बुरी तरह से हारे. मणिपुर के सियासी इतिहास में पहली बार चुनाव लड़ने वाली मुस्लिम महिला नजीमा बीबी ने तमाम कट्टपंथी सामाजिक संगठनों के विरोध को तो मात दे दिया, लेकिन चुनावी रण में नहीं टिक पाईं और उन्हें केवल छठा स्थान नसीब हुआ. वाबगाइ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी नजीमा बीबी को महज 33 वोट मिले, जबकि इस सीट से जीत दर्ज करने वाले कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद फजूर रहीम को 12,474 वोट मिले.

प्रमुख सीट और जीत/हार

सीट	जीत	हार	मार्जिन
थौबाल	इबोबी सिंह (कांग्रेस)	बसंता सिंह (भाजपा)	10,470
हैइंगांग	बिरेन सिंह (भाजपा)	शरत चंद्र सिंह (तृणमूल कांग्रेस)	1,206
नुंगबा	गाईखांगम (कांग्रेस)	आदिम पामै (भाजपा)	5,147
वांगखेइ	ओ हैनरी सिंह (कांग्रेस)	वाई रावत सिंह (भाजपा)	4,336

मतदान प्रतिशत ने यह तो संकेत दे ही दिया था कि इस बार कुछ अद्भूत होने वाला है. हर बार की सरकार विरोधी लहर के बाद भी अंत समय में जीत से बाजी पलट कर लगातार तीन बार से सत्ता पर काबिज होने वाली कांग्रेस भी इस बार बहुमत का आंकड़ा नहीं छु पाई. वहीं, वह भाजपा भी जादुई आंकड़े से दूर रह गई, जिसे उम्मीद थी कि नाकेबंदी और सत्ता विरोधी लहर उसे इस बार मणिपुर की सियासी वैतरणी पार करा देंगे. सबसे चौंकाने वाला नतीजा रहा इरोम शर्मिला की प्रजा पार्टी (पिपल्स रिसर्जेन्स एन्ड जस्टिस अलायंस) की शर्मिंदगी भरी हार. मणिपुर की पारंपरिक राजनीति और दलों का

किसे कितनी सीटें मिलीं

कांग्रेस	28
भाजपा	21
एनपीपी	04
एनपीएफ	04
लोजपा	01
तृणमूल कांग्रेस	01
अन्य	01

वोट और मत प्रतिशत

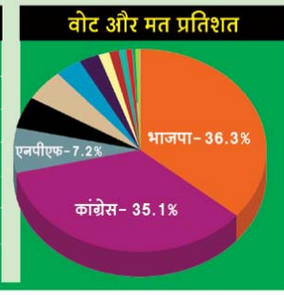

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

भाजपा और संघ पर भारी नरेंद्र मोदी

मेरी सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत देकर लोगों ने ये संकेत दे दिया है कि लोग विकास चाहते हैं. अब लोग सरकार चलाने के दौरान आपस का झगड़ा नहीं देखना चाहते हैं. यह बात अलग है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बहकावे में आ गए कि अगर केंद्र सरकार चलाने वाली पार्टी की सरकार बनती है तो विकास के लिए बहुत पैसे आएंगे. यह भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपगंडा था. यह राजनीति करने का दोषपूर्ण तरीका है. यह भारत की संघीय व्यवस्था और संविधान की भावना के खिलाफ है. जो भी हो, लोगों ने इस उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया क्योंकि उन्हें लगा कि बीजेपी के जीतने से उत्तर प्रदेश में काफी पैसा आएगा और विकास होगा. यही बात नरेंद्र मोदी ने कहा और यही अमित शाह भी दोहराते रहे. यही उम्मीद उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के दिमाग में भी रही.

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं. इन नतीजों से कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोग निराश, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं या आपकी सहानुभूति किस पार्टी के साथ है? जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी काफी लोकप्रिय हैं, नोटबंदी के फैसले को लोगों ने सराहा, मोदी की नीतियां अच्छी हैं, इस वजह से चुनावों के नतीजे ऐसे आए हैं. उसी तरह जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, वो कहेंगे कि बीजेपी ने खूब पैसा बहाया और पूरे तंत्र का दुरुपयोग किया. इसकी बिना परवाह किए कि कौन सा गुट क्या कहता है, कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं. पहली बात यह है कि एक्जिट पोल की प्रासंगिकता खत्म हो गई है. अब कुछ चैनल ये दावा करेंगे कि उनका अनुमान सही निकला, लेकिन बात ये नहीं है. सच्चाई यह है कि हर एक्जिट पोल अलग-अलग नतीजे बता रहा था और कोई भी एक्जिट पोल सही साबित नहीं हुआ.

ऐसे में नतीजों का विश्लेषण क्या हो? उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2007 में उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुजन समाज पार्टी को बहुमत दिया. वहीं 2012 में लोगों ने समाजवादी पार्टी और इस बार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत से जिताया है. यह साफ है कि लोगों के दिमाग में दो बातें थीं. एक यह कि लोग पहले देख चुके हैं कि किस तरह मिली-जुली सरकार में विधायकों की खरीद-बिक्री होती है. लोग इस तरह की राजनीति से थक चुके हैं इसलिए अब स्थायी सरकार चाहते हैं. उत्तर प्रदेश के लिए यह अच्छी बात है कि लोगों ने पांच साल मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी को चुना, फिर पांच साल के लिए समाजवादी पार्टी और अब पांच साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को शासन करने का मौका दिया. इस तरह की राजनीति से कोई नुकसान नहीं है.

मेरी सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत देकर लोगों ने ये संकेत दे दिया है कि लोग विकास चाहते हैं. अब लोग सरकार चलाने के दौरान आपस का झगड़ा नहीं देखना चाहते हैं. यह बात अलग है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बहकावे में आ गए कि अगर केंद्र सरकार चलाने वाली पार्टी की सरकार बनती है तो विकास के लिए बहुत पैसे आएंगे. यह भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपगंडा था. यह राजनीति करने का दोषपूर्ण तरीका है. यह भारत की संघीय व्यवस्था और संविधान की भावना के खिलाफ है. जो भी हो, लोगों ने इस उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया क्योंकि उन्हें लगा कि बीजेपी के जीतने से उत्तर प्रदेश में काफी पैसा आएगा और विकास होगा. यही बात नरेंद्र मोदी ने कहा और यही अमित शाह भी दोहराते रहे. यही उम्मीद उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के दिमाग में भी रही. दूसरी बात यह है कि एक्जिट पोल का अब कोई मायने नहीं रहा. लोग अब गठबंधन की राजनीति से तंग आ चुके हैं. यह एक तरह से अच्छी बात है. जो बातें उत्तर प्रदेश के लिए सही हैं, वही बातें उत्तराखंड में भी लागू होती हैं क्योंकि दोनों जगहों के लोग एक ही तरह के हैं.

इस चुनाव से दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सामने आई है, वो यह कि कांग्रेस मुक्त भारत की बातें बेमानी हैं. पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा. गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रही. हालांकि ये दोनों छोटे राज्य हैं और राष्ट्रीय राजनीति में इनका कोई असर नहीं है, फिर भी इन दोनों राज्यों के लोगों ने उस घातक कल्पना को दफना दिया, जो

> **उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह तय करना भारतीय जनता पार्टी की अगली चुनौती है. उन्हें किसी परिपक्व व्यक्ति को चुनना चाहिए, जो राज्य का शासन चला सके. लेकिन अभी मथुरा के विधायक या किसी और का नाम जो अमित शाह के करीबी हैं, चल रहा है. हैरानी यह है कि राजनाथ सिंह, उमा भारती या उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे कैबिनेट मंत्री का कोई नाम नहीं ले रहा है. कोई किसी परिपक्व व्यक्ति का नाम ले ही नहीं रहा है. यह बहुत बड़ी गलती होगी.**

सिद्धांततः देश में एक ही पार्टी का शासन यानी एकसत्तावाद स्थापित करना चाहता है.

पंजाब में एक तीसरी पार्टी इस आशा के साथ चुनाव में कूदी कि लोग दोनों पार्टियों को अस्वीकार कर उन्हें चुन लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री के रूप में पांच साल तक अच्छा शासन दिया था. उसके बाद यहां दस साल तक प्रकाश सिंह बादल का शासन रहा. पंजाब में लोगों ने एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व पर भरोसा जताया है.

जहां तक इन चुनावों से सीख लेने की बात है, तो हमें राजनीतिक तौर पर पहले से ज्यादा परिपक्व होने की जरूरत है. लोगों से हर बार झूठे वादे कर वोट लेना या वोट की खातिर उत्साह में आकर बड़े-बड़े वादे करने से किसी भी राज्य का भला नहीं होने वाला है.

अब न तो भारतीय जनता पार्टी है और न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, सिर्फ एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी. उनका हर फैसला अब अंतिम फैसला है. हकीकत तो यह है कि इस बार संघ ने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने से मना कर दिया था. हालांकि, इससे मोदी का हाथ और भी मजबूत हुआ है. अब नरेंद्र मोदी ये दावा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जीत, उनकी व्यक्तिगत जीत है क्योंकि किसी ने उनकी मदद नहीं की.

उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह तय करना भारतीय जनता पार्टी की अगली चुनौती है. उन्हें किसी परिपक्व व्यक्ति को चुनना चाहिए, जो राज्य का शासन चला सके. लेकिन अभी मथुरा के विधायक या किसी और का नाम जो अमित शाह के करीबी हैं, चल रहा है. हैरानी यह है कि राजनाथ सिंह, उमा भारती या उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे कैबिनेट मंत्री का कोई नाम नहीं ले रहा है. कोई किसी परिपक्व व्यक्ति का नाम ले ही नहीं रहा है. यह बहुत बड़ी गलती होगी. उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को शासन चलाने का मौका मिला है. उन्हें किसी परिपक्व व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुनना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वीकार्य हो और जो सभी को साथ लेकर चलने में भी सक्षम हो. यह बात सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश जाति, उप-जाति, वर्ग और धर्म में इतनी बुरी तरह बंटा हुआ है कि अगर मुख्यमंत्री परिपक्व न हो तो राज्य का भला नहीं हो सकता है.

भारतीय जनता पार्टी इस तरह की गलती पहले भी कर चुकी है. गोवा से उन्होंने परिकर को उठाकर रक्षा मंत्री बना दिया. वो एक बुरे रक्षा मंत्री साबित हुए. अब गोवा में लोग उन्हें वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं. ये अच्छी बात होगी, अगर उन्हें वापस गोवा भेज दिया जाए. वैसे यह पार्टी का आंतरिक मामला है और किसी बाहरी को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जब हम लोगों की भलाई, प्रशासन और राज्य की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो हमें तर्कपूर्ण बातें तो करनी ही पड़ेंगी. चुनाव के नतीजे हाल में आए हैं. विपक्षी पार्टियां क्या करती हैं या भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती है, इसके लिए हमें कुछ सप्ताह इंतजार करना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

फारूक अब्दुल्ला के बयान का मतलब

शुजात बुखारी

वर्ष 1996 में जब भारत सरकार को जम्मू-कश्मीर की निर्वाचन प्रक्रिया को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त चेहरे की तलाश थी, तब ऐसे में उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला के अलावा अन्य कोई नाम नहीं सूझा. फारूक अब्दुल्ला उस समय अपरिहार्य हो गए थे, जब एक शीर्ष अलगाववादी नेता ने इस आग में अपने हाथ जलाने से इंकार कर दिया था, हालांकि इससे पहले सौदा पक्का हो गया था. सरकार का एक अन्य विकल्प बदनाम काउंटर-इंसर्जेंसी नेता कूका परे थे, जो सामाजिक तौर पर पहले से ही बहिष्कृत थे. मज़े की बात यह है कि जिस विधानसभा चुनाव के बाद फारूक अब्दुल्ला की मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी हुई, उसी चुनाव में परे सोनावारी क्षेत्र से चुनकर विधानसभा पहुंचे. फारूक अब्दुल्ला अपने 1987-89 के उथल पुथल भरे शासन काल में सशस्त्र विद्रोह के बाद कश्मीर से भाग गए थे. इसके बाद वे बिना किसी राजनीतिक रियायत के चुनावी रथ पर सवार होने के लिए तैयार नहीं थे. उनकी सबसे बड़ी मांग अधिक स्वायत्तता बहाल करने की थी.

फारूक को राजी कर लिया गया क्योंकि नई दिल्ली ने कश्मीर में अपना विश्वास खो दिया था. तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के स्वायत्तता को लेकर स्काई इज दी लिमिट (यानी मामले में बहुत कुछ किया जा सकता है) वक्तव्य के बाद ही वे राजी हुए थे. गौरतलब है कि उनकी पार्टी ने मई 1996 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था और राज्य की राजनीतिक स्थिति बहाल करने के आश्वासन पर अड़ी थी. फारूक को मुख्यधारा की राजनीति में बिल्कुल उसी तरह से शामिल कर लिया गया था, जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने उनके पिता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 1975 में शामिल किया था. उसमें एकमात्र अंतर यह था कि शेख अब्दुल्ला को इंदिरा गांधी जैसे नेता ने संभाला था, जबकि फारूक को राज़ी करने वाले नेता का राजनीतिक क़द उतना बड़ा नहीं था. 1996 से 2002 के अपने कार्यकाल के दौरान फारूक ने दिल से भारतीय होने की मिसाल पेश की. उन्होंने न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों द्वारा खास तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) की कार्रवाईयों की तरफ से आंखें बंद रखीं, बल्कि कश्मीर में सामान्य स्थिति की बहाली के नाम पर या दूसरे शब्दों में कहें तो भारत की संप्रभुता की रक्षा के नाम पर होने वाले सभी गलत कामों को भी स्वीकार कर लिया.

अपने संपूर्ण कार्यकाल के दौरान फारूक अब्दुल्ला का तर्क था कि आतंकवाद से सख्ती से निपटो, पाकिस्तान पर बमबारी करो. फारूक का ये भी कहना था कि उनके द्वारा प्रशासित कश्मीर में आतंकवाद केवल पाकिस्तान से आता है. ये बातें उन्होंने 20 अक्टूबर 2001 को जम्मू में कही थीं. फारूक ने अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में पत्रकारों से कहा था कि अगर 11 सितंबर के हमलों के बाद अमरीका अफगानिस्तान पर हमला कर सकता है, तो हम पाकिस्तान से संचालित आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते हैं?

अब समय आ गया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से संचालित आतंकवादी संगठनों और प्रशिक्षण शिविरों के खिलाफ सेना कार्रवाई करे. जम्मू और कश्मीर ने पिछले 12 सालों में बहुत रक्तपात देखा है. हमारी धैर्य की क्षमता अब समाप्त हो गई है. समय आ गया है कि पूरी शक्ति और जोश के साथ पीओके के प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट कर दिया जाए.

दरअसल, 2002 के विधानसभा चुनावों में यही बयान उनकी हार का कारण बना था क्योंकि लोगों को उनका पाकिस्तान विरोधी बयान अच्छा नहीं लगा था. नरसिंह राव के स्वायत्तता पर विचार के वादे और फिर प्रधानमंत्री देवगौड़ा सरकार के आश्वासन के बाद भी वे अनुकूल परिस्थिति में इस मुद्दे को उठाना भूल गए. यह वह अवसर था, जब विधानसभा ने बहुमत के साथ यह प्रस्ताव पारित कर दिया था, लेकिन वर्ष 2000 में केंद्र में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसे खारिज कर दिया था. वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि 1984 में कांग्रेस द्वारा उनकी सरकार के खिलाफ करवाए गए विद्रोह की पुनरावृत्ति हो. उन्हें अक्सर यह कहते हुए सुना गया कि अगर जम्मू-कश्मीर में सत्ता में बने रहना है, तो आपको केंद्र के साथ रहना पड़ेगा. इसका पालन स्पष्ट रूप से सभी मुख्यमंत्रियों ने किया, जिनमे उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद और अब उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं. गुलाम नबी आजाद को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वे केंद्र से और केंद्र के ही व्यक्ति थे.

आकर्षक व्यक्तित्व, स्पष्टवादी रुख और बेझिझक अपनी बात कहने की आदत ही फ़ारूक को राजनीति में अलग खड़े करती है. चाहे हवा का रुख किसी भी तरफ हो, वे स्पष्ट रूप से नई दिल्ली के लिए एक मूल्यवान व्यक्ति थे. 2010 में उनके शासनकाल के दौरान राज्य में अशांति फैली थी. इसके बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फारूक अब्दुल्ला बीमारी की वजह से लन्दन में नहीं पड़े होते और चुनाव अभियान में हिस्सा लिया होता तो 2014 के चुनाव में नेशनल कांफ्रेंस की स्थिति बेहतर होती. यह एक तथ्य है कि उनके स्वभाव में परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होता रहता है. वे 1974 में मिरपुर में जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के सदस्य के रूप में शपथ भी ले सकते हैं और बाद में मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं.

> **दरअसल, 2002 के विधानसभा चुनावों में यही बयान उनकी हार का कारण बना था क्योंकि लोगों को उनका पाकिस्तान विरोधी बयान अच्छा नहीं लगा था. नरसिंह राव के स्वायत्तता पर विचार के वादे और फिर प्रधानमंत्री देवगौड़ा सरकार के आश्वासन के बाद भी वे अनुकूल परिस्थिति में इस मुद्दे को उठाना भूल गए. यह वह अवसर था, जब विधानसभा ने बहुमत के साथ यह प्रस्ताव पारित कर दिया था, लेकिन वर्ष 2000 में केंद्र में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसे खारिज कर दिया था. वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि 1984 में कांग्रेस द्वारा उनकी सरकार के खिलाफ करवाए गए विद्रोह की पुनरावृत्ति हो.**

फिलहाल एक लंबे समय से उन्होंने अपना रुख नहीं बदला है और एलओसी को अंतरराष्ट्रीय सीमा में बदलने के बारे में लगातार बोलते रहे हैं. कश्मीर के संदर्भ में किसी भी नेता और पार्टी के विचार सत्ता में रहने या सत्ता से बाहर रहने के संदर्भ में तय होते हैं. स्टेट टेररिज्म के शिकार लोगों के साथ सहानुभूति दिखाना और कश्मीर से संबंधित प्रस्तावों के बारे में बात करना सत्ता से बाहर रहने वाले नेताओं का पसंदीदा कार्य है. लेकिन फारूक अब्दुल्ला का हालिया बयान केवल चुनाव के लिए ही नहीं है. दिसंबर 2016 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के समर्थन में उनका बयान और यह बताना कि मिलिटेंट्स आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, गंभीर बातें हैं.

अब ज़रा देखिए कि उन्होंने फरवरी में क्या कहा? विधायक या मंत्री बनने के लिए हमारे युवा अपनी जान नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वे ऐसा कर रहे हैं. यह हमारी ज़मीन है. यहां के युवाओं ने एक रास्ता चुना है और उन्होंने खुदा से वादा किया है केवल वही ज़िंदगी देने और लेने वाला है, लेकिन हम इस राष्ट्र की आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान करेंगे ... आज एक नया राष्ट्र (जम्मू-कश्मीर) तैयार है, वह राष्ट्र जो बंदूक से नहीं डरता है और जो आजादी के लिए निकल पड़ा है. उन्होंने कोई ठोस काम करने के लिए बंदूक उठाया है. हमें यह देखने की ज़रूरत है कि बंदूकों को कैसे खामोश किया जाए. बंदूक उठाने वाले युवक न तो भारत के दुश्मन हैं और न ही पाकिस्तान के.

फारूक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के बारे में भारत के एक राज्य की तरह नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में बात कर रहे हैं. वे मिलिटेंट्स की प्रशंसा स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में कर रहे हैं, जिन्हें कुचलने के लिए कभी उनकी सरकार ने अभियान चलाया था.

बहुत से लोग फारूक के इस गुस्से को आगामी लोकसभा चुनावों से जोड़ कर देखते हैं, जिसमें उनके चुनाव लड़ने की संभावना है. लेकिन यह उतना सरल नहीं है, जितना दिखता है. नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक ने पूर्व में इन राजनैतिक भावनाओं का लाभ उठाया है, लेकिन इस बार वे जो कह रहे हैं, उसे उन्होंने देखा है. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2016 के हिंसक विरोध के दौरान खुद को संभाले रखने में बहुत सावधानी बरती है. यदि फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग कश्मीर की नई हकीकत के मुताबिक बात कर रहे हैं, तो यह नई दिल्ली के लिए एक संदेश है कि कैसे उसने स्थिति का गलत आकलन किया है और ये अब भी सोचती है कि मस्जिद, मदरसा, मीडिया और विभिन्न संप्रदायों के खुफिया ऑपरेशन के जरिए स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकता है. यदि फारूक अब्दुल्ला मिलिटेंट्स को फ्रीडम फाइटर कहने पर मजबूर हैं तो उन्हें आतंकवादी कौन कहेगा? यह दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह है, इसे पढ़ने के लिए आवश्यकता है तो बस एक चश्मे की. ■

–लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

इस चुनावी हार से सीख लेने की जरूरत है

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली अप्रत्याशित जीत अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस को बहुत परेशान कर रही होगी. असल में पहली गलती अखिलेश यादव की है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में महागठबंधन नहीं बनाया. अब अखिलेश यादव को इस बात का एहसास होगा कि अगर पार्टी में सही लोग नहीं हों, तो वे आपको वैसी ही खबरें देंगे, जो आपको अच्छी लगती हों. अगर आप इंटेलीजेंस एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपको वैसी ही खबरें मिलेंगी, जैसी आप सुनना चाहते हैं. आपको सत्य नहीं मिलता है. ये बहुतों के साथ बहुत बार हुआ है. अटली जी, मनमोहन जी और उसके पहले नरसिम्हा राव के साथ हुआ, पर हर व्यक्ति यह गलती दोहराता ही है. इसके बावजूद अखिलेश यादव अगर बिहार से सीख लेकर अति उत्साह में नहीं होते या दूसरे शब्दों में, अहंकार में नहीं होते, तो वे अपने साथ अजित सिंह, नीतीश कुमार और छोटे-छोटे दलों को भी रखते, जिनमें पीस पार्टी का नाम प्रमुख है. फिर देखते कि वे उत्तर प्रदेश में किस तरह दोबारा सत्ता पर काबिज होते. उन्होंने चुनाव के बाद मायावती जी का साथ लेने का ऐलान किया, लेकिन अगर यही वो पहले कर लेते तो जो वोट मिले हैं, वो ये बताते हैं कि उस समय अखिलेश यादव बहुत बड़े बहुमत में होते.

कांग्रेस, सपा और बसपा के कुल मिले वोटों को जोड़ दें, तो ये बीजेपी को मिले वोट से बहुत अधिक हैं, यानी कांग्रेस सपा गठबंधन के साथ अगर बसपा भी होती, तो मुमकिन है कि आज रिजल्ट बिल्कुल अलग होता. अगर इसमें अजित सिंह और नीतीश कुमार भी होते, तब तो यह कोई युद्ध था ही नहीं. चुनाव आयोग ने शाम चार बजे तक जो आंकड़े जारी किए, उसके मुताबिक बीजेपी को यूपी चुनाव में सिर्फ 39.6 फीसद वोट मिले हैं, जबकि बीएसपी को बेहद कम सीट मिलने के बावजूद 22 फीसद वोट मिले हैं. दूसरी ओर सपा को 21.9 फीसद और कांग्रेस को 6.3 फीसद लोगों ने वोट दिए. हालांकि, वोट बंट जाने की वजह से अधिकांश सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है. ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो कुल 50 फीसद वोट एक जगह हो सकते थे.

बिहार में एक-दूसरे के बेहद विरोधी रहे लालू यादव और नीतीश कुमार चुनाव के वक्त साथ हो गए थे. 2015 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने कांग्रेस के साथ एक महागठबंधन तैयार किया था. इस वजह से बीजेपी को 24 फीसद वोट तो मिले थे, लेकिन

> चुनाव के दौरान भाषा का छिछलापन, भाषा की अभद्रता, तरह-तरह के वादे हमें देखने को मिले, लेकिन ये सारी चीजें कम से कम लोकतांत्रिक तो नहीं थीं. उत्तर प्रदेश का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक और कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के लिए घोर अलोकतांत्रिक रहा. कांग्रेस को यह समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी के चुनाव प्रचार करने और गठबंधन के बावजूद उनके पास सिर्फ 7 सीटें कैसे आईं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस इसका कोई भी विश्लेषण नहीं करेगी. न ही इस हार से कोई सीख लेगी और न अपने उन लोगों को याद करेगी, जो राजनीति में निष्णात हैं.

सीटें नहीं मिल पाई थीं. आरजेडी का 18 फीसद, जद यू का 16 फीसद और कांग्रेस का 6 फीसद वोट एक साथ होने की वजह से उन्हें 178 सीटें मिल गई थीं. दूसरी ओर एनडीए के पास 58 सीटें आई थीं. ऐसे में यूपी चुनाव का ऐतिहासिक रिजल्ट अब मायावती और अखिलेश को साथ न आने की गलती का एहसास करा सकता है, लेकिन कहावत तो वही है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत.

इन गलतियों के बाद भी मुसलमानों के बीच का कन्फ्यूजन, चुनाव में राहुल गांधी का जनता से पूरी तौर पर संवाद स्थापित न कर पाना, चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के भीतर एक मैकेनिज्म का न बन पाना, इन कारणों ने कार्यकर्ताओं को साथ नहीं आने दिया. दूसरा, कांग्रेस पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव का मंच शेयर नहीं करते थे, मंच पर हिस्सेदारी नहीं करते थे, यद्यपि उन्हें पास भेजे जाते थे. कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को यह निर्देश दिया था कि वो वहीं मीटिंग में जाएं, जहां अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त रैली हो. इस फैसले ने कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने नहीं दिया.

महान स्ट्रैटिजिस्ट श्री प्रशांत किशोर, जिनकी मार्केटिंग नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव के बाद की, ने जिस तरीके से प्रियंका और राहुल गांधी को मूर्ख बनाया, उसका कोई जवाब नहीं है. उन्होंने प्रियंका गांधी से कहा था कि कांग्रेस को 77 के आस-पास सीटें आएंगी. इस पर प्रियंका गांधी ने भी विश्वास कर लिया और सारी रणनीति प्रशांत किशोर के कहने पर बनाई. यहां पर कांग्रेस के नेताओं को यह समझ में नहीं आया कि राजनीतिक कार्यकर्ता और पीआर एजेंसी चलाने वाले में कितना अंतर होता है. पीआर एजेंसी चलाने वाला पैसे लेकर काम करता है, जबकि राजनीतिक वर्कर अपना खून देकर काम करता है. कांग्रेस ने अपने नेताओं, पॉलिटिकल वर्कर्स पर कोई भरोसा नहीं किया. प्रशांत किशोर के कहने से उन्होंने अखिलेश यादव से समझौता किया. नतीजे के तौर पर पूरी कांग्रेस पार्टी, उसके सारे कार्यकर्ता, कुछ चंद नेताओं को छोड़ दें, सब अपने घर बैठ गए. राजनेताओं को समझना चाहिए कि वो पांच साल जो प्रचार करते हैं, वो आखिरी एक महीने में नहीं बदला जा सकता. लोगों के पास वो बात बहुत गंभीरता से पहुंच चुकी होती है.

शायद प्रियंका गांधी को यही डर लगा होगा, जिसके कारण उन्होंने चुनाव में कांग्रेस का प्रचार नहीं किया. कांग्रेस का छोड़ दीजिए, उन्होंने अमेठी और रायबरेली में भी प्रचार नहीं किया. अमेठी और रायबरेली की सीटें भी भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्या में जीत गई. यहां तक कि संजय सिंह के सिर्फ अमेठी में चुनाव प्रचार में लगे रहने के बावजूद वो अपनी पत्नी अमिता सिंह को चुनाव नहीं जिता पाए.

चुनाव के दौरान भाषा का छिछलापन, भाषा की अभद्रता, तरह-तरह के वादे हमें देखने को मिले, लेकिन ये सारी चीजें कम से कम लोकतांत्रिक तो नहीं थीं. उत्तर प्रदेश का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक और कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के लिए घोर अलोकतांत्रिक रहा. कांग्रेस को यह समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी के चुनाव प्रचार करने और गठबंधन के बावजूद उनके पास सिर्फ 7 सीटें कैसे आईं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस इसका कोई भी विश्लेषण नहीं करेगी. न ही इस हार से कोई सीख लेगी और न अपने उन लोगों को याद करेगी, जो राजनीति में निष्णात हैं. अखिलेश यादव तो ये मान बैठे हैं कि उन्हें हराने में शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव का बहुत बड़ा हाथ है. उन्हें चाहिए कि वे अपने पिताजी के पास जाएं और उनकी सलाह से की हुई गलतियों को सुधारें. उनके पास उम्र है, लेकिन उन्हें थोड़ा समाजवाद व आंदोलनों के बारे में भी समझना चाहिए और लोगों को पहचानने की कला आनी चाहिए. अहंकार होता है, लेकिन इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि वो आपके राजनीतिक भविष्य पर ही अवरोध खड़े करने लगे. उत्तर प्रदेश का चुनाव सारी पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को भी सीख देता है कि अगर आप बड़बोलापन करेंगे, काम नहीं करेंगे, लोगों को झूठे सपने दिखाएंगे, झूठ बोलेंगे, अहंकार करेंगे, तो आपके लिए अगला विधानसभा चुनाव भले ही मुश्किल न हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में आप वो नहीं कर पाएंगे, जो आपके प्रधानमंत्री आपसे अपेक्षा करते हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

आर या पार

नफरत को सरकारी समर्थन

भारत और अमेरिका में सरकार खुद नफरत को हवा दे रही है

यह बड़ा अजीब लगता है कि जो सरकार खुद अपने यहां नफरत पैदा करने वाले अपराधों को रोक नहीं पा रही है, वह अमेरिकी सरकार को ऐसे ही अपराधों को रोकने की नसीहत दे रही है. वह भी सिर्फ इसलिए कि ऐसे ही एक अपराध में जान गंवाने वाला व्यक्ति भारतीय है. 22 फरवरी को श्रीनिवास कुछिभोतला की कन्सास में एक श्वेत व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्यारा यह चिल्ला रहा था कि भारतीय मेरे देश से बाहर चले जाएं. इस घटना के हफ्ते भर बाद तक अमेरिकी सरकार की ओर से इसकी निंदा का कोई बयान नहीं आया. व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सिन स्पाइसर ने घटना को 'परेशान करनेवाला' मानने के अलावा कुछ नहीं कहा. 28 फरवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए इस घटना का जिक्र अपने भाषण के शुरू में ही किया. भारतीय मीडिया ने इसके बाद यह दावा करना शुरू कर दिया कि ट्रम्प ने कन्सास घटना की निंदा की है, जबकि ट्रम्प ने इसका हल्का जिक्र भर किया था. ट्रम्प ने कहा था कि यहूदी समाज के लोगों के खिलाफ होने वाली हिंसक घटनाएं और कन्सास की घटना हमें इस बात की याद दिलाती हैं कि नीतियों के स्तर पर भले ही हमारा देश बंटा हुआ दिखता हो, लेकिन नफरत और बुराइयों की निंदा में एकजुट रहता है. ट्रम्प ने यह नहीं कहा कि उनकी नीतियों की वजह से इस तरह की घटनाओं के लिए माहौल बना है. अमेरिका समेत कोई भी देश ऐसा नहीं है, जो विभिन्न समुदायों के बीच आपसी पूर्वग्रह से पूरी तरह मुक्त हो. हर देश में सरकारें इन भावनाओं को नीतियों समेत कई उपायों से बरकरार रखने की कोशिश करती हैं.

आज जो अमेरिका में हो रहा है, वही सब

पिछले ढाई साल में भारत में हुआ है. मई, 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है. तब से नफरत पैदा करने वाले अपराध बढ़ गए हैं और जान-बूझकर मुस्लिम समाज के लोगों को अलग-थलग करने की कोशिश शुरू हुई है. कभी लव जिहाद का मुद्दा उठाया जाता है तो कभी कुछ और. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा सांप्रदायिक मुद्दे उठाए गए. इससे मुस्लिमों में भारतीय समाज में अपनी स्थिति को लेकर असुरक्षा का माहौल बढ़ रहा है. ऐसा किसी छोटे समूह या कुछ छिटपुट लोगों की वजह से नहीं हो रहा है. ऐसा तब होता है जब शीर्ष स्तर से यह संदेश जाए कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ भी करने पर न तो उसकी निंदा की जाएगी और न ही उन पर कोई कार्रवाई होगी. उत्तर प्रदेश के दादरी में मोहम्मद अखलाक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. जब भी कोई ऐसी घटना होती है, शीर्ष स्तर पर बहुत अधिक शांति दिखती है. ट्रम्प ने थोड़ा ही सही, लेकिन जो कहा है, वह भी ऐसे अपराधों के बाद मोदी के अब तक के कहे से बहुत अधिक है.

भारत और अमेरिका में जो हो रहा है, उनकी आपसी तुलना यहीं खत्म नहीं होती है. 'राष्ट्र' की परिभाषा को लेकर भी बहुत कुछ चल रहा है. ट्रम्प अक्सर अमेरिका को फिर से महान बनाने की बात करते हैं, लेकिन यह अमेरिका है क्या? क्या इस अमेरिका में कई देशों से आए लोगों के लिए, जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, कोई जगह है? या फिर उन्हें अमेरिका को फिर से महान बनाने की राह में रोड़ा माना जाएगा? जिस भाषण में ट्रम्प ने कन्सास की घटना का जिक्र किया, उसी में उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाने का प्रस्ताव रखा, जो दूसरे देशों से आए लोगों द्वारा किए गए अपराधों से प्रभावित अमेरिकी नागरिकों के हितों के लिए काम करेगा. उन्होंने दूसरे देशों से आए लोगों द्वारा पुलिसकर्मियों के मारे जाने की कई घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन यह नहीं बताया कि जिन्हें वे अमेरिकी मानते हैं, उन्होंने कितनी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है. 'अप्रवासी' शब्द का इस्तेमाल कर वे उसी तरह के लोगों के हाथों में खेल रहे थे, जिनमें से एक ने कन्सास की

> आज जो अमेरिका में हो रहा है, वही सब पिछले ढाई साल में भारत में हुआ है. मई, 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है. तब से नफरत पैदा करने वाले अपराध बढ़ गए हैं और जान-बूझकर मुस्लिम समाज के लोगों को अलग-थलग करने की कोशिश शुरू हुई है. कभी लव जिहाद का मुद्दा उठाया जाता है तो कभी कुछ और. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा सांप्रदायिक मुद्दे उठाए गए. इससे मुस्लिमों में भारतीय समाज में अपनी स्थिति को लेकर असुरक्षा का माहौल बढ़ रहा है.

घटना को अंजाम दिया था. ऐसे लोगों के लिए जिसकी चमड़ी का रंग अलग हो, जो अलग दिखता हो या कोई दूसरी भाषा बोलता हो, वह अमेरिका के लिए खतरा है.

भारत में भी मौजूदा सरकार ने अपने हिसाब से 'राष्ट्र' और 'राष्ट्रवाद' का एजेंडा तय कर रखा है. जहां एक तरफ सभी भारतीय 'हिन्दू राष्ट्रवादी' हैं, वहीं भारतीय मुसलमानों को यह साबित करना है कि वे 'राष्ट्रवादी' हैं. इसके अलावा वे सभी लोग 'राष्ट्र विरोधी' हैं, जो सरकार और उसकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं, कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करते हैं, कश्मीर, पूर्वोत्तर या बस्तर में सुरक्षाकर्मियों की ज्यादतियों की आलोचना करते हैं और जो यह कहते हैं कि विरोध जताने का अधिकार भी अभिव्यक्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ है. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में जो कुछ हुआ, उसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू अति वामपंथियों और राष्ट्रवादियों के बीच विचारधारा के संघर्ष के तौर पर देखते हैं. इस हिसाब से तो सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य ही राष्ट्रवादी हैं.

भारत सरकार और अमेरिकी सरकार अपने-अपने यहां गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं. भारत में विद्यार्थी परिषद को राष्ट्रवाद का अपना संस्करण थोपने की खुली छूट दी जा रही है. वहीं अमेरिका में हथियारबंद लोगों को उन लोगों को मारने तक की छूट दी जा रही है, जो कथित रूप से अमेरिका के लिए 'खतरा' हैं. ऐसी सरकारें न सिर्फ नफरत को हवा देने का काम करने के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि ये सहिष्णुता और संवाद की संभावनाओं को भी तबाह कर देती हैं. ■

(साभार इकोनॉमिक एंड पॉलीटिकल वीकली)

feedback@chauthiduniya.com

जलील मस्तान की अमर्यादित टिप्पणी पर बाधित रहा बिहार विधानमंडल

हंगामों के बीच जन आकांक्षाओं की गूंज नहीं

भाजपा के नेताओं ने घोषणा कर दी कि मंत्री की बर्खास्तगी के बगैर वे विधानमंडल चलने नहीं देंगे. सप्ताह के शेष दिनों में सदन की कार्यवाही ठप रही. मस्तान प्रकरण के पहले विपक्ष ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न-पत्र लीक घोटाला का मसला उठाए रखा. इस प्रकरण की सीबीआई जांच पर जोर दिया, तो मुख्यमंत्री ने सीबीआई को सौंपे गए मामलों की बदहाली का ब्योरा देते हुए इस मांग को खारिज कर दिया. इस मसले पर विपक्ष के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसके आधार पर सत्ता पक्ष को घेरा जा सके. उसने बड़ी मशक्कत से एक एसएमएस ऊपर किया, जो विधानसभा के स्पीकर के निजी सहायक का था. यह एसएमएस पिछले महीने एएनएम की भर्त्ती के संदर्भ में किसी की पैरवी के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) के तत्कालीन अध्यक्ष (अब गिरफ्तार) सुधीर कुमार को भेजा गया था. वस्तुतः विपक्ष उन तथ्यों का भी जुगाड़ नहीं कर सका, जिनके संकेत एसआईटी से पूछताछ के दौरान मिले थे. विपक्ष के इस सूचना-दारिद्र्य का लाभ सत्ता पक्ष ने उठाया.

सरोज सिंह

बिहार विधानमंडल के मौजूदा बजट अधिवेशन के दौरान सत्ता पक्ष के कई काम निपटे, पर बिहार की जन आकांक्षा और जन समस्याओं की गूंज-अनुगूंज सुनने के अवसर नहीं मिले. इस दौरान जनता के सवालात के अलावा सब कुछ छाया रहा. विपक्ष के हंगामे हुए, सदनों के भीतर अस्त-व्यस्तता रही, दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित हुई. हालात सुधारने के स्पीकर के प्रयास बार-बार विफल हुए. इसके बावजूद राज्यपाल के अभिभाषण और उस पर चर्चा हुई. वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया गया और वित्त मंत्री व शिक्षा मंत्री के भाषण हुए. लब्बोलुबाब यह कि सरकार के काम तो निकले या उन्हें निकलने दिया गया, पर जन आकांक्षाओं और समस्याओं को जन-प्रतिनिधियों ने अपनी राजनीति से बाहर रखा.

विधानमंडल के बजट अधिवेशन की शुरुआत 23 फरवरी को हुई थी. परंपरा के अनुरूप कैलेंडर वर्ष के पहले कामकाजी दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है. सो उस दिन राज्यपाल रामनाथ कोविंद के शांतिपूर्ण अभिभाषण के बाद कुछ औपचारिक काम हुए. इसके बाद अगले हफ्ते के पहले दिन वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी का कोई बीस मिनट का बजट भाषण हुआ. राज्यपाल के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री के भाषण भी हुए, पर एक मार्च से अब्दुल जलील मस्तान प्रकरण ने दोनों सदनों को अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद तीन दिनों तक यह मसला छाया रहा. महागठबंधन सरकार में कांग्रेस कोटे के मद्यनिषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने पूर्णिया जिले के अमौर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की, साथ ही प्रधानमंत्री की तस्वीर पर लोगों को जूते-चप्पल बरसाने के लिए उकसाया भी. विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो निंदा की ही, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व राज्य के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी और कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने भी कड़े शब्दों में निंदा की. खुद अब्दुल जलील मस्तान ने अपने आचरण के लिए सार्वजनिक तौर पर खेद जताया, लेकिन भाजपा और एनडीए के उसके सहयोगी दल मंत्री के इस्तीफे या उनकी बर्खास्तगी से कम पर मानने को तैयार नहीं थे. अपनी मांग को लेकर वे राज्यपाल के पास भी गए.

भाजपा के नेताओं ने घोषणा कर दी कि मंत्री की बर्खास्तगी के बगैर वे विधानमंडल चलने नहीं देंगे. सप्ताह के शेष दिनों में सदन की कार्यवाही ठप रही. मस्तान प्रकरण के पहले विपक्ष ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न-पत्र लीक घोटाला का मसला उठाए रखा. इस प्रकरण की सीबीआई जांच पर जोर दिया, तो मुख्यमंत्री ने सीबीआई को सौंपे गए मामलों की बदहाली का ब्योरा देते हुए इस मांग को खारिज कर दिया. इस मसले पर विपक्ष के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसके आधार पर सत्ता पक्ष को घेरा जा सके. उसने बड़ी मशक्कत से एक एसएमएस ऊपर किया, जो विधानसभा के स्पीकर के निजी सहायक का था. यह एसएमएस पिछले महीने एएनएम की भर्त्ती के संदर्भ में किसी की पैरवी के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) के तत्कालीन अध्यक्ष (अब गिरफ्तार) सुधीर कुमार को भेजा गया था. वस्तुतः विपक्ष उन तथ्यों का भी जुगाड़ नहीं कर सका, जिनके संकेत एसआईटी से पूछताछ के दौरान मिले थे. विपक्ष के इस सूचना-दारिद्र्य का लाभ सत्ता पक्ष ने उठाया. इस हंगामे से विपक्ष को भी कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो तय है कि सूबे के विकास व जन कल्याण कार्यक्रमों पर नज़र रखने की अपनी बुनियादी जिम्मेवारी के निर्वहन में जन प्रतिनिधि नाकाम रहे.

मस्तान की अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी को एक क्षेत्रीय चैनल पर 23 फरवरी को दिखाया गया था. लेकिन बिहार भाजपा के नेताओं को अपने शिखर नेता की प्रतिष्ठा को लेकर चिंता जाहिर करने में एक सप्ताह लग गया. इससे भी बड़ी बात यह है कि इस घटना की राजनीतिक उपयोगिता को केन्द्रीय नेतृत्व ने पहले समझा, बाद में सूबे के नेताओं ने. ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में बेहतर वे ही बता सकते हैं. यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि अमौर से पूर्णिया जिला मुख्यालय की दूरी कोई पैंतीस किलोमीटर है, पर पार्टी के जिला नेतृत्व को इस घटना पर प्रतिक्रिया जाहिर करने में पांच दिन लग गए.

मस्तान की अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी को एक क्षेत्रीय चैनल पर 23 फरवरी को दिखाया गया था. लेकिन बिहार भाजपा के नेताओं को अपने शिखर नेता की प्रतिष्ठा की चिंता को जाहिर करने में एक सप्ताह लग गया. इससे भी बड़ी बात यह है कि इस घटना की राजनीतिक उपयोगिता को केन्द्रीय नेतृत्व ने पहले समझा, बाद में सूबे के नेताओं ने. ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में बेहतर वे ही बता सकते हैं. यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि अमौर से पूर्णिया जिला मुख्यालय की दूरी कोई पैंतीस किलोमीटर है, पर पार्टी के जिला नेतृत्व को इस घटना पर प्रतिक्रिया जाहिर करने में पांच दिन लग गए. भाजपा के सूत्रों पर भरोसा करें तो प्रादेशिक नेताओं को 23 फरवरी को ही इसकी जानकारी मिल गई थी, लेकिन वे शांत रहे. जब इसकी खबर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को मिली, तब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए वीडियो मांगा गया. इसके बाद पार्टी के प्रांतीय नेताओं का मौन टूटा.

विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार चौधरी ने मस्तान प्रकरण से बने हालात को सामान्य बनाने की हरसंभव कोशिश की, पर राजनीति ने उनके प्रयास पर पानी फेर दिया. इस मामले के सामने आते ही उन्होंने सभी दलों की बैठक आहूत की, फिर कार्यमंत्रणा समिति की भी बैठक बुलाई. लेकिन विपक्ष के नेता डॉ. प्रेम कुमार ने खुद को इन बैठकों से अलग रखा. वे सदन की कार्यवाही आरंभ होने ही मंत्री की बर्खास्तगी की मांग पर अड़े रहे. इसके बाद भाजपा के विधायक वेल में आ जाते. दशकों के बाद टेबुल-कुर्सी टूटे. एक मार्च से लेकर तीन मार्च तक विधानमंडल की कार्यवाही कभी एक घंटे नहीं चलने दी गई. विपक्ष इस मसले पर मुख्यमंत्री से बयान की मांग कर रहा था, लेकिन हालात को सामान्य बनाने के लिए सत्ता पक्ष से कोई महत्वपूर्ण पहल भी नहीं दिखी. इतना साफ था कि भाजपा के आक्रोशित नेताओं से निपटने की जिम्मेवारी- औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर- स्पीकर पर ही छोड़ दी गई थी. तो क्या सदन की स्थिति के इस कदर बिगड़ जाने में सत्तारूढ़ महागठबंधन की आंतरिक राजनीति भी अपनी भूमिका निभा रही थी? इसका बेहतर जवाब सत्ता पक्ष ही दे सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

मंजिल से दूर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

एस.के. गांधी

सरकारी उदासीनता, प्रशासनिक संवेदनहीनता एवं बीमा कंपनियों के बर्ताव के कारण सूबे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बंदी के कगार पर पहुंच चुकी है. परिणामतः 1 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक इसकी विस्तारित की गई इलाज सेवा प्रचार-प्रसार के अभाव में बीमा कंपनी की भेंट चढ़ गई है. इस बीच संबद्ध अस्पताल बीपीएल रोगियों के इलाज में आनाकानी करने लगे हैं.

इसके पूर्व युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने लखीसराय जिले में आरएसबीवाई अस्पतालीकरण की कैशलेस इलाज सेवा 01 मई 2015 से 30 सितम्बर 2016 तक बीपीएल हेल्थ स्मार्ट कार्ड धारक मरीजों के लिए शुरू की थी. इस दौरान जिले में 104779 बीपीएल लाभार्थियों में से बीमा सेवा प्रदाता कंपनी की थर्ड पार्टी कार्य एजेंसी विडॉल हेल्थ केयर टीपीए की ओर से आनन-फानन में कुल 40285 लाभुकों के हेल्थ स्मार्ट कार्ड बनवाए गए. इससे प्रति लाभुक 30 रुपये प्रति कार्ड की दर से बतौर पंजीयन बारह लाख रुपए की शुल्क वसूली भी की गई. इसमें से 3 रुपए की दर से राशि संबद्ध एफकेओ को पहचान मानदेय के तौर पर व्यय किया जाना है.

बीमा कंपनी की टीपीए एवं कार्ड सप्लाई एजेंसी व्हाय फ्लैक्स लि. द्वारा 01 अप्रैल से 31 जुलाई 2015 तक जिले में गुपचुप तरीके से स्मार्ट कार्ड इनरॉलमेंट के कार्य को अंतिम रूप दिया गया. इसके पूर्व इनरॉलमेंट एजेंसी की ओर से जिला स्तरीय कार्यशाला, वर्कशॉप व प्रचार-प्रसार मात्र रस्म अदायगी के लिए की गई.

दूसरी ओर कई स्थानों पर बीमा कंपनी के

प्रतिनिधि इनरॉलमेंट के लिए स्टेशन तक गठित नहीं कर सके. डीकेएमए डाटा में हेरफेर कर सर्वर पर ऑनलाइन कार्ड बनाकर वितरण करने के आरोप भी लगे. मुंगेर की सांसद सह अध्यक्ष वीणा देवी से लोगों ने जिले में व्याप्त इनरॉलमेंट घोटाले की जांच के बाद ही बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान दिये जाने की बातें कही हैं.

इनरॉलमेंट सेंटर पर वेब कैमरा, ऑप्टिकल बायोमैट्रिक स्कैनर, डाटा मास्टर, बैट्री पावर बैकअप एवं डाय सबमिशन प्रिंटर आदि उपलब्ध नहीं थे. इसके अलावा एफकेओ में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं एवं विकास मित्र आदि को स्मार्ट कार्ड बनाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. आईसीडीएस अथवा बीडीओ की साप्ताहिक बैठक में इनसे पंजीयन पर दस्तखत करवाकर इनरॉलमेंट की रस्मअदायगी की गई.

इतना ही नहीं, गरीब लाभुकों को नजरंदाज कर अमीर लोगों का भी हेल्थ स्मार्ट कार्ड बना दिया गया. लखीसराय जिले के टाल, दियारा एवं नक्सल प्रभावित कई इलाकों में इनरॉलमेंट टीम की ओर से विधि-व्यवस्था का हवाला देकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति अर्थात आदिवासियों के भी हेल्थ स्मार्ट नहीं बनवाए गए. यहां तक कि इनरॉलमेंट से पूर्व जिले में प्रखंडवार रोड मैप तक नहीं बनाया गया.

विदित हो कि लखीसराय जिले में बीमा सेवा प्रदाता को प्रति हेल्थ स्मार्ट कार्ड की सरकारी प्रीमियम राशि 248 रुपए एवं पंजीयन शुल्क 30 रुपए प्रति कार्ड की दर से एक करोड़ इकतीस लाख रुपए की प्रीमियम राशि निर्धारित हुई है.

दिसम्बर 2016 तक कुल 1117 बीपीएल मरीजों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पांच अस्पतालों से इलाज मुहैया कराए गए. इस पर कुल इक्कासी लाख सत्तर लाख रुपए अस्पतालों ने बीमा कम्पनी को भुगतान के लिए दिए हैं. युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने इसमें से पच्चीस लाख तेहत्तर हजार रुपए के बिल का भुगतान कर दिया है. इसके बावजूद जिले में अस्पतालीकरण के पचपन लाख छियानवे हजार रुपए का भुगतान बकाया है.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत दिसंबर 2016 तक नेत्रलोक अस्पताल ने 25,52,537 रुपए, नयन ज्योति अस्पताल ने 21,83, 150 रुपए, सदर अस्पताल लखीसराय ने 22,000 रुपए, श्री अशोकधाम जनरल एंड सर्जिकल अस्पताल ने 33,74,475 रुपए एवं श्री कृष्ण सेवा सदन द्वारा मात्र 37,750 रुपए की राशि बीपीएल रोगियों की कैशलेस हेल्थ स्मार्ट कार्ड के माध्यम से इलाज की सुविधा दी गई.

इसमें श्री अशोक धाम जनरल एवं सर्जिकल अस्पताल एवं श्री कृष्ण सेवा सदन को बीमा सेवा प्रदाता कंपनी की ओर से अभी तक किसी प्रकार के बिल का भुगतान नहीं किया गया है. इसे लेकर अस्पताल संचालकों में बीमा कंपनी एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के प्रति भारी असंतोष व्याप्त है.

गौरतलब है कि बीमा सेवा अवधि को 31 मार्च 2017 तक विस्तारित कर दिया गया है. बीमा कंपनी की मनमानी के चलते नयन ज्योति अस्पताल, श्री अशोकधाम जेनरल एंड सर्जिकल अस्पताल एवं श्री कृष्ण सेवा सदन के अलावा सभी प्राइवेट पंजीकृत अस्पतालों में अघोषित तौर पर इसकी सेवा बंद कर दी गई है.

विदित हो कि सूबे के 20 जिलों में से अररिया, बांका, शेखपुरा, मधेपुरा, अरवल, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, सीवान, बेगुसराय, जहानाबाद, पूर्णिया, किशनगंज, प. चंपारण, शिवहर, मुंगेर, भागलपुर, जमुई, लखीसराय एवं नवादा में युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को आरएसबीवाई का कार्य एजेंसी बनाया गया है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-बसर करने वाले लोगों एवं असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के एक परिवार के कुल पांच सदस्यों के बीच बीमित राशि तीस हजार रुपये तक बायोमैट्रिक हेल्थ स्मार्ट कार्ड पर मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है.■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार में एक जेल ऐसा भी...

यहां परिवार के साथ छुट्टियां मनाते हैं कैदी

राणा अवधूत कुमार

बिहार की जेलों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर यह धारणा है कि यहां कैदियों को न्यूनतम सुविधा मिलती है. कैदियों को भेड़-बकरियों की तरह ठूंस-ठूंस कर रखा जाता है. इतना ही नहीं, कैदियों के कद यानी उसके रसूख के हिसाब से जेलों में सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं. वहीं बक्सर जिला में एक जेल ऐसा भी है, जहां कैदियों को ना सिर्फ पूरी सुविधाएं दी जाती हैं, बल्कि पर्व-त्योहार में उन्हें अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने का अवसर भी दिया जाता है. इसके अलावा, जेल प्रशासन कैदियों को जेल से बाहर मजदूरी या अन्य कोई काम करने का अवसर भी देता है. कह सकते हैं कि बक्सर केंद्रीय कारा एकमात्र ऐसा जेल है, जहां कैदियों के मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखकर उनके साथ व्यवहार किया जाता है. सजा पूरी होने के पूर्व उन्हें परिजनों के साथ समय बिताने और अपनी गलती सुधारकर समाज की मुख्यधारा में वापस लौटने के अवसर दिए जाते हैं.

बक्सर केंद्रीय कारागार में ही बनाया गया है, एक ओपन जेल. यह अपने आप में अनूठा है और बाहरी लोगों के लिए बिल्कुल ही अविश्वसनीय. पिछले साल की दिवाली तो यहां के कैदियों के लिए यादगार रही, वहीं इस बार की होली भी एक अनुपम उपहार लेकर आई. जेल में वर्षों से कैद कई मुजरिमों को अपने परिवार के साथ होली-दिवाली की खुशियां बांटने का अवसर मिला. बक्सर के केंद्रीय कारा में ही बने एक विशेष सेल को ओपेन जेल का नाम दिया गया है. जेनरल सेक्शन से ओपेन जेल में जाने की भी कुछ अर्हताएं हैं. यहां कैदियों का अच्छा व्यवहार, दूसरे लोगों व कैदियों के साथ प्रेमपूर्वक बर्ताव और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की प्रतिबद्धता दिखाना अनिवार्य है. सबसे बड़ी बात यह है कि इस जेल में वैसे ही कैदियों की इंट्री होती है, जो अपनी आधी सजा मुख्य जेल में काट चुके हों. इन नियमों के बाद ही कैदियों को ओपेन जेल में रहने की सुविधा मिलती है.

समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए इन कैदियों को जेल में ही परिवार के साथ रहने और पर्व-त्योहारों में उनके साथ समय गुजारने के लिए फ्लैट तक मुहैया कराया जाता है. इस बार इसमें रहने के लिए 87 कैदियों को चुना गया है.

> यहां उन्हीं कैदियों को रखा जाता है, जो अपनी आधी सजा काट चुके हैं और जिनका व्यवहार आम कैदियों से बेहतर और सद्भावनापूर्ण रहता है. जो जेल से निकलने के बाद समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की इच्छा रखते हों. जेल यातना देने के लिए नहीं, बल्कि उनके हृदय परिवर्तन का स्थान बने, इस उद्देश्य के पीछे यही भावना निहित है.
>
> *आनंद किशोर, जेल आईजी, बिहार*

> बिहार के अन्य जेलों में बंद कैदी भी सरकार की इस पहल की खूब सराहना करते हैं. चाहे वह रोहतास का कैदी बाल मुकुंद हो या गोपालगंज का साबिर अंसारी या फिर गया का अफसर खान. साबिर अली का 10 साल का पोता अपने जन्म के बाद पहली बार जेल में ही अपने दादा से मिला. वहीं मधुबनी की पिंकी अपने मौसा-मौसी के साथ पिछली बार एकसाथ दिवाली मना सकी. उसने कई साल से अपने किसी परिचित का मुंह तक नहीं देखा था.

बिहार के इस अनूठे जेल के दीदार के लिए कई विदेशी डेलीगेट्स भी यहां आ चुके हैं. ब्रुनेई में एशियन पैसिफिक करेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्रेंस में बिहार के जेल आईजी आनंद किशोर ने ओपेन जेल और इसकी सकारात्मक सफलता के बारे में पूरी दुनिया को बताया. इसके बाद कई देशों के विशेषज्ञों ने इस जेल के भ्रमण की इच्छा जताई और अपने देश में भी इसे अमल करने की मंशा जाहिर की. बक्सर केंद्रीय कारागार स्वतंत्रता संग्राम से लेकर लोहिया के नेतृत्व में कांग्रेस हटाओ देश बचाओ आंदोलन और जेपी आंदोलन का भी मूक गवाह रह चुका है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विशेष पहल के तहत कैदियों को इस जेल में सुविधाएं मिल रही हैं. 23 मई 2012 को मुख्यमंत्री ने बक्सर केंद्रीय कारा में ओपेन जेल का उद्घाटन किया था.

ओपेन जेल की कुछ विशेषताएं इसे अन्य जेलों से अलग करती हैं. आम तौर पर जेल के चहारदिवारी की ऊंचाई 15-18 फुट होती है, लेकिन ओपेन जेल की चहारदिवारी महज 4 फुट रखी गई है. ओपेन जेल के करीब 52 कैदी मनरेगा के तहत बाहर जाकर मजदूरी करते हैं और शाम होते ही सेल में लौट आते हैं. इन्हें भी अन्य मजदूरों की भांति 220 रुपए रोजाना मिलते हैं. इस जेल में बंद कई कैदियों से बात करने पर पता चलता है कि वे इस व्यवस्था से कितने खुश हैं. अब उनके लिए त्योहार खुशियों की सौगात लेकर आती है, जब वे अपने परिजनों से मिलते हैं. इस साल जेल के लिए चुने गये 87 कैदियों में से कई ऐसे हैं, जो वर्षों से अपने परिजनों-रिश्तेदारों से नहीं मिले थे. यह इन कैदियों के लिए किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं था.

बिहार के अन्य जेलों में बंद कैदी भी सरकार की इस पहल की खूब सराहना करते हैं. चाहे वह रोहतास का कैदी बाल मुकुंद हो या गोपालगंज का साबिर अंसारी या फिर गया का अफसर खान. साबिर अली का 10 साल का पोता अपने जन्म के बाद पहली बार जेल में ही अपने दादा से मिला. वहीं मधुबनी की पिंकी अपने मौसा-मौसी के साथ पिछली बार एकसाथ दिवाली मना सकी. उसने कई साल से अपने किसी परिचित का मुंह तक नहीं देखा था. हजारीबाग केंद्रीय कारा और कोलकाता केंद्रीय कारा के अधिकारी भी ओपेन जेल का भ्रमण कर चुके हैं. वे इस तरह की पहल देश के अन्य जेलों में भी लागू करने की वकालत कर रहे हैं. ओपन जेल के प्रभारी काराधीक्षक राजेश कुमार ने कहा कि ओपन जेल कैदियों के भरोसे और विश्वास के आधार पर ही उन्हें बेहतर मानवीय सुविधाएं देने के प्रयास में जुटा है. यह पहल कैदियों के प्रति मानवीय मूल्यों एवं समाज की मुख्यधारा में वापस लौटने की उनकी प्रेरणा को राह देता है.■

feedback@chauthiduniya.com

एक मंच पर 56 जोड़ी वर-वधुओं का निकाह

कौमी एकता का मिसाल बना सामूहिक विवाह

राकेश कुमार

एक ही मंच पर एक साथ विवाह और निकाह संपन्न हों, तो इससे बेहतर गंगा-जमुनी तहजीब कहीं और ढूंढनी मुश्किल है. लोगों को आश्चर्य हुआ, जब एक तरफ सात फेरे की तैयारियों में जुटे पंडित और दूसरी तरफ निकाह पढ़ाने आए मौलवी एक-दूसरे से गले मिल रहे थे. बिहार के चंपारण जिले में इस सच को साकार किया है नगदाहां सेवा समिति ने. 26 फरवरी को मोतिहारी के राजेन्द्र नगरभवन से रथों पर सवार एक ही लिबास में सजे 56 दूल्हों के साथ बारात निकली. दर्जनों हाथी, घोड़े, ऊंट और गाजे-बाजे के साथ निकली इस बारात की अगुआई जिले के गणमान्य लोगों ने की. बारात के साथ हजारों लोग पैदल चल रहे थे. छत से महिलाएं फूलों की बारिश कर रही थीं. मोतिहारी के बरियारपुर स्थित गृह रक्षा वाहिनी के मैदान में विशाल पंडाल का निर्माण किया गया था. एक-एक कर 56 दूल्हे शेरवानी और मुकुट पहने मंच पर उपस्थित हुए. इसके बाद लाल साड़ियों में सजी-संवरी दुल्हनों को मंच पर लाया गया. मंच पर एक तरफ बुरके में 6 मुस्लिम दुल्हनें भी थीं. महिलाओं ने मंगल गीत गाकर इन जोड़ियों का स्वागत किया. कौमी एकता और भाईचारे के इस अद्भुत दृश्य को देख उपस्थित जन-सैलाब की आंखें भर आईं. वर-वधु के परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू बहते रहे. अपनी बेटी के लिए एक जोड़ी साड़ी तक की व्यवस्था करने में अक्षम मां-बाप अपनी लाडली की शाही शादी के गवाह बन रहे थे. कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम बिहार के सबसे बड़े सामाजिक आयोजन होने का गौरव प्राप्त कर रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

बच्चे के लिए स्तनपान जरूरी

ariskon Pharma Pvt.Ltd.

डॉ. यू.के. मिश्रा (BAMS)
गंगा मेडिकल हॉल, नियर जगजीवन कॉलेज, गया

गया जगजीवन कॉलेज के पास गंगा मेडिकल हॉल में प्रेक्टिस कर रहे डॉ. यू.के मिश्रा ने अपनी बात रखते हुए बताया कि जन्म से तीन महीने तक शिशु की देखभाल बड़े ध्यान से करने की आवश्यकता है। बच्चे के जन्म लेने के बाद जितनी जल्दी हो सके बच्चे को मां का दूध पिलाना चाहिए। बच्चे को मां का पहला दूध (कोलोस्ट्रम) पीने से जीवन जीने की शक्ति मिलती है और मां के दूध में पाये जाने वाले तत्व पौष्टिकता देने के साथ-साथ बच्चे को कई रोगों और रोग को फैलने से बचाते हैं। बच्चे को पहले दिन से ही दो-तीन घंटे के बाद ही दूध पिला देना चाहिए। जब बच्चा रोने लगे तब उसको मां का दूध पिलाना सबसे अच्छा आहार है। तीन महीने तक के बच्चे को जब तक वह मां का दूध पीता है, उस समय बच्चे को पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। मां का दूध ही बच्चे के पूरे भोजन का काम करता है।शुरुआत में दो-तीन महीने बच्चा दूध पीकर अगर उल्टी कर देता है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक बच्चा मां का दूध पीता है तब तक दूध को हजम करने के लिए बच्चे को किसी घुट्टी या ग्राइप वाटर की जरूरत नहीं है। जब तक बच्चा मां का दूध पीए, तब तक मां को चाहिए कि वह खाना खाने के बाद पानी न पीए, बल्कि बच्चे को दूध पिलाने से 15 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी लें, इसके बाद ही बच्चे को स्तनपान (अपना दूध पिलायें) करायें। ऐसा करने से बच्चे को उल्टी-दस्त नहीं होते हैं। मां को सदा खुश होकर और हर दो से तीन घंटे के अंतर पर बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। गुस्से या दिमागी परेशानी में बच्चे को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। ■ भारती

ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident

Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.

AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.

ASRFEN-P
Acedofenac+Paracetamol Serratiopeplidase Tab.

ECTALOPAM
Escilalopram oxalate & Clonazepam Tablets

SILIPLEX
Silymarin, Vitamin B-Complex & Lactic acid, Calcium, Bacillus Cap/Syp

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम

जानें किस विधानसभा क्षेत्र से किस पार्टी का कौन उम्मीदवार जीता

क्रम	विधानसभा सीट	विजेता का नाम	पार्टी	सुरक्षित	संख्या	जिला	लोकसभा क्षेत्र
01	आगरा कैंट	डॉ. गिरराज सिंह धर्मेश	भाजपा	SC	87	आगरा	आगरा
02	आगरा उत्तर	जगन प्रसाद गर्ग	भाजपा		89	आगरा	आगरा
03	आगरा ग्रामीण	हेमलता दिवाकर	भाजपा	SC	90	आगरा	फतेहपुर सीकरी
04	आगरा दक्षिण	योगेन्द्र उपाध्याय	भाजपा		88	आगरा	आगरा
05	अजगरा	कैलाश नाथ सोनकर	सुहेलदेवभासपा	SC	385	वाराणसी	चंदौली
06	अकबरपुर	राम अचल राजभर	बसपा		281	अंबेडकरनगर	अंबेडकरनगर
07	अकबरपुर रनिया	प्रतिभा शुक्ला	भाजपा		206	कानपुर देहात	अकबरपुर
08	आलापुर	अनीता	भाजपा	SC	279	अंबेडकर नगर	संतकबीर नगर
09	अलीगंज	सत्यपाल सिंह राठौर	भाजपा		103	एटा	फर्रुखाबाद
10	अलीगढ़	संजीव राजा	भाजपा		76	अलीगढ़	अलीगढ़
11	इलाहाबाद उत्तर	हर्षवर्धन वाजपेयी	भाजपा		262	इलाहाबाद	फूलपुर
12	इलाहाबाद दक्षिण	नंद गोपाल गुप्ता नंदी	भाजपा		263	इलाहाबाद	इलाहाबाद
13	इलाहाबाद पश्चिम	सिद्धार्थ नाथ सिंह	भाजपा		261	इलाहाबाद	फूलपुर
14	अमनपुर	देवेन्द्र प्रताप	भाजपा		101	कासगंज	एटा
15	अमेठी	गरिमा सिंह	भाजपा		186	अमेठी	अमेठी
16	अमृतपुर	सुशील कुमार शाक्य	भाजपा		193	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद
17	अमरोहा	महबूब अली	सपा		41	अमरोहा	अमरोहा
18	अनूपशहर	संजय	भाजपा		67	बुलंदशहर	बुलंदशहर
19	आंवला	धर्म पाल सिंह	भाजपा		126	बरेली	आंवला
20	आर्य नगर	अमिताभ वाजपेयी	सपा		214	कानपुर	कानपुर
21	असमोली	पिंकी यादव	सपा		32	मुरादाबाद	संभल
22	अतरौली	संदीप कुमार सिंह	भाजपा		73	अलीगढ़	अलीगढ़
23	अतरौलिया	डॉ. संग्राम यादव	सपा		343	आजमगढ़	लालगंज
24	औराई	दीनानाथ भास्कर	भाजपा	SC	394	संतरविदास नगर	भदोही
25	औरैया	रमेश चंद्रा	भाजपा	SC	204	औरैया	इटावा
26	अयहशाह	विकास गुप्ता	भाजपा		241	फतेहपुर	फतेहपुर
27	अयोध्या	वेद प्रकाश गुप्ता	भाजपा		275	फैजाबाद	फैजाबाद
28	आजमगढ़	दुर्गा प्रसाद	सपा		347	आजमगढ़	आजमगढ़
29	बाबागंज	विनोद कुमार	स्वतंत्र	SC	245	प्रतापगढ़	कौशांबी
30	बबेरू	चंद्रपाल कुशवाहा	भाजपा		233	बांदा	बांदा
31	बबीना	राजीव सिंह	भाजपा		222	झांसी	झांसी
32	बछरावां	रामनरेश रावत	भाजपा	SC	177	रायबरेली	रायबरेली
33	बदायूं	महेश चंद्र गुप्ता	भाजपा		115	बदायूं	बदायूं
34	बदलापुर	रमेश चंद्र मिश्रा	भाजपा		364	जौनपुर	जौनपुर
35	बागपत	योगेश धामा	भाजपा		52	बागपत	बागपत
36	बाह	रानी पक्षालिका सिंह	भाजपा		94	आगरा	फतेहपुर सीकरी
37	बहेड़ी	छत्रपाल सिंह	भाजपा		118	बरेली	पीलीभीत
38	बहराइच	अनुपमा जायसवाल	भाजपा		286	बहराइच	बहराइच
39	बैरिया	सुरेन्द्र	भाजपा		363	बलिया	बलिया
40	बख्शी का तालाब	अविनाश त्रिवेदी	भाजपा		169	लखनऊ	मोहनलालगंज
41	बालामऊ	राम पाल वर्मा	भाजपा	SC	160	हरदोई	मिसरिख
42	बालदेव	पूरन प्रकाश	भाजपा	SC	85	मथुरा	मथुरा
43	बलहा	अक्षयवर लाल	भाजपा	SC	282	बहराइच	बहराइच
44	बलिया शहर	आनंद	भाजपा		361	बलिया	बलिया
45	बलरामपुर	पलटू राम	भाजपा		294	बलरामपुर	श्रावस्ती
46	बांदा	प्रकाश द्विवेदी	भाजपा		235	बांदा	बांदा
47	बांगड़मऊ	कुलदीप सिंह सेंगर	भाजपा		162	उन्नाव	उन्नाव
48	बांसडीह	राम गोविंद चौधरी	सपा		362	बलिया	सलेमपुर
49	बांसगांव	विमलेश पासवान	भाजपा		327	गोरखपुर	बांसगांव
50	बांसी	जय प्रताप सिंह	भाजपा		304	सिद्धार्थनगर	डुमरियागंज
51	बारा	डॉ. अजय कुमार	भाजपा	SC	264	इलाहाबाद	इलाहाबाद
52	बाराबंकी	धर्मराज सिंह यादव	सपा		268	बाराबंकी	बाराबंकी
53	बरौली	श्री दलवीर सिंह	भाजपा		72	अलीगढ़	अलीगढ़
54	बरौत	कृष्णपाल मलिक	भाजपा		51	बागपत	बागपत
55	बरेली	डॉ. अरुण कुमार	बीजेपी		124	बरेली	बरेली
56	बरेली कैंट	राजेश अग्रवाल	भाजपा		125	बरेली	बरेली
57	बरहज	सुरेश त्रिवेदी	भाजपा		342	देवरिया	बांसगांव
58	बरहापुर	सुशान्त कुमार	भाजपा		19	बिजनौर	मुरादाबाद
59	बरखेड़ा	किशन लाल राजपूत	भाजपा		128	पीलीभीत	पीलीभीत
60	बस्ती सदर	दयाराम चौधरी	भाजपा		310	बस्ती	बस्ती
61	बेहट	नरेश सैनी	कांग्रेस		01	सहारनपुर	सहारनपुर
62	बेलथरा रोड	धनंजय कन्नौजिया	भाजपा	SC	357	बलिया	सलेमपुर
63	भदोही	रविन्द्र नाथ त्रिपाठी	भाजपा		392	संतरविदास नगर	भदोही
64	भगवंतनगर	हृदय नारायण दीक्षित	भाजपा		166	उन्नाव	उन्नाव
65	भरथना	सावित्री कठेरिया	भाजपा	SC	201	इटावा	इटावा
66	भाटपार रानी	आशुतोष	सपा		340	देवरिया	सलेमपुर
67	भिनगा	मो. असलम	बसपा		289	श्रावस्ती	श्रावस्ती
68	भोगनीपुर	विनोद कुमार कटियार	भाजपा		208	कानपुर देहात	जालौन
69	भोजीपुरा	भैरोलाल मौर्या	भाजपा		120	बरेली	बरेली
70	भोजपुर	नागेन्द्र सिंह राठौर	भाजपा		195	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद
71	भोगांव	राम नरेश अग्निहोत्री	भाजपा		108	मैनपुरी	मैनपुरी
72	बिधूना	विनय शाक्य	भाजपा		202	औरैया	कन्नौज
73	बिजनौर	शुची	भाजपा		22	बिजनौर	बिजनौर
74	बीकापुर	शोभा सिंह चौहान	भाजपा		274	फैजाबाद	फैजाबाद
75	बिलारी	मो. फईम	सपा		30	मुरादाबाद	संभल
76	बिलासपुर	बलदेव सिंह अवलाख	भाजपा		36	रामपुर	रामपुर
77	बिलग्राम मल्लावां	आशीष कुमार सिंह	भाजपा		159	हरदोई	मिसरिख
78	बिल्हौर	भगवती प्रसाद सागर	भाजपा	SC	209	कानपुर	मिसरिख
79	बिलसी	राधा कृष्ण शर्मा	भाजपा		114	बदायूं	बदायूं
80	बिन्दकी	कर्ण सिंह पटेल	भाजपा		239	फतेहपुर	फतेहपुर
81	बिसालपुर	अज्ञश रामशरन वर्मा	भाजपा		130	पीलीभीत	पीलीभीत
82	बिसौली	कुशाग्र सागर	भाजपा		112	बदायूं	बदायूं
83	बिसवां	महेन्द्र सिंह	भाजपा		149	सीतापुर	सीतापुर
84	विश्वनाथगंज	राकेश कुमार वर्मा	अपना दल		247	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
85	बिठारी चैनपुर	राजेश कुमार मिश्रा	भाजपा		123	बरेली	आंवला
86	बिठूर	अभिजित सिंह सांगा	भाजपा		210	कानपुर नगर	अकबरपुर
87	बुढ़ाना	उमेश मलिक	भाजपा		11	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर
88	बुलंदशहर	विरेंद्र सिंह सिरोही	भाजपा		65	बुलंदशहर	बुलंदशहर
89	कैम्पियरगंज	फतेह बहादुर	भाजपा		320	गोरखपुर	गोरखपुर
90	चैल	संजय कुमार	भाजपा		253	कौशांबी	कौशांबी
91	चकिया	श्रद्धा प्रसाद	भाजपा	SC	383	चंदौली	रॉबर्ट्सगंज
92	चमरौहा	नसीर अहमद खान	सपा		35	रामपुर	रामपुर
93	चंदौसी	गुलाब देवी	भाजपा	SC	31	संभल	संभल
94	चांदपुर	कमलेश सैनी	भाजपा		23	बिजनौर	बिजनौर
95	चरखारी	बृजभूषण राजपूत	भाजपा		231	महोबा	हमीरपुर
96	चरथावल	विजय कुमार कश्यप	भाजपा		12	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर
97	चौरी-चौरा	संगीता यादव	भाजपा		326	गोरखपुर	बांसगांव
98	छानबे	राहुल प्रकश	अपना दल	SC	395	मिर्जापुर	मिर्जापुर
99	छपरौली	सहेन्द्र सिंह रामलाल	आरएलडी		50	बागपत	बागपत
100	छर्रा	रवीन्द्र पाल सिंह	भाजपा		74	अलीगढ़	हाथरस
101	छाता	लक्ष्मी नारायण	भाजपा		81	मथुरा	मथुरा
102	छिबरामऊ	अर्चना पाण्डेय	भाजपा		196	कन्नौज	कन्नौज
103	चिल्लूपार	विनय शंकर तिवारी	बसपा		328	गोरखपुर	बांसगांव
104	चित्रकूट	चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय	भाजपा		236	चित्रकूट	बांदा
105	चुनार	अनुराग सिंह	भाजपा		398	मिर्जापुर	मिर्जापुर
106	कर्नलगंज	अजय प्रताप सिंह	भाजपा		298	गोंडा	कैसरगंज
107	ददरौल	मानवेंद्र सिंह	भाजपा		136	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर
108	दादरी	तेजपाल सिंह नागर	भाजपा		62	गौतमबुद्ध नगर	गौतमबुद्ध नगर
109	दरियाबाद	सतीश चंद्र शर्मा	भाजपा		270	बाराबंकी	फैजाबाद
110	दातागंज	राजीव कुमार सिंह	भाजपा		117	बदायूं	आंवला
111	डिबाई	डॉ. अनिता लोधी राजपूत	भाजपा		68	बुलंदशहर	बुलंदशहर
112	देवबंद	बृजेश	भाजपा		05	सहारनपुर	सहारनपुर
113	देवरिया	जनमेजय सिंह	भाजपा		337	देवरिया	देवरिया
114	धामपुर	अशोक कुमार राणा	भाजपा		20	बिजनौर	नगीना
115	धनौरा	राजीव कुमार	भाजपा	SC	39	अमरोहा	अमरोहा
116	धनघटा	श्रीराम चौहान	भाजपा	SC	314	संतकबीर नगर	संतकबीर नगर
117	धौरहरा	अवस्थी बाला प्रसाद	भाजपा		141	लखीमपुर खीरी	धौरहरा
118	धौलाना	असलम चौधरी	बसपा		58	हापुड़	गाजियाबाद
119	डिबियापुर	लखन सिंह	भाजपा		203	औरैया	इटावा
120	दीदारगंज	सुखदेव राजभर	बसपा		350	आजमगढ़	लालगंज
121	डुमरियागंज	राघवेन्द्र प्रताप सिंह	भाजपा		306	सिद्धार्थ नगर	डुमरियागंज
122	दुद्धी	हरी राम	अपना दल	ST	403	सोनभद्र	रॉबर्ट्सगंज
123	एटा	विपीन कुमार डेविड	भाजपा		104	एटा	एटा
124	इटावा	सरिता भदौरिया	भाजपा		200	इटावा	इटावा
125	एतमादपुर	राम प्रताप सिंह	भाजपा		86	आगरा	आगरा
126	फरीदपुर	डॉ. श्याम बिहारी लाल	भाजपा	SC	122	बरेली	आंवला
127	फर्रुखाबाद	मेजर सुनील दत्त द्विवेदी	भाजपा		194	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद
128	फतेहाबाद	जितेंद्र वर्मा	भाजपा		93	आगरा	फतेहपुर सीकरी
129	फतेहपुर	विक्रम सिंह	भाजपा		240	फतेहपुर	फतेहपुर
130	फतेहपुर सीकरी	चौधरी उदयभान सिंह	भाजपा		91	आगरा	फतेहपुर सीकरी
131	फाजिलनगर	गंगा	भाजपा		332	कुशीनगर	देवरिया
132	फिरोजाबाद	मनीष असीजा	भाजपा		97	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद
133	गैंसड़ी	शैलेश कुमार सिंह	भाजपा		292	बलरामपुर	श्रावस्ती
134	गनगोह	प्रदीप कुमार	भाजपा		07	सहारनपुर	कैराना
135	गरौठा	जवाहर लाल राजपूत	भाजपा		225	झांसी	जालौन
136	गढ़मुक्तेश्वर	कमल सिंह मलिक	भाजपा		60	हापुड़	अमरोहा
137	गौरा	प्रभात कुमार वर्मा	भाजपा		301	गोंडा	गोंडा
138	गौरीगंज	राकेश प्रताप सिंह	सपा		185	अमेठी	अमेठी
139	घाटमपुर	कमल रानी	भाजपा	SC	218	कानपुर	अकबरपुर
140	गाजियाबाद	अतुल गर्ग	भाजपा		56	गाजियाबाद	गाजियाबाद
141	गाजीपुर	संगीता	भाजपा		375	गाजीपुर	गाजीपुर
142	घोरावल	अनिल कुमार मौर्या	भाजपा		400	सोनभद्र	रॉबर्ट्सगंज
143	घोसी	फग्गू चौहान	भाजपा		354	मऊ	घोसी
144	गोला गोकरणनाथ	अरविन्द गिरि	भाजपा		139	लखीमपुर खीरी	खीरी
145	गोंडा	प्रतीक भूषण सिंह	भाजपा		296	गोंडा	गोंडा
146	गोपालपुर	नफीस अहमद	सपा		344	आजमगढ़	आजमगढ़
147	गोपामऊ	श्याम प्रकाश	भाजपा	SC	157	हरदोई	हरदोई
148	गोरखपुर ग्रामीण	विपीन सिंह	भाजपा		323	गोरखपुर	गोरखपुर
149	गोरखपुर शहर	डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल	भाजपा		322	गोरखपुर	गोरखपुर
150	गोसाईंगंज	इंद्रप्रताप उर्फ खब्बू तिवारी	भाजपा		276	फैजाबाद	अंबेडकर नगर
151	गोवर्धन	कारीन्दा सिंह	भाजपा		83	मथुरा	मथुरा
152	गोविंदनगर	सत्यदेव पचौरी	भाजपा		212	कानपुर	नगर कानपुर
153	गुन्नौर	अजीत कुमार	भाजपा		111	बदायूं	बदायूं
154	ज्ञानपुर	विनय मिश्रा	आमदल		393	संतरविदास नगर	भदोही
155	हैदरगढ़	बैजनाथ रावत	भाजपा	SC	272	बाराबंकी	बाराबंकी
156	हमीरपुर	अशोक कुमार सिंह चंडेल	भाजपा		228	हमीरपुर	हमीरपुर
157	हंडिया	हाकिम लाल	बसपा		258	इलाहाबाद	भदोही
158	हापुड़	विजय पाल	भाजपा	SC	59	हापुड़	मेरठ
159	हरचंदपुर	राकेश सिंह	कांग्रेस		179	रायबरेली	रायबरेली
160	हरदोई	नीतीन अग्रवाल	सपा		156	हरदोई	हरदोई
161	हसगांव	सुरेश राही	भाजपा	SC	147	सीतापुर	धौरहरा
162	हैया	अजय कुमार सिंह	भाजपा		307	बस्ती	बस्ती
163	हसनपुर	महेंद्र सिंह खडगवंशी	भाजपा		42	अमरोहा	अमरोहा
164	हस्तिनापुर	दिनेश खटीक	भाजपा	SC	45	मेरठ	बिजनौर
165	हाटा	पवन कुमार	भाजपा		334	कुशीनगर	कुशीनगर
166	हाथरस	हरिशंकर सिंह माहोर	भाजपा	SC	78	हाथरस	हाथरस
167	हुसैनगंज	रविन्द्र प्रताप सिंह	भाजपा		242	फतेहपुर	फतेहपुर
168	इगलास	राजवीर दिलेर	भाजपा	SC	77	अलीगढ़	हाथरस
169	इसौली	अहरार अहमद	सपा		187	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर
170	इटवा	डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी	भाजपा		305	सिद्धार्थनगर	डुमरियागंज
171	जगदीशपुर	सुरेश कुमार	भाजपा	SC	184	अमेठी	अमेठी
172	जहानाबाद	जय कुमार सिंह जैकी	अपना दल		238	फतेहपुर	फतेहपुर
173	जखनियां	त्रिवेणी राम	सुहेलदेव भासपा	SC	373	गाजीपुर	गाजीपुर
174	जलालाबाद	शरदवीर सिंह	सपा		132	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर
175	जलालपुर	रितेश पाण्डेय	बसपा		280	अंबेडकरनगर	अंबेडकरनगर
176	जलेसर	संजीव कुमार दिवाकर	भाजपा	SC	106	एटा	आगरा
177	जेंगीपुर	विरेन्द्र कुमार यादव	सपा		376	गाजीपुर	गाजीपुर
178	जससरा	रामगोपाल पप्पू लोधी	भाजपा		96	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद
179	जसवंतनगर	शिवपाल सिंह यादव	सपा		199	इटावा	मैनपुरी
180	जौनपुर	गिरीशचंद्र यादव	भाजपा		366	जौनपुर	जौनपुर
181	जेवर	धीरेन्द्र सिंह	भाजपा		63	गौतमबुद्ध नगर	गौतमबुद्ध नगर
182	झांसी नगर	रवि शर्मा	भाजपा		223	झांसी	झांसी
183	कादीपुर	राजेश गौतम	भाजपा	SC	191	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर
184	कायमगंज	अमर सिंह	भाजपा	SC	192	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद
185	कैराना	नाहीद हसन	सपा		08	शामली	कैराना
186	कैसरगंज	मुकुट बिहारी	भाजपा		288	बहराइच	कैसरगंज
187	कालपी	कुंवर नरेन्द्रपाल सिंह	भाजपा		220	जालौन	जालौन
188	कल्याणपुर	नीलिमा कटियार	भाजपा		211	कानपुर	अकबरपुर
189	कन्नौज	अनिल कुमार दोहरे	सपा	SC	198	कन्नौज	कन्नौज
190	कानपुर कैंट	सोहेल अख्तर अंसारी	कांग्रेस		216	कानपुर	कानपुर

क्रम	विधानसभा सीट	विजेता का नाम	पार्टी	सुरक्षित	संख्या	जिला	लोकसभा क्षेत्र
191	कांठ	राजेश कुमार सिंह	भाजपा		25	मुरादाबाद	मुरादाबाद
192	कपिलवस्तु	श्याम धनी	भाजपा	SC	303	सिद्धार्थनगर	डुमरियागंज
193	कप्तानगंज	चंद्र प्रकाश शुक्ल	भाजपा		308	बस्ती	बस्ती
194	करछना	उज्ज्वल रमन सिंह	सपा		260	इलाहाबाद	इलाहाबाद
195	करहल	सोबरन सिंह यादव	सपा		110	मैनपुरी	मैनपुरी
196	कासगंज	देवेन्द्र सिंह राजपूत	भाजपा		100	कासगंज	एटा
197	कसता	सौरभ सिंह	भाजपा	SC	143	लखीमपुर खीरी	धौरहरा
198	कठेरी	लाल जी वर्मा	बसपा		277	अंबेडकरनगर	अंबेडकरनगर
199	कटरा	वीर विक्रम सिंह प्रिंस	भाजपा		131	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर
200	कटरा बाजार	बवन सिंह	भाजपा		297	गोंडा	कैसरगंज
201	केराकट	दिनेश चौधरी	भाजपा	SC	372	जौनपुर	मछलीशहर
202	खड्डा	जटाशंकर त्रिपाठी	भाजपा		329	कुशीनगर	कुशीनगर
203	खागा	कृष्णा पासवान	भाजपा	SC	243	फतेहपुर	फतेहपुर
204	खैर	अनुप	भाजपा	SC	71	अलीगढ़	अलीगढ़
205	खजानी	संत प्रसाद	भाजपा	SC	325	गोरखपुर	संतकबीर नगर
206	खलीलाबाद	दिग्विजय नारायण चौबे	भाजपा		313	संतकबीर नगर	संतकबीर नगर
207	खतौली	विक्रम सिंह	भाजपा		15	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर
208	खैरागढ़	महेश कुमार गोयल	भाजपा		92	आगरा	फतेहपुर सीकरी
209	खुरजा	विरेन्द्र सिंह	भाजपा	SC	70	बुलंदशहर	गौतमबुद्ध नगर
210	किदवई नगर	महेश चंद्र	भाजपा		215	कानपुर	कानपुर
211	किशनी	ब्रजेश कुमार	सपा	SC	109	मैनपुरी	मैनपुरी
212	किठोर	सत्यवीर त्यागी	भाजपा		46	मेरठ	मेरठ
213	कोइल	अनिल पराशर	भाजपा		75	अलीगढ़	अलीगढ़
214	कोराओं	राजमणी	भाजपा	SC	265	इलाहाबाद	इलाहाबाद
215	कुंडा	रघुराज प्रताप सिंह	स्वतंत्र		246	प्रतापगढ़	कौशांबी
216	कुंदरकी	मो. रिजवान	सपा		29	मुरादाबाद	संभल
217	कुरसी	साकेन्द्र प्रताप वर्मा	भाजपा		266	बाराबंकी	बाराबंकी
218	कुशीनगर	रजनीकांत मणी त्रिपाठी	भाजपा		333	कुशीनगर	कुशीनगर
219	लहरपुर	सुनील वर्मा	भाजपा		148	सीतापुर	सीतापुर
220	लखीमपुर	योगेश वर्मा	भाजपा		142	लखीमपुर खीरी	खीरी
221	लालगंज	आजाद अरिमर्दन	बसपा	SC	351	आजमगढ़	लालगंज
222	ललितपुर	रामरतन कुशवाहा	भाजपा		226	ललितपुर	झांसी
223	लंभुआ	देवमणी द्विवेदी	भाजपा		190	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर
224	लोनी	नंदकिशोर	भाजपा		53	गाजियाबाद	गाजियाबाद
225	लखनऊ कैंट	डॉ. रीता बहुगुणा जोशी	भाजपा		175	लखनऊ	लखनऊ
226	लखनऊ सेंट्रल	ब्रजेश पाठक	भाजपा		174	लखनऊ	लखनऊ
227	लखनऊ पूरब	आशुतोष टंडन 'गोपालजी'	भाजपा		173	लखनऊ	लखनऊ
228	लखनऊ उत्तर	डॉ. नीरज बोरा	भाजपा		172	लखनऊ	लखनऊ
229	लखनऊ पश्चिम	सुरेश कुमार श्रीवास्तव	भाजपा		171	लखनऊ	लखनऊ
230	मछलीशहर	जगदीश सोनकर	सपा	SC	369	जौनपुर	मछलीशहर
231	माधवगढ़	मूलचंद्र सिंह	भाजपा		219	जालौन	जालौन
232	मधुबन	दारा सिंह चौहान	भाजपा		353	मऊ	घोसी
233	महादेवा	रवि कुमार सोनकर	भाजपा	SC	311	बस्ती	बस्ती
234	महाराजगंज	जयमंगल	भाजपा	SC	318	महराजगंज	महराजगंज
235	महाराजपुर	सतीश महाना	भाजपा		217	कानपुर नगर	अकबरपुर
236	महसी	सुरेश्वर सिंह	भाजपा		285	बहराइच	बहराइच
237	महमूदाबाद	नरेंद्र सिंह वर्मा	सपा		151	सीतापुर	सीतापुर
238	महोबा	राकेश कुमार गोस्वामी	भाजपा		230	महोबा	हमीरपुर
239	महोली	शशांक त्रिवेदी	भाजपा		145	सीतापुर	धौरहरा
240	मैनपुरी	राजकुमार उर्फ राजू यादव	सपा		107	मैनपुरी	मैनपुरी
241	मझावां	सुचिस्मिता मौर्या	भाजपा		397	मिर्जापुर	मिर्जापुर
242	मल्हानी	प्रशांत यादव	सपा		367	जौनपुर	जौनपुर
243	मलिहाबाद	जय देवी	भाजपा	SC	168	लखनऊ	मोहनलालगंज
244	मानिकपुर	आरके सिंह पटेल	भाजपा		237	चित्रकूट	बांदा
245	मंझनपुर	लाल बहादुर	भाजपा	SC	252	कौशांबी	कौशांबी
246	मनकापुर	रमापति शास्त्री	भाजपा	SC	300	गोंडा	गोंडा
247	मांठ	श्याम सुंदर शर्मा	बसपा		82	मथुरा	मथुरा
248	मरहारा	वीरेन्द्र	भाजपा		105	एटा	एटा
249	मडीहां	रामा शंकर सिंह	भाजपा		399	मिर्जापुर	मिर्जापुर
250	मरियाहू	लीना तिवारी	अपना दल		370	जौनपुर	मछलीशहर
251	मठेरा	यसर शाह	सपा		284	बहराइच	बहराइच
252	मथुरा	श्रीकांत शर्मा	भाजपा		84	मथुरा	मथुरा
253	मऊ	मुख्तार अंसारी	बसपा		356	मऊ	घोसी
254	मऊरानीपुर	बिहारी लाल आर्या	भाजपा	SC	224	झांसी	झांसी
255	मीरापुर	अवतार सिंह भडाना	भाजपा		16	मुजफ्फरनगर	बिजनौर
256	मीरगंज	डॉ. डीसी वर्मा	भाजपा		119	बरेली	बरेली
257	मेरठ	रफीक अंसारी	सपा		48	मेरठ	मेरठ
258	मेरठ कैंट	सत्य प्रकाश अग्रवाल	भाजपा		47	मेरठ	मेरठ
259	मेरठ दक्षिण	डॉ. सोमेन्द्र तोमर	भाजपा		49	मेरठ	मेरठ
260	मेहनगर	कल्पनाथ पासवान	सपा	SC	352	आजमगढ़	आजमगढ़
261	मेहनौन	विनय कुमार	भाजपा		295	गोंडा	गोंडा
262	मेहरोनी	मनोहर लाल	भाजपा	SC	227	ललितपुर	झांसी
263	मेजा	नीलम करवरीया	भाजपा		259	इलाहाबाद	इलाहाबाद
264	मेंहदावल	राकेश सिंह बघेल	भाजपा		312	संतकबीरनगर	संतकबीरनगर
265	मिलक	राजबाला	भाजपा	SC	38	रामपुर	रामपुर
266	मिलकीपुर	गोरख नाथ	भाजपा	SC	273	फैजाबाद	फैजाबाद
267	मिर्जापुर	रत्नाकर मिश्रा	भाजपा		396	मिर्जापुर	मिर्जापुर
268	मिसरिख	राम कृष्ण भार्गव	भाजपा	SC	153	सीतापुर	मिसरिख
269	मोदी नगर	डॉ. मंजू शिवाच	भाजपा		57	गाजियाबाद	बागपत
270	मोहम्मदाबाद	अलका राय	भाजपा		378	गाजीपुर	बलिया
271	मोहम्मदी	लोकेन्द्र प्रताप सिंह	भाजपा		144	लखीमपुर खीरी	धौरहरा
272	मोहान	ब्रजेश कुमार	भाजपा	SC	164	उन्नाव	उन्नाव
273	मोहनलालगंज	अंबरीश सिंह पुष्कर	सपा	SC	176	लखनऊ	मोहनलालगंज
274	मुरादाबाद नगर	रितेश कुमार गुप्ता	भाजपा		28	मुरादाबाद	मुरादाबाद
275	मुरादाबाद ग्रामीण	हाजी इकराम कुरैशी	सपा		27	मुरादाबाद	मुरादाबाद
276	मुबारकपुर	शाह आलम	बसपा		346	आजमगढ़	आजमगढ़
277	मुगलसराय	साधना सिंह	भाजपा		380	चंदौली	चंदौली
278	मुहम्मदाबाद-गोहना	श्रीराम सोनकर	भाजपा	SC	355	मऊ	घोसी
279	मुंगरा बादशाहपुर	सुषमा पटेल	बसपा		368	जौनपुर	जौनपुर
280	मुरादनगर	अजीत पाल त्यागी	भाजपा		54	गाजियाबाद	गाजियाबाद
281	मुजफ्फरनगर	कपिल देव अग्रवाल	भाजपा		14	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर
282	नगीना	मनोज कुमार पारस	सपा	SC	18	बिजनौर	नगीना
283	नजीबाबाद	तसलीम अहमद	सपा		17	बिजनौर	नगीना
284	नकुर	डॉ. धर्म सिंह सैनी	भाजपा		02	सहारनपुर	कैराना
285	नानपारा	माधुरी वर्मा	भाजपा		283	बहराइच	बहराइच
286	नरैनी	राज करन कबीर	भाजपा	SC	234	बांदा	बांदा
287	नौगावां सादात	चेतन चौहान	भाजपा		40	अमरोहा	अमरोहा
288	नौतनवां	अमनमणी त्रिपाठी	स्वतंत्र		316	महराजगंज	महराजगंज
289	नवाबगंज	केसर सिंह	भाजपा		121	बरेली	बरेली
290	नेहटौर	ओम कुमार	भाजपा	SC	21	बिजनौर	नगीना
291	निघासन	पटेल रामकुमार वर्मा	भाजपा		138	लखीमपुर खीरी	खीरी
292	निजामाबाद	आलम बादी	सपा		348	आजमगढ़	लालगंज
293	नोएडा	पंकज सिंह	भाजपा		61	गौतमबुद्धनगर	गौतमबुद्धनगर
294	नूरपुर	लोकेन्द्र सिंह	भाजपा		24	बिजनौर	नगीना
295	ओबरा	संजीव कुमार	भाजपा	ST	402	सोनभद्र	रॉबर्ट्सगंज
296	ओरई	गौरी शंकर	भाजपा	SC	221	जालौन	जालौन
297	पडरौना	स्वामी प्रसाद मौर्य	भाजपा		330	कुशीनगर	कुशीनगर
298	पलिया	हरवेन्द्र कुमार साहनी	भाजपा		137	लखीमपुर खीरी	खीरी
299	पनियारा	ज्ञानेन्द्र	भाजपा		319	महराजगंज	महराजगंज
300	पथरदेवा	सूर्य प्रताप शाही	भाजपा		338	देवरिया	देवरिया
301	पटियाली	ममतेश	भाजपा		102	कासगंज	एटा
302	पट्टी	राजेन्द्र प्रताप सिंह	भाजपा		249	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
303	पयागपुर	सुभाष त्रिपाठी	भाजपा		287	बहराइच	कैसरगंज
304	फाफामऊ	विक्रमजीत	भाजपा		254	इलाहाबाद	फूलपुर
305	फरेंदा	बजरंग बहादुर सिंह	भाजपा		315	महराजगंज	महराजगंज
306	फेफना	उपेन्द्र तिवारी	भाजपा		360	बलिया	बलिया
307	फूलपुर पवई	अरुण कुमार यादव	भाजपा		349	आजमगढ़	लालगंज
308	फूलपुर	प्रवीण कुमार सिंह	भाजपा		256	इलाहाबाद	फूलपुर
309	पीलीभीत	संजय सिंह गंगवार	भाजपा		127	पीलीभीत	पीलीभीत
310	पिंडारा	अवधेश सिंह	भाजपा		384	वाराणसी	मछलीशहर
311	पिपराइच	महेन्द्र पाल सिंह	भाजपा		321	गोरखपुर	गोरखपुर
312	पोवायां	चैतराम	भाजपा	SC	134	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर
313	प्रतापगढ़	संगम लाल गुप्ता	अपना दल		248	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
314	प्रतापपुर	मो. मुजतबा सिद्दकी	बसपा		257	इलाहाबाद	भदोही
315	पूरनपुर	बाबू राम पासवान	भाजपा	SC	129	पीलीभीत	पीलीभीत
316	पुरकाजी	प्रमोद अटवाल	भाजपा	SC	13	मुजफ्फरनगर	बिजनौर
317	पुरवा	अनिल सिंह	बसपा		167	उन्नाव	उन्नाव
318	रायबरेली	अदिती सिंह	कांग्रेस		180	रायबरेली	रायबरेली
319	रामनगर	शरद कुमार अवस्थी	भाजपा		267	बाराबंकी	बाराबंकी
320	रामकोला	रामानन्द बौद्ध	सुहेलदेव भासपा	SC	335	कुशीनगर	कुशीनगर
321	रामपुर	मो. आजम खान	सपा		37	रामपुर	रामपुर
322	रामपुर कारखाना	कमलेश शुक्ला	भाजपा		339	देवरिया	देवरिया
323	रामपुर खास	आराधना मिश्रा 'मोना'	कांग्रेस		244	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
324	रामपुर मनिहारन	देवेन्द्र कुमार	भाजपा	SC	06	सहारनपुर	सहारनपुर
325	रानीगंज	अभय कुमार	भाजपा		250	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
326	रसड़ा	उमा शंकर सिंह	बसपा		358	बलिया	घोसी
327	रसूलाबाद	निर्मला शंखवार	भाजपा	SC	205	कानपुर देहात	कन्नौज
328	राठ	मनीषा अनुरागी	भाजपा	SC	229	हमीरपुर	हमीरपुर
329	रॉबर्ट्सगंज	भूपेश चौबे	भाजपा		401	सोनभद्र	रॉबर्ट्सगंज
330	रोहनिया	सुरेन्द्र नारायण सिंह	भाजपा		387	वाराणसी	वाराणसी
331	रुदौली	राम चंद्र यादव	भाजपा		271	फैजाबाद	फैजाबाद
332	रुधौली	संजय प्रताप जयसवाल	भाजपा		309	बस्ती	बस्ती
333	रुद्रपुर	जय प्रकाश निषाद	भाजपा		336	देवरिया	बांसगांव
334	सादाबाद	रामवीर उपाध्याय	बसपा		79	हाथरस	हाथरस
335	सदर	सीताराम	भाजपा		189	सुल्तानपुर	सल्तानपुर
336	सफीपुर	बाबा लाल	भाजपा	SC	163	उन्नाव	उन्नाव
337	सगरी	बंदना सिंह	बसपा		345	आजमगढ़	आजमगढ़
338	सहजनवां	शीतल पाण्डेय	भाजपा		324	गोरखपुर	गोरखपुर
339	सहारनपुर	मसूद अख्तर	कांग्रेस	SC	04	सहानपुर	सहारनपुर
340	सहारनपुर नगर	संजय गर्ग	सपा		03	सहानपुर	सहारनपुर
341	सहसवां	ओमकार सिंह	सपा		113	बदायूं	बदायूं
342	साहिबाबाद	सुनील कुमार शर्मा	भाजपा		55	गाजियाबाद	गाजियाबाद
343	सैदपुर	सुभाष पासी	सपा	SC	374	गाजीपुर	गाजीपुर
344	सैयदराजा	सुशील सिंह	भाजपा		382	चंदौली	चंदौली
345	सकलडीहा	प्रभुनारायण यादव	सपा		381	चंदौली	चंदौली
346	सलेमपुर	काली प्रसाद	भाजपा	SC	341	देवरिया	सलेमपुर
347	सलोन	दलबहादुर	भाजपा	SC	181	रायबरेली	अमेठी
348	संभल	इकबाल महमूद	सपा		33	मुरादाबाद	संभल
349	सांडी	प्रभाष कुमार	भाजपा	SC	158	हरदोई	हरदोई
350	संडीला	राज कुमार अग्रवाल	भाजपा		161	हरदोई	मिसरिख
351	सरधना	संगीत सिंह सोम	भाजपा		44	मेरठ	मुजफ्फरनगर
352	सरेनी	धीरेन्द्र बहादुर सिंह	भाजपा		182	रायबरेली	रायबरेली
353	सरोजनीनगर	स्वाति सिंह	भाजपा		170	लखनऊ	मोहनलालगंज
354	सवायजपुर	कुंवर माधवेंद्र प्रताप	भाजपा		154	हरदोई	हरदोई
355	सेवापुरी	नीलरतन सिंह पटेल	अपना दल		391	वाराणसी	वाराणसी
356	सेवाता	ज्ञान तिवारी	भाजपा		150	सीतापुर	सीतापुर
357	शाहाबाद	रजनी तिवारी	भाजपा		155	हरदोई	हरदोई
358	शाहगंज	शैलेन्द्र यादव	सपा		365	जौनपुर	जौनपुर
359	शाहजहांपुर	सुरेश कुमार खन्ना	भाजपा		135	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर
360	शामली	तेजेन्द्र निर्बल	भाजपा		10	शामली	कैराना
361	शेखुपुर	धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य	भाजपा		116	बदायूं	आंवला
362	शिकारपुर	अनिल कुमार	भाजपा		69	बुलंदशहर	बुलंदशहर
363	शिकोहाबाद	मुकेश वर्मा	भाजपा		98	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद
364	शिवपुर	अनिल राजभर	भाजपा		386	वाराणसी	चंदौली
365	शोहरतगढ़	अमर सिंह चौधरी	अपना दल		302	सिद्धार्थनगर	डुमरियागंज
366	श्रावस्ती	राम फेरन	भाजपा		290	श्रावस्ती	श्रावस्ती
367	सिधौली	हरगोविन्द भार्गव	बसपा	SC	152	सीतापुर	मोहनलालगंज
368	सिकंदरपुर	संजय यादव	भाजपा		359	बलिया	सलेमपुर
369	सिकंदरा	मथुरा प्रसाद पाल	भाजपा		207	कानपुर देहात	इटावा
370	सिकंदरा राव	विरेन्द्र सिंह राणा	भाजपा		80	हाथरस	हाथरस
371	सिकंदराबाद	विमला सिंह सोलंकी	भाजपा		64	बुलंदशहर	गौतमबुद्धनगर
372	सिराथू	शीतला प्रसाद	भाजपा		251	कौशांबी	कौशांबी
373	सिरसागंज	हरिओम यादव	सपा		99	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद
374	शीशामऊ	हाजी इरफान सोलंकी	सपा		213	कानपुर	कानपुर
375	सिसवा	प्रेमसागर पटेल	भाजपा		317	महराजगंज	महराजगंज
376	सीतापुर	राकेश राठौर	भाजपा		146	सीतापुर	सीतापुर
377	सिवालखास	जीतेन्द्र पाल सिंह	भाजपा		43	मेरठ	बागपत
378	सोरांओं	जमुना प्रसाद	अपना दल	SC	255	इलाहाबाद	फूलपुर
379	श्री नगर	मंजू त्यागी	भाजपा	SC	140	लखीमपुर खीरी	खीरी
380	सुगर	मो. अब्दुल्लाह आजम खान	सपा		34	रामपुर	रामपुर
381	सुल्तानपुर	सूर्यभान सिंह	भाजपा		188	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर
382	स्याना	देवेन्द्र	भाजपा		66	बुलंदशहर	बुलंदशहर
383	तुमकूही राज	अजय कुमार लल्लू	कांग्रेस		331	कुशीनगर	देवरिया
384	टांडा	संजू देवी	भाजपा		278	अंबेडकरनगर	अंबेडकरनगर
385	तरबगंज	प्रेम नारायण पाण्डेय	भाजपा		299	गोंडा	कैसरगंज
386	ठाकुरद्वारा	नवाब जान	सपा		26	मुरादाबाद	मुरादाबाद
387	थाना भवन	सुरेश कुमार	भाजपा		09	शामली	कैराना
388	तिलहर	रौशन लाल वर्मा	भाजपा		133	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर
389	तिलोई	मयंकेश्वर शरण सिंह	भाजपा		178	रायबरेली	अमेठी
390	तिंदवारी	ब्रजेश कुमार प्रजापति	भाजपा		232	बांदा	हमीरपुर
391	तिरवा	कैलाश सिंह राजपूत	भाजपा		197	कन्नौज	कन्नौज
392	तुलसीपुर	कैलाश नाथ शुक्ला	भाजपा		291	बलरामपुर	श्रावस्ती
393	टूंडला	सत्यपाल सिंह बघेल	भाजपा	SC	95	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद
394	ऊंचाहार	मनोज कुमार पाण्डेय	सपा		183	रायबरेली	रायबरेली
395	उन्नाव	पंकज गुप्ता	भाजपा		165	उन्नाव	उन्नाव
396	उतरौला	शशिकांत वर्मा	भाजपा		293	बलरामपुर	गोंडा
397	वाराणसी कैंट	सौरभ श्रीवास्तव	भाजपा		390	वाराणसी	वाराणसी
398	वाराणसी उत्तर	रविन्द्र जायसवाल	भाजपा		388	वाराणसी	वाराणसी
399	वाराणसी दक्षिण	डॉ. नीलकंठ तिवारी	भाजपा		389	वाराणसी	वाराणसी
400	जफराबाद	डॉ. हरेन्द्र प्रसाद सिंह	भाजपा		371	जौनपुर	मछलीशहर
401	जहूराबाद	ओम प्रकाश राजभर	सुहेलदेव भासपा		377	गाजीपुर	बलिया
402	जैदपुर	उपेन्द्र सिंह	भाजपा	SC	269	बाराबंकी	बाराबंकी
403	जमनिया	सुनीता	भाजपा		379	गाजीपुर	गाजीपुर

श्रद्धांजलि

रवि राय का निधन समाजवादी आंदोलन के लिए बड़ी क्षति है

प्रख्यात समाजवादी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय का 6 मार्च को कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निधन हो गया. वे 90 साल के थे. राय के परिवार में उनकी पत्नी सरस्वती स्वेन हैं. उनकी कोई संतान नहीं है. रवि राय उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के जानकार थे. स्वतंत्रता सेनानी, दिग्गज समाजवादी नेता और एक ऊंचे कद के सांसद के रूप में राय ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष जैसे विभिन्न पदों पर रहते हुए देश की सेवा की. उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए बड़ी क्षति है. समाजवादी आंदोलन में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा.

रवि राय का जन्म 26 नवम्बर, 1926 को ओडीशा में भगवान जगन्नाथ की नगरी के रूप में विख्यात जिला पुरी के भानगढ़ गांव में हुआ. उन्होंने राज्य के एक उत्कृष्ट महाविद्यालय, रावेनशॉ कॉलेज, कटक से इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में कटक के मधुसूदन लॉ कॉलेज से कानून की शिक्षा ग्रहण की. उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत उस समय हुई, जब 1948-49 में रावेनशॉ कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर और उसके बाद 1949-50 में मधुसूदन लॉ कॉलेज छात्र संघ के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उनका निर्वाचन हुआ.

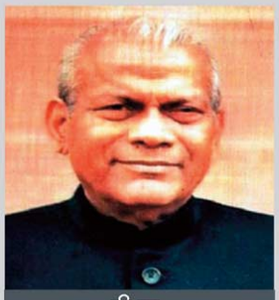

रवि राय
(26 नवम्बर 1926- 6 मार्च 2017)

रवि राय स्वतंत्रता संघर्ष में भी शामिल हुए. 1947 के प्रारम्भ में, स्नातक शिक्षा प्राप्त करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय झंडा फहराने के सिलसिले में गिरफ्तारी दी. समाजवाद में विश्वास रखने वाले रवि राय 1948 में सोशलिस्ट पार्टी में एक सदस्य के रूप में शामिल हुए. 1953-54 के दौरान वे अखिल भारतीय समाजवादी युवक सभा के संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत रहे. 1956 में उन्होंने डॉ. राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में ओडीशा में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की. इस दौरान वे सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे. बाद में, 1960 में उन्होंने लगभग एक वर्ष के लिए दल के महासचिव का कार्यभार संभाला.

रवि राय 1967 में पहली बार संसद सदस्य बने, जब ओडीशा के पुरी से चौथी लोक सभा के लिए उनका निर्वाचन हुआ. इस दौरान वे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (एस.एस.पी.) के संसदीय दल के नेता भी रहे. 1974 में ओडीशा से ही वे राज्य सभा के लिए चुने गए. प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने जनवरी, 1979 में उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की हैसियत से अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया. उन्होंने जनवरी, 1980 तक यह कार्य-भार संभाला. 1977-80 की अवधि के दौरान रवि राय जनता पार्टी के महासचिव भी रहे. नौवीं लोक सभा चुनाव में कोई भी एक राजनीतिक दल सदन में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सका. पहली बार त्रिशंकु संसद बनी. लेकिन लोक सभा के सदस्यों ने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर श्री राय को सर्वसम्मति से नौवीं लोक सभा का अध्यक्ष चुना. सादगी से भरे रवि राय ने अपने निष्पक्ष तथा विवेकपूर्ण रवैये से अध्यक्ष पद के सम्मान और गरिमा में वृद्धि की.

रवि राय का विचार था कि अध्यक्ष केवल संसद का संरक्षक ही नहीं होता, बल्कि अंतर संसदीय संबंधों को बढ़ावा देने और उसे सुदृढ़ करने में भी उसकी एक अहम भूमिका होती है. उन्होंने साथी देशों में संसदीय शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर द्विपक्षीय संबंधों को प्रोत्साहन दिया. अपने कार्यकाल के दौरान श्री राय ने विभिन्न देशों में गए संसदीय प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया. दसवीं लोक सभा के बाद रवि राय ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में वे बुद्धिजीवी मंचों में भाग लेते रहे. वे उड़िया, हिन्दी और अंग्रेजी की विभिन्न पत्रिकाओं में समकालीन राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दों पर नियमित रूप से लेख लिखते रहे. ■

वामपंथी विचार से लैस एक समाजवादी नेता को सलाम

पूर्व राजनयिक, सांसद और आज़ादी के बाद मुसलमानों के सबसे मुखर नेता सैयद शहाबुद्दीन 82 वर्ष की आयु में 4 मार्च 2017 को इस दुनिया से रुखसत हो गए. उन्हें दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन स्थित पंज पीरा कब्रिस्तान में सपुर्द-ए-खाक किया गया. उनकी अंतिम यात्रा में अन्य लोगों के साथ उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, समाजसेवी स्वामी अग्निवेश, पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे और सलमान हैदर शामिल थे.

शहाबुद्दीन का जन्म 4 नवम्बर 1935 को रांची में हुआ था. वो शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे. 1950 में उन्होंने पूरे बिहार में प्रथम स्थान हासिल किया था. उनके बारे में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, जो आज भी लोगों की याद्दाश्त में महफूज़ हैं. जैसे एक मशहूर किस्सा यह था कि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का बोर्ड की परीक्षा में रिकॉर्ड तोड़ दिया था. शहाबुद्दीन बाद की परीक्षाओं में भी प्रथम स्थान हासिल किए. बहरहाल, साइंस कॉलेज, पटना से एमएससी करने के बाद वहां के वाइस चांसलर ने उन्हें लेक्चररशिप का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया. इस दौरान उन्होंने पटना लॉ कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की और सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करते रहे. 1958 में वे पहली ही कोशिश में सिविल सर्विसेज परीक्षा में दूसरा रैंक हासिल करने में कामयाब रहे. उन्होंने अपने लिए विदेश सेवा का चुनाव किया, लेकिन पुलिस की गोपनीय रिपोर्ट में नकारात्मक टिप्पणी होने की वजह से उनकी नियुक्ति रुक गई थी. इसका कारण यह था कि उन्होंने 1955 में नवादा में हुई पुलिस फायरिंग के खिलाफ पटना में विरोध-प्रदर्शन का नेतृत्व किया था. पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में उन्हें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बताकर उक्त विरोध प्रदर्शन का हवाला दिया था. बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के बाद उन्हें विदेश सेवा में बहाल किया गया.

सैयद शहाबुद्दीन
(4 नवम्बर 1935-4 मार्च 2017)

उनका कहना था कि उनके पिता चाहते थे कि वे सिविल सेवा परीक्षा में बैठें. चयन के बाद नौकरी करने का जी करे तो करें, वरना छोड़ दें. इस दौरान उन्हें कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी से नुक्लियर फिजिक्स में स्कॉलरशिप मिल चुकी थी. यही वजह थी कि वर्ष 1978 में भारत सरकार ने समयपूर्व सेवानिवृत्ति का प्रावधान किया तो उन्होंने इसका लाभ उठाते हुए विदेश सेवा से त्यागपत्र दे दिया और तत्कालीन जनता पार्टी में शामिल हो गए. बीस साल की सर्विस के दौरान वे सेकंड सेक्रेटरी, फर्स्ट सेक्रेटरी, चार्ज डी अफेयर्स, राजदूत और विदेश मंत्रालय में दक्षिण-पूर्व एशिया, हिंद महासागर और प्रशांत के संयुक्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने खास तौर पर बांग्लादेश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वे खुद कहते थे कि जहां तक बांग्लादेश की स्थापना का सवाल है तो निश्चित रूप से मैंने इसके लिए काम किया, क्योंकि मौलाना आजाद की तरह मेरा भी मानना था कि पाकिस्तान का जादू वक़्त के साथ समाप्त हो जाएगा.

हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होने के संदेह में भारतीय विदेश सेवा में उनकी नियुक्ति रोक दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में बार-बार कहा कि उस समय वे किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं थे. बाद में उन्होंने कहा कि मैं विचार से वामपंथी हूं और मेरा विश्वास समाजवाद में है. बहरहाल 1978 में विदेश सेवा से इस्तीफा देकर वे राजनीति में आ गए और सबसे पहले सत्ताधारी जनता पार्टी के टिकट पर राज्य सभा गए. इसके बाद दो बार बिहार के किशनगंज से चुनाव जीत कर लोकसभा गए. वे जनता दल में शामिल हुए और इन्साफ पार्टी का एक नाकाम तजुर्बा भी किया. संसद में अपने कार्यकाल के बारे में उनका कहना था कि चूंकि उनका विचार वामपंथी था, इसलिए बाबरी मस्जिद और मुस्लिम पर्सनल लॉ को छोड़कर हर मामले में उनका विचार वही होता था, जो वामपंथियों का था. संसद में वे हमेशा मुसलमानों से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे. बाद की सियासी हलचल से दूर रहने के बावजूद वे 2007 से 2011 तक ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावेरत के अध्यक्ष भी रहे. वर्ष 1983 से लेकर 2002 तक एक मासिक पत्रिका मुस्लिम इंडिया का संपादन करते रहे, इस दौरान उनके लेख देशी-विदेशी अख़बारों में भी छपते रहे.

हालांकि कई मामलों को लेकर शहाबुद्दीन की आलोचना भी हुई, खास तौर पर शाह बनो मामले में उनके पक्ष को लेकर. लेकिन उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता को लेकर कोई सवाल नहीं उठा सकता था. सत्ता का लोभ उन्हें कभी नहीं रहा इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा भेजे गए मंत्री पद से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलरी तक का पद ठुकरा दिया. ऐसे समय में भी मंत्री पद की चाह नहीं की, जब वे मंत्री बन सकते थे. सैयद शहाबुद्दीन के निधन से भारत में मुस्लिम राजनीति में जो रिक्तता पैदा हुई है वह शायद ही भर सके. सैयद शहाबुद्दीन को चौथी दुनिया परिवार की तरफ से अंतिम सलाम. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

जन्मांक के हिसाब से इस सप्ताह आपका भविष्यफल

क्या कहता है आपका टैरो कार्ड

अलंकृता मानवी

लेखिका मशहूर टैरो कार्ड रीडर हैं. आप भी अगर टैरो कार्ड के ज़रिए अपना भविष्य जानना चाहते हैं, तो संपर्क करें- astro@chauthiduniya.com

जन्मांक 1: (जिनका जन्म 1, 19, 28 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह सूर्य है)

इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, सेवन ऑफ डबल वज्र. इस हफ्ते आपके भाग्य में बहुत सारा पैसा और समृद्धि है. आपके जीवन में बहुत सी अच्छी चीजें घटित हो सकती है.

जन्मांक 2: (जिनका जन्म 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह चन्द्रमा है)

इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, एस ऑफ लोटसेज. यह विश कार्ड है. इस सप्ताह आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं. आपकी आत्मा शुद्धता से भरी रहेगी.

जन्मांक 3: (जिनका जन्म 3, 12, 21, 30 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह वृहस्पति है)

इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, सिक्स ऑफ डबल वज्र. इस हफ्ते आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हो सकती हैं. रिश्तों के ख्याल से यह सप्ताह आपके लिए बेहतर है. नए संबंध भी बन सकते हैं, जो मधुर होंगे. आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा.

जन्मांक 4: (जिनका जन्म 4, 13, 22, 31 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह है यूरेनस यानी अरुण ग्रह)

इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, एट ऑफ ज्वेल कार्ड. ये कार्ड बताता है कि इस सप्ताह यदि आप कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. यह सप्ताह सफलता के लिए आपसे सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत की मांग करता है.

जन्मांक 5: (जिनका जन्म 5, 14, 23 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह बुध है)

इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, थ्री ऑफ लोटसेज. अगर आपके मन में कोई भय हो, तो इस सप्ताह उस भय को पूरी तरह से निकाल दें. साथ ही पुरानी शंका या भय को भी मन से हटा दें. यदि आप ऐसा कर पाते हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा.

जन्मांक 6: (जिनका जन्म 6, 15, 24 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह शुक्र है)

इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, फोर ऑफ ज्वेल्स. इस सप्ताह आप दान-पुण्य करें. यह सप्ताह आपसे चाहता है कि आप किसी भी वस्तु आदि को दूसरे के साथ साझा यानी शेयर करें. इससे आपको शांति और संतुष्टि मिलेगी.

जन्मांक 7: (जिनका जन्म 7, 16, 25 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह वरुण है).

इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, डेथ कार्ड. हालांकि, आपको इस कार्ड से घबराने की जरूरत नहीं है. यह सिर्फ इतना बताता है कि आपके जीवन से पुरानी चीजें खत्म हो जाएंगी और एक नए की शुरुआत होगी.

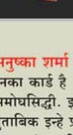

जन्मांक 8: (जिनका जन्म 8, 17, 26 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह शनि है)

इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, द बुद्धा ऑफ लोटसेज. इस सप्ताह आपके जीवन में स्थिरता रहेगी, सुरक्षा मिलेगी और साथ ही शांति और शुद्धता का एहसास करेंगे.

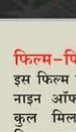

जन्मांक 9: (जिनका जन्म 9, 18, 27 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह मंगल है)

इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, माया-द मदर कार्ड. इस सप्ताह आपको बहुत अधिक प्यार और केयर मिलने वाला है. इस सप्ताह भाग्य भी आपका बहुत अधिक साथ देगा. आपको नाम और ख्याति भी मिल सकती है.

सेलीब्रिटी टैरो कार्ड

इस हफ्ते अनुष्का शर्मा की फिल्म फिल्लौरी आ रही है. आइए, जानते हैं कि टैरो कार्ड के हिसाब से इन दोनों और फिल्म का भविष्य क्या होगा?

अनुष्का शर्मा

इनका कार्ड है अमोघसिद्धी. इसके मुताबिक इन्हे प्रोटेक्शन (सुरक्षा/ आशीर्वाद) लेने की जरूरत होगी, ताकि इनकी मूवी अच्छा प्रदर्शन कर सके.

फिल्म-फिल्लौरी

इस फिल्म का कार्ड है, नाइन ऑफ लोटसेज. कुल मिला कर ये फिल्म उतना अच्छा परिणाम नहीं देगी, जितनी मेहनत इसके लिए की गई है.

टीम इंडिया ने दिखाया दम

फिरकी की फांस में फंसी कंगारू टीम

दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 75 रनों की करारी शिकस्त दी

दूसरी पारी में अश्विन की घातक गेंदबाजी

सैयद मोहम्मद अब्बास

भारतीय टीम ने कंगारुओं के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार वापसी करते हुए सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. बेंगलुरु में खेले गए एक नाटकीय टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे दिन ही तीसरे सेशन में 75 रनों की करारी शिकस्त देते हुए चार मैचों की टेस्ट श्रृंखला में एक नया रोमांच पैदा कर दिया है. अभी कुछ दिन पहले पुणे टेस्ट में मिली हार के बाद आलोचकों ने भले ही टीम इंडिया पर सवाल खड़े किए हों, लेकिन इस जीत से आलोचकों को करारा जवाब मिल गया है. भारत की सरजमीं पर विदेशी टीम अक्सर स्पिन पर नाचती दिखती है. पुणे टेस्ट में भले ही टीम इंडिया अपने जाल में फंस गई हो, लेकिन बेंगलुरु में वही दांव चल गया. पहली पारी में टीम इंडिया सस्ते में निपट गई तो लगा कि यहां भी कंगारू अपनी जीत का डंका बजाएंगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कंगारुओं को सबक सिखा दिया. पहली पारी में जहां तेज गेंदबाजों में उमेश यादव की खतरनाक स्पीड और गजब की स्विंग के आगे कंगारुओं के बल्लेबाज बेबस दिखे, वहीं जडेजा की फिरकी के आगे भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे. दूसरी पारी में जहां पुजारा और रहाणे बल्लेबाजी में चमके तो अश्विन ने एक बार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की दूसरी पारी में कमर तोड़ दी. इस जीत में लोकेश राहुल का भी खास योगदान रहा. लोकेश ने दोनों पारियों में अर्धशतक जमाया. उनकी इस पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया.

ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट जीतकर बुलंद हौसले के साथ दूसरे टेस्ट में उतरा. उसका सबूत टेस्ट के पहले दिन देखने को मिला. भारतीय टीम की पहली पारी एक बार फिर सस्ते में निपट गई. कंगारू टीम के सबसे अनुभवी ऑफ स्पिनर नाथन लियोन की फिरकी के आगे टीम इंडिया के कई धाकड़ बल्लेबाजों ने सस्ते में अपने विकेट गंवा दिए. मुरली विजय की गैरमौजूदगी में अभिनव मुकुंद को शामिल किया गया था लेकिन उनका बल्ला खाता भी नहीं खोल सका. पुजारा और विराट कोहली इस पारी में कोई करिश्मा नहीं दिखा सके, जबकि रहाणे ने एक बार फिर निराश किया. लोकेश राहुल ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 90 रन की अच्छी पारी खेली. लोकेश राहुल की इस पारी के सहारे टीम इंडिया किसी तरह से 189 रन बना सकी. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाथन लियोन ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए आठ विकेट चटकाए और टीम इंडिया के बल्लेबाजों के होश उठा दिए. पहली पारी में कम स्कोर पर आउट होने से टीम इंडिया केगेंदबाजों पर दबाव बढ़ गया. तेज गेंदबाजों ने जोरदार गेंदबाजी की, लेकिन अश्विन नहीं चले. अब सारा दबाव जडेजा पर था. जडेजा ने अपनी मारक गेंदबाजी की बदौलत मेहमान टीम को भारी बढ़त से रोक दिया. कंगारुओं ने पहली पारी में 274 रन बनाकर पहली पारी में 87 रन की मामूली बढ़त हासिल कर ली. जडेजा ने छह विकेट चटकाए. दूसरी पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर अच्छे प्रदर्शन का दारोमदार था. लोकेश राहुल ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 51 रन का योगदान दिया, जबकि दूसरे ओपनर मुकुंद फिर सस्ते में चलते बने. पुजारा ने पारी संभालते हुए विराट के साथ टीम को मजबूती दी, लेकिन विराट का बल्ला एक बार फिर रन बनाने में नाकाम रहा. इसके बाद जडेजा को बल्लेबाजी क्रम में आगे भेजा, लेकिन यह दांव चल नहीं सका और जडेजा दो रन के स्कोर पर आउट हो गए. इसके बाद पुजारा का साथ देने रहाणे क्रीज पर आए. पिछली कई पारियों से रन बनाने के लिए तरस रहे रहाणे ने यहां दूसरी पारी में संभल कर बल्लेबाजी करते हुए 51 रन जड़े, जबकि पुजारा के बल्ले से 92 रन का योगदान मिला. जानकारों की मानें तो पुजारा का यह स्कोर किसी शतक से कम नहीं है. रहाणे और पुजारा के आउट होने के बाद टीम इंडिया की बल्लेबाजी फिर लड़खड़ा गई. भारत केपांच विकेट 20 रन पर गिर गए, लेकिन टीम इंडिया सीरीज में पहली बार 274 रन बनाने में कामयाब रही. इस तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम को 188 रन की चुनौती मिली. इस टेस्ट मैच में पल-पल रोमांच बढ़ता रहा. जहां मैच के चौथे दिन कंगारुओं ने पहले दो सेशन अपने नाम किए, वहीं चौथे सेशन में अश्विन की कहर बरपाती हुई गेंदों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के इरादों पर पानी फेर दिया. अश्विन की घूमती हुई गेंदों के कारण मेहमान टीम का चौथे दिन पिच पर टिकना मुश्किल हो रहा था. आलम यह रहा कि कंगारू टीम को 35.4 ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने 112 रन के स्कोर पर रोक दिया. इस तरह से टीम इंडिया ने 75 रन से मैच जीत लिया. आर अश्विन पहली पारी में उतने असरदार नहीं दिखे लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने लय हासिल करते हुए छह विकेट लेकर मेहमान टीम को गहरा झटका दिया. चौथे दिन पिच एकदम खराब दिखी. पिच पर गेंद स्पिन तो हो रही थी, साथ ही असमान उछाल भी देखने को मिला. चौथे दिन कुल 16 विकेट गिरे. कुल मिलाकर टीम इंडिया ने इस टेस्ट में किसी तरह जीत तो हासिल कर ली, लेकिन बल्लेबाजी में अभी काफी सुधार की जरूरत है. ओपनिंग बल्लेबाजी अब भी टीम इंडिया की बड़ी समस्या है. दूसरी ओर मध्यक्रम भी उतना चल नहीं रहा, खासकर कोहली का बल्ला अभी शांत नजर आ रहा है. अगर भारत को सीरीज जीतनी है तो विराट कोहली और रहाणे जैसे खिलाड़ियों को बड़ी पारी खेलनी होगी. ■

बाद में संभल गए रहाणे

मौजूदा सीरीज में टीम इंडिया के चोटी बल्लेबाज रहाणे की फॉर्म को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में उनके बल्ले ने चुप्पी तोड़ते हुए अर्धशतक जमाया. कुछ महीनों पूर्व टीम इंडिया जीत के रथ पर सवार थी, लेकिन कंगारुओं के पहले टेस्ट में जोरदार खेल के आगे विराट की टीम में अचानक कई खामियां नजर आने लगी हैं. यह बात भी सत्य है कि टीम जब तक जीतती है तब तक उसके ऐब किसी को नहीं दिखते हैं, लेकिन जहां हार मिली वहां सब उसकी आलोचना करने के लिए मोर्चा खोल देते हैं. दरअसल टीम इंडिया की दोनों टेस्ट में बल्लेबाजी खराब रही है. गेंदबाजों के सहारे टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट में जीत हासिल कर ली. टीम इंडिया की बल्लेबाजी की सबसे अहम कड़ी माने जाने वाले रहाणे इस समय अपनी जगह बचाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं. उनका खामोश बल्ला आलोचकों के लिए नया हथियार साबित हो रहा है. हाल के दिनों में रहाणे का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है. जानकारों की मानें तो रहाणे की काबिलियत पर किसी को शक नहीं है, लेकिन उनकी खराब फॉर्म टीम इंडिया पर भारी पड़ती दिख रही है. दूसरे टेस्ट की पहली पारी में रहाणे एक बार रन बनाने से चूक गए, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने पुजारा का अच्छा साथ देते हुए 52 रन की अहम पारी खेली. उनकी इस पारी से टीम इंडिया को बड़ी राहत मिली.

रहाणे भारत के सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनका बल्ला खामोश रहा है. इसके बाद वे पहले ही टी-20 और वन डे में अपनी जगह बचाने में कामयाब नहीं रहे हैं. हालांकि टी-20 टीम में उनकी जगह बनती नहीं दिख रही है, वहीं वन डे में वे 15 सदस्यीय दल में शामिल होते हैं, लेकिन अंतिम ग्यारह में उनको जगह नहीं मिलती है. टेस्ट में वे बेस्ट माने जाते हैं. सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ व वीवीएस लक्ष्मण के संन्यास के बाद मध्य क्रम को मजबूत करने का जिम्मा रहाणे जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी पर रहा है. मौजूदा समय में उनका बल्ला काफी समय से खामोश रहा है. उनकी खराब फिटनेस भी उनके खेल को प्रभावित कर रही है. बेंगलुरु टेस्ट से पूर्व अंतिम पांच पारियों में रहाणे केवल 204 रन ही बना सके हैं. उनके प्लॉप शो के चलते टीम के कई प्रतिभावान खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ा है. ऐसा नहीं है कि रहाणे को मौका नहीं दिया जा रहा है. कोच और कप्तान का भरोसा अब भी रहाणे पर कायम है. दूसरी ओर करुण नायर जैसे खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के बावजूद टीम में स्थान को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है. क्रिकेट के कई जानकारों का मानना है कि रहाणे बड़े मैच केबड़े खिलाड़ी हैं. आईपीएल में अपने बल्ले का लोहा मनवाने के बाद रहाणे को टीम इंडिया का बुलावा आया. वन डे में उनका प्रदर्शन ठीक-ठाक कहा जा सकता है. उन्होंने 73 वन डे में 32.42 की औसत से 2837 रन बनाए हैं, लेकिन टेस्ट में रहाणे अपने बल्ले का जौहर दिखाने में कामयाब रहे हैं. बेंगलुरु टेस्ट से पूर्व 34 टेस्ट मैचों में उन्होंने 46.40 की औसत से 4530 रन बनाए हैं. इस दौरान रहाणे ने आठ शतक भी जड़े हैं. सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि टीम इंडिया जब भी मुश्किलों में दिखी उन्होंने अपने मजबूत खेल से टीम इंडिया को बाहर निकाल लिया. कोच कुंबले भी रहाणे केइसी प्रदर्शन की दुहाई देते नजर आ रहे हैं. यह भी इत्तेफाक है कि जिस टीम के खिलाफ डेब्यू किया था उसी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वे रनों के लिए तरस रहे हैं. 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहाणे ने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की थी. शिखर धवन के चोटिल होने के बाद उन्हें टीम में मौका मिला था. रहाणे उस मौके का कोई खास फायदा नहीं उठा सके. उन्होंने पहली पारी में सात और दूसरी पारी में एक रन का योगदान दिया. इस नाकामी के बावजूद कप्तान का उनपर भरोसा कायम रहा. इसके बाद रहाणे ने दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अपने बल्ले का हुनर दिखाया. उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी पिच पर अपने बल्ले का करिश्माई खेल दिखाया. यहां से लगा कि रहाणे टेस्ट क्रिकेट के लिए फिट हैं. यह वही दौर था जब टीम इंडिया मध्यक्रम को मजबूत करने में जुटी थी क्योंकि कई बड़े खिलाड़ी संन्यास ले चुके थे. दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रहाणे ने भले ही शतक नहीं जमाया हो, लेकिन अपने मजबूत खेल से भविष्य की आस को परवान चढ़ा दिया. इसके बाद न्यूजीलैंड दौरे पर खराब हालात में शतक जड़कर उन्होंने अपने चयन को सही भी साबित किया. माना जाता है कि यहां से वे मध्यक्रम के अहम खिलाड़ी बनकर सामने आए. बल्लेबाजी के दौरान मैदान पर लड़ने की गजब क्षमता रखने वाले रहाणे ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर शतक लगातार सबको अपनी बल्लेबाजी का मुरीद बना लिया. इसके बाद रहाणे विदेशी पिचों पर अपने बल्ले की हनक दिखाने में माहिर नजर आए. ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर रहाणे ने अपनी बल्लेबाजी का दम-खम दिखाया. इतना ही नहीं, भारतीय पिचों पर उनका बल्ला रनों का अम्बार लगाने में माहिर दिखा लेकिन क्रिकेट में फॉर्म कभी-कभी धोखा दे जाती है. रहाणे ने दूसरे टेस्ट में अर्धशतक लगाकर फॉर्म में आने के संकेत दिये हैं. क्रिकेट करियर में हर खिलाड़ी की फॉर्म एक जैसी नहीं रहती है, लेकिन रहाणे की खराब फॉर्म टीम इंडिया केप्रदर्शन को काफी प्रभावित कर रही है. अगर भारत को बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो रहाणे को बड़ी पारी खेलनी होगी. ■

महिला क्रिकेट में सचिन हैं मिताली राज

विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया लगातार इतिहास बना रही है. कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने नम्बर वन का तमगा हासिल किया है. हाल में भारतीय टीम का प्रदर्शन काबिलेतारीफ रहा है, लेकिन कंगारुओं के खिलाफ शुरुआती टेस्ट मैचों में कमजोर प्रदर्शन किया है. जहां एक ओर भारतीय टीम कंगारुओं से लोहा ले रही है, वहीं महिला क्रिकेट भी चमकदार प्रदर्शन कर रही है. जिस तरह से विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया दुनिया की हर टीम केलिए खतरा बन रही है, ठीक उसी तरह मिताली राज की अगुआई में महिला क्रिकेट लगातार जीत का डंका बजा रही है. हाल में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को पराजित कर महिला विश्व कप के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर खिताब पर भी कब्जा कर लिया. भारत में अगर क्रिकेट की बात होती है तो केवल पुरुष खिलाड़ियों की ही चर्चा होती है. देश में सचिन को रिकॉर्ड पुरुष कहा जाता है, जबकि विराट कोहली को सचिन से भी बड़ा खिलाड़ी माना जाने लगा है. हिन्दुस्तान में महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन की चर्चा नहीं के बराबर होती है, जबकि सच्चाई यह है कि महिला क्रिकेट में भी कई खिलाड़ी अपने प्रदर्शन की बदौलत सचिन और विराट जैसे क्रिकेटरों की तरह आगे आने का हौसला दिखा रही हैं. भारतीय महिला क्रिकेट भी लगातार अपने प्रदर्शन की बदौलत चर्चा में है. हाल में महिला टीम ने विश्व क्रिकेट क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में शानदार क्रिकेट खेला. मिताली की कप्तानी में टीम इंडिया ने इस साल जून में होने वाले महिला विश्व कप के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है. महिला टीम को इस मुकाम तक पहुंचाने में मिताली राज का सबसे अहम योगदान रहा है. मिताली का न केवल बल्लेबाजी, बल्कि कप्तानी में भी कोई सानी नहीं है. हाल के दिनों में महिला क्रिकेट टीम भी खूब सुर्खियों में बनी हुई है. महिला क्रिकेट रैंकिंग में भी भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिल रहा है. महिला टीम की कप्तान मिताली राज रैंकिंग में नम्बर दो पर काबिज हैं, जबकि हरमनप्रीत कौर को दसवां स्थान मिला है. एक वक्त था, जब महिला खिलाड़ियों में अंजुम चोपड़ा और झूलन गोस्वामी का नाम चर्चा में रहता था, लेकिन अब विश्व क्रिकेट में मिताली राज के बल्ले की दहाड़ सुनाई दे रही है. उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद विशेषज्ञ उन्हें महिला क्रिकेट का सचिन बता रहे हैं.

मिताली में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. उनका बल्ला जब भी बोलता है तब विरोधियों के हौसले पस्त होने में देर नहीं लगती है. वन डे क्रिकेट से लेकर टेस्ट क्रिकेट में मिताली का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक जमाकर सबको अपनी बल्लेबाजी का मुरीद बना दिया. हैदराबाद से कई पुरुष खिलाड़ियों ने भारतीय टीम में अपना नाम रौशन किया है, लेकिन महिला क्रिकेट में मिताली राज की हनक देखी जा सकती है. यह भी एक इत्तेफाक है कि महज दस साल की आयु में क्रिकेट का बल्ला थामने वाली मिताली 17 साल में भारतीय टीम में जगह बनाने में कामयाब रही. राष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ने के बाद 1999 में उन्हें पहली बार भारतीय टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला. आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू मैच में मिताली ने धमाकेदार 114 रन बनाकर टीम इंडिया में अपनी जगह को और मजबूत किया. इसके बाद मिताली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बहुत जल्द भारतीय टीम की कमान भी संभाल ली. महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी की अहम कड़ी बन चुकीं मिताली बतौर कप्तान भी अपनी अलग छाप छोड़ रही हैं. इंग्लैंड के खिलाफ 2002 में टेस्ट मैच में मिताली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 214 रन की पारी खेलकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया. मिताली की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2006 में इंग्लैंड की धरती पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में 1-0 से पराजित कर टीम इंडिया का मान बढ़ाया. इतना ही नहीं, हाल में विश्व कप क्वालिफाइंग मैचों में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया. मिताली की कप्तानी में टीम इंडिया ने लगातार 13 वन डे जीतने का नया इतिहास बनाया है. इसके साथ ही उनका बल्ला भी इस समय खूब बोल रहा है. मिताली के वन डे करियर पर नजर डालें तो इतना साफ है कि वह भारत की सबसे प्रतिभाशाली क्रिकेटरों में से एक हैं. उन्होंने अब तक 172 वन डे में 51.3 के बेजोड़ औसत से 5614 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने पांच शतक के साथ-साथ 43 अर्धशतक भी जड़ा है, जबकि दस टेस्ट मैचों में 51 की औसत से 663 रन बनाए हैं. इस दौरान वे एक शतक और चार पचासा जमाने में कामयाब रही हैं. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने दो-दो बार एशिया कप भी जीता. 2013 में अपने शानदार खेल के लिए वे महिला क्रिकेट में शीर्ष पर पहुंच गईं. कुल मिलाकर देखा जाए तो महिला क्रिकेट के लिए यह बहुत अच्छी बात है कि उनकी कप्तानी में टीम इंडिया अब दुनिया की दूसरी टीमों को हराने का दम-खम रखती है. अब यह देखना रोचक होगा कि विश्व कप में टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है. ■

मिताली में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. उनका बल्ला जब भी बोलता है तब विरोधियों के हौसले पस्त होने में देर नहीं लगती है. वन डे क्रिकेट से लेकर टेस्ट क्रिकेट में मिताली का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक जमाकर सबको अपनी बल्लेबाजी का मुरीद बना दिया. हैदराबाद से कई पुरुष खिलाड़ियों ने भारतीय टीम में अपना नाम रौशन किया है, लेकिन महिला क्रिकेट में मिताली राज की हनक देखी जा सकती है. यह भी एक इत्तेफाक है कि महज दस साल की आयु में क्रिकेट का बल्ला थामने वाली मिताली 17 साल में भारतीय टीम में जगह बनाने में कामयाब रही. राष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ने के बाद 1999 में उन्हें पहली बार भारतीय टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला.

feedback@chauthiduniya.com

संजय दत्त

संजय दत्त की शख्सियत को देख ऐसा लगता है कि यह बंदा तो बना ही एक्शन फिल्मों के लिए है. एक्शन दृश्यों को वे अच्छी तरह से निभाते हैं. उनकी बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट लगती है. हाथ में पिस्तौल लिए जब वे निशाना लगाते हैं तो उनकी आंखों की चमक देखने लायक होती है. गैंगस्टर का रोल हो तो लगता ही नहीं कि संजू बाबा अभिनय कर रहे हैं. संजय के एक्शन में एक स्टाइल है जो उन्हें दूसरे एक्शन स्टार्स से जुदा करता है. वैसे भी अपने संजू बाबा 50 तोले से खुश होने वालों में से नहीं हैं इसलिए उन्होंने अपने लंबे करियर में ज्यादातर एक्शन फिल्में ही की हैं. संजू बाबा की मुख्य एक्शन फिल्में रॉकी, इनाम दस हजार, जान की बाज़ी, ख़तरों के खिलाड़ी, हथियार, ख़तरनाक, क्रोध, थानेदार, वलगार, ख़लनायक, कांटे, मुसाफिर, ज़िंदा, वास्तव, सड़क, ताकतवर, थानेदार, महानता, आंदोलन, दाग द फायर और अग्निपथ रही हैं.■

ये हैं बॉलीवुड के एक्शन हीरो

प्रवीण कुमार

बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों की शुरुआत काफी पहले हो चुकी है और यह हमेशा से चलता आया है. बताया जाता है कि शुरुआती दौर में एक्शन फिल्में कम ही बनती थी और जो बनती थी तो उन्हें दर्शक अच्छी फिल्म नहीं मानते थे. इन फिल्मों को सी ग्रेड की फिल्में कहा जाता था.

लेकिन एक दौर वह भी आया जब एक्शन फिल्मों ने सभी को पछाड़ कर बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए रखा. जी हां, 70 के दशक में एक्शन फिल्मों का सिलसिला ऐसा चला कि उसका जादू आज भी कायम है. पहले की फिल्मों में निर्माता-निर्देशक बिना कारण फाइट सीन ठूंस देते थे. फिर एक समय ऐसा भी आया जब दर्शक इन चीजों से उबने लगे. इसके बाद एक्शन फिल्मों में बदलाव देखने को मिला. धीरे-धीरे एक्शन कम हुआ और फिल्मों की स्टोरी पर ध्यान दिया जाने लगा, ताकि एक्शन जस्टिफाई हो सके. बीते जमाने में जहां अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, जितेंद्र, धर्मेंद्र, दारा सिंह, सन्नी देओल, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, गोविंदा, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, सुनील शेट्टी आदि अभिनेताओं ने अपने एक्शन से लंबे समय तक दर्शकों के दिलों पर राज किया.

वहीं आज के दौर में अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहिम जैसे सितारे अपने एक्शन से दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं. आइए जानते हैं किस अभिनेता ने किन फिल्मों के जरिए अपनी एक्शन छवि बनाई है जिसके चलते इनकी इमेज एक एक्शन हीरो के रूप में बनी और इनमें से टॉप एक्शन हीरो कौन है, ये फैसला आप खुद कीजिए.■

अजय देवगन

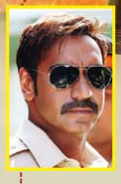

सांवले चेहरे के साथ जब 1991 में फूल और कांटे से अजय देवगन ने अपना करियर शुरू किया तब एक्शन फिल्मों का बोलबाला था. उस समय बॉलीवुड में अजय के पिता वीरू देवगन जाने माने एक्शन कोरियोग्राफर थे. आगे चलकर अजय देवगन को पिता की ओर से यह सबसे बड़ा फायदा मिला और फिल्म फूल और कांटे में अजय ने दमदार एक्शन करते हुए बॉलीवुड में एक्शन का स्टाइल ही बदल दिया. दो बाइक पर अपने पैर खोलकर कॉलेज में एंट्री देना, ऐसा पहले किसी ने नहीं किया था. हवा में उड़कर किक करना, बंदूक को नए सिरे से अलग-अलग स्टाइल में चलाना, बाइक को हवा में उड़ाना या फिर ट्रक के नीचे से निकालना, यह सब अजय के लिए मामूली सी बात थी.

अजय की एक ख़ास बात और थी कि वह जितना अच्छा एक्शन कर लेते थे, उनका अभिनय उससे भी बेहतर था. अभिनय हो या एक्शन वे कुछ भी करते हैं तो उनकी आंखें उनसे ज्यादा बोलती हैं.

अजय की एक्शन फिल्मों की लिस्ट भी अच्छी ख़ासी है, जिनमें फूल और कांटे, जिगर, विजयपथ, सुहाग, नाज़ायज़, हलचल, तक्षक, कंपनी, जान, दिलजले, दिलवाले, गुंडाराज, हकीकत, एक्शन जैक्सन, ख़ाकी, क़यामत, कच्चे धागे, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, सिंघम, सिंघम रिटर्न्स और शिवाय फिल्में प्रमुख हैं.■

अमिताभ बच्चन

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सभी पर भारी हैं. शायद ही इस देश में कोई ऐसा हो जो अमिताभ बच्चन को नहीं जानता हो. बिग बी के फैंस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े पैमाने पर हैं. अमिताभ के अभिनय के क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी दीवाने हैं. अमिताभ बच्चन अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में सफल नहीं रहे. लेकिन साल 1973 में आई फिल्म जंजीर से वे रातों रात स्टार बन गए. फिल्म में अच्छी स्क्रिप्ट, शानदार डायलॉग डिलीवरी और एक्शन ने अमिताभ को वह पहचान दिलाई जिसके वे काबिल थे. जंजीर के बाद अमिताभ ने शोले, दीवार, अमर अकबर अंथोनी, अग्निपथ, त्रिशूल, कुली, डॉन, शहंशाह, सुहाग, मर्द, कालिया, राम बलराम आदि सुपरहिट फिल्मों में एक्शन किया. अमिताभ बच्चन आज भी बॉलीवुड में सक्रिय हैं और नंबर वन अभिनेता बने हैं.■

धर्मेन्द्र

ड्रैशिंग धर्मेन्द्र सही मायने में भारत के पहले एक्शन हीरो कहे जा सकते हैं. चेहरा और कद काठी ऐसी कि उन्हें देख हसीनाओं का दिल धड़कता था और जब वे बाजू फड़काते तो गुंडों का दम निकलता था. फिल्म फूल और पत्थर में उन्होंने शर्टलेस होकर हंगामा मचा दिया था. गरम धरम का रिएक्शन दर्शकों को काफी पसंद आया. कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा दहाड़ते हुए जब वे गुंडों के पीछे भागते तो सभी की शामत आ जाती थी. एक्शन फिल्मों में इस देसी ही-मैन का जवाब नहीं.

वैसे तो धर्मेन्द्र ने अपने करियर में ख़ूब फिल्में कीं लेकिन कीमत, जुगनू, चरस, शोले, प्रतिज्ञा, आज़ाद, शालीमार, क्रोधी, लोहा, हुकूमत, ऐलान-ए-जंग, जलजला, बगावत, बदले की आग, धरमवीर, राम बलराम, गुलामी, वादों की बारात, लोहा, फरिश्ते, तहलका, हक़ीक़त जैसी फिल्में उनकी मुख्य एक्शन फिल्में थीं.■

अक्षय कुमार

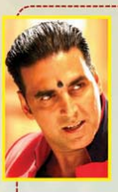

कोई संदेह नहीं है कि अक्षय कुमार एक्शन में अच्छे ख़ासे जमते हैं. नए स्टंट्स करना उन्हें पसंद है. वे फुर्तीले हैं. वे अपने स्टंट्स खुद करते हैं जिससे सीन असल दिखते हैं. फिल्म *खिलाड़ी* सीरिज के रूप में उन्होंने कई एक्शन मूवी की, जो दर्शकों को बहुत पसंद आई. इसलिए उन्हें बॉलीवुड का सबसे बड़ा खिलाड़ी भी कहा जाता है. अक्षय कभी हेलिकॉप्टर से लटके, तो कभी डेढ़ सौ किलो के पहलवान को रिंग में धूल चटा दी. मार्शल आर्ट्स में पारंगत होना एक्शन फिल्मों में अक्षय के बहुत काम आया. वे एक्शन सीन करते हुए कई बार बाल-बाल बचे भी हैं.

अक्षय की एक्शन फिल्मों में खिलाड़ी, वे वक्त हमारा है, मोहरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, संघर्ष, इंटरनेशनल खिलाड़ी, खिलाड़ी 420, सबसे बड़ा खिलाड़ी, सुहाग, सैनिक, जानवर, ये वक्त हमारा है, हॉलिडे, खिलाड़ी 786, सिंग इज किंग, बेबी, राउडी राठौड़, गब्बर इज बैक और रुस्तम जैसी फिल्में उनके करियर में शामिल हैं. ■

मिथुन चक्रवर्ती

मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों का नाम ही एक्शन से भरा होता था. कराटे चैंपियन मिथुन अपने स्टाइल में गुंडों को ठिकाने लगाते थे. एक दौर ऐसा भी था जब हर हफ्ते मिथुन की फिल्म प्रदर्शित होती और ज्यादातर सफल भी रहती. एक समय ऐसा भी था जब मिथुन की इमेज एक डांसर के रूप में बन चुकी थी. उस समय फिल्म इंडस्ट्री में मिथुन जैसा डांसर कोई नहीं था. लेकिन समय के साथ-साथ मिथुन ने अपनी इमेज बदलते रहने में ही भलाई समझी और देखते ही देखते वे एक्शन हीरो की भूमिका में ज्यादा नज़र आने लगे.

उन्होंने अपने करियर में चांडाल, गुंडा, जल्लाद, अंगारा, वारदात, सुरक्षा, साहस, शपथ, हम से ना टकराना, प्रतिज्ञाबद्ध, चीता, रोटी की कीमत, युगांधर, कृष्ण अवतार, मुहत, कसम पैदा करने वाले की, प्यार का देवता, फूल और अंगारे, दलाल, गुलामी, यमराज, मुजरिम आदि जैसी धुआंधार एक्शन फिल्में दीं.■

सनी देओल

बॉलीवुड में अगर सबसे भारी हाथ है तो वह सिर्फ अपने पंजाबी मुंडे सनी पाजी का है, वह भी ढाई किलो का. जो एक बार किसी पर पड़ जाए तो उठता नहीं, उठ जाता है. सनी देओल भी अपने पापा धर्मेंद्र की तरह ही एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. जब वे सिंह की तरह दहाड़ते हैं तो सिनेमाहॉल में सन्नाटा छा जाता है. गदर में वे अकेले पूरी पाकिस्तानी फ़ौज को पछाड़ देते हैं. हैंडपम्प उखाड़ देते हैं. ये सनी का ही कमाल था कि उन्होंने इस अकल्पनीय बात को विश्वसनीय बना दिया. सनी ने हीरो के रूप में लंबी पारी खेली और धमाकेदार एक्शन से हर बार विलेन को उठा-उठाकर ख़ूब पटका है.

सनी की मुख्य एक्शन फिल्में अर्जुन, घायल, घातक, सल्तनत, डकैत, यतीम, त्रिदेव, विश्वात्मा, नरसिम्हा, जिद्दी, गदर, इंडियन, जीत, दामिनी, बॉर्डर, अर्जुन पंडित, अंगरक्षक, नरसिम्हा, जोर, क्रोध, सिंह साहब द ग्रेट, कहर, योद्धा और इंतिहान रहीं.■

सलमान खान

सलमान खान को रोमांटिक और एक्शन दोनों तरह की फिल्मों में पसंद किया गया. लेकिन धीरे-धीरे सलमान ने अपनी इमेज बदलनी शुरू की और एक्शन फिल्मों में काम करना पसंद किया. इस बीच सलमान बाग़ी, करण अर्जुन, जीत, औज़ार, बंधन जैसी एक्शन फिल्में भी करते रहे. बीच में एक दौर ऐसा भी आया जब लगा कि सलमान के करियर का बल्ब फ्यूज होने वाला है, लेकिन एक्शन फिल्मों के करंट ने उन्हें संभाल लिया. जी हां, साल 2009 में जब बॉलीवुड का ये सितारा वांटेड हुआ तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि सलमान सितारों की रेस में इतनी तेजी से आगे निकल जाएंगे कि कोई उनके आस पास भी नहीं टिक सकेगा. उन्होंने लगातार 10 ऐसी फिल्में दीं हैं, जो 100 करोड़ से ज्यादा का व्यापार कर चुकी हैं. वे आज के समय में शिखर पर हैं. सलमान की एक्शन फिल्मों में बाग़ी, करण अर्जुन, औज़ार, तुमको ना भूल पाएंगे, बंधन, जुड़वा, वीरगति, तेरे नाम, गर्व, वांटेड, दबंग, दबंग-2 बॉडीगार्ड, रेडडी, एक था टाइगर, जय हो, किक आदि फिल्में शामिल हैं. ■

शाहरुख खान

बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर रोमांटिक सुपरस्टार अगर कोई हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान ही हैं. रोमांस के मामले में बॉलीवुड में उनके जैसा ना कोई है और ना ही शायद कोई होगा.

शाहरुख ने अपने फिल्मी करियर में लगभग सभी किरदार निभाए हैं. फिर वह चाहे हीरो का हो या विलेन का, रोमांस हो या गंभीर किरदार, वह सभी में एकदम फिट बैठते हैं. उनके फैंस उनको रोमांस के अलावा एक्शन में भी देखना काफी पसंद करते हैं. कई फिल्मों में उनकी मौत पर दर्शक सिनेमाघर से रोते हुए भी बाहर आते हैं, जो उनको अच्छा नहीं लगता. शाहरुख ने अपने करियर के दौरान बहुत सी एक्शन फिल्में की हैं, जिनमें बाज़ीगर, डर, अंजाम, रामजाने, डुप्लीकेट, कोयला, करण-अर्जुन, दीवाना, डॉन, डॉन-2, रॉ-वन, मैं हूं ना, दिलवाले, फैन और रईस शामिल हैं. ■

अनिल कपूर

बॉलीवुड का झकास और बिंदास अभिनेता अनिल कपूर जिन्होंने बड़े से बड़े अभिनेता को कड़ी टक्कर दी है. फिर वह चाहे कॉमेडी हो, एक्शन हो, फैमिली ड्रामा फिल्म हो या फिर किसी भी तरह का गंभीर किरदार, अनिल इन सबको बखूबी करते हैं और दर्शक उनके हर किरदार के कायल हैं. उनका जादू आज भी लोगों पर सिर चढ़कर बोलता है. सिल्वर स्क्रिन पर जब वे इमोशनल सीन या एक्शन करते हैं तो सिनेमाघर में दर्शक सीटी बजाए बिना रह नहीं सकते. अनिल कपूर ने अपने करियर में काफी फिल्में की हैं, जिनमें एक्शन फिल्मों की भी अच्छी ख़ासी भरमार है.

उनकी एक्शन फिल्मों में मिस्टर इंडिया, तेजाब, मेरी जंग, परिंदा, राम लखन, लाडला, किशन कन्हैया, कर्मा, पुकार, बुलंदी, जंगबाज़, युद्ध, जीवन एक संघर्ष, लोफर आदि जैसी फिल्में शामिल हैं.■

ऋतिक रोशन

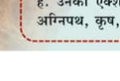

करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन और बच्चों के सुपरहीरो कृष यानी ऋतिक रोशन, ने अपनी पहली ही फिल्म कहो ना प्यार से बॉलीवुड में शानदार एंट्री की और सभी नामी अभिनेताओं पर भारी पड़े. डांस में कोई भी बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक के आस पास भी नहीं टिकता और जब एक्शन करते हैं तो सबकी बोलती बंद कर देते हैं. ऋतिक ने अपने करियर में ज्यादा एक्शन फिल्में नहीं की हैं, पर जितनी भी की हैं काबिले तारीफ हैं. उनकी एक्शन फिल्मों में कहो ना प्यार है, मिशन कश्मीर, धूम-2, अग्निपथ, कृष, कृष-3, बैंग-बैंग और काबिल शामिल हैं.■